HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 01-15 सितम्बर, 2019

द रीव टाइम्स
The RIEV Times

हिमाचल
वर्ष 2/ अंक 28/ पृष्ठ: 16
मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

'मुट्ठी में कर लो आसमान-दिल से सेवा दिल से भुगतान' : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

उद्यमिता के क्षेत्र में मिशन रीव बना सहारा
स्वरोजगार व व्यवसाय शुरु करने में रीव की बड़ी पहल
प्रशिक्षण के बाद किसी भी प्रकार के व्यवसाय में करेगा सहयोग

द रीव टाइम्सः हेमराज चौहान

"मिशन रीव ने उद्यमिता के क्षेत्र में एक बड़ी पहल करते हुए बेरोजगार युवाओं को उद्यमी बनाने और प्रशिक्षण से लेकर लोन सुविधा तक सराहनीय पहल की है। उद्यमिता एवं व्यवसाय विकास यानि ईबीडी के अंतर्गत मिशन रीव उद्यमिता सहयोग सेवाऐं यानि ईएसएस देने में प्रयासरत है जिसमें कई युवाओं को लोन व अन्य सुविधा प्रदान की जा चुकी है तथा यह प्रयास निरंतर जारी है। युवाओं को बेरोजगार होने की स्थिति में अपना कोई भी व्यवसाय शुरु करने के लिए मिशन रीव से जुड़कर उसकी समस्त औपचारिकताओं से मुक्ति देकर रीव व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण एवं लोन आदि की सुविधा प्रदान कर व्यवसाय को स्थायित्व देने में सहयोग कर रहा है। द रीव टाइम्स इस अंक में हम आप के साथ कुछ केस स्टडी साझा कर रहे है, जो यह स्पष्ट करती हैं कि मिशन रीव किस तरह गांव के युवाओं के उद्यमी बनने के सपने को साकार करने में सहायता कर रहा है..."

केस स्टडी – 1
गौरव के घर लगाई एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग मशीन

विकास खण्ड जुब्बल – कोटखाई में **बैंकिंग, फाइनेंस और इंशोरेंस प्रभाग** के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग, एप्पल ग्रेडिंग व पैकिंग मशीन को स्थापित कर रोजगार के क्षेत्र में सराहनीय पहल की है। गौरव शर्मा जो कि जुब्बल से संबन्धित है, द्वारा मिशन रीव में आवश्यकता आकलन के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए आवेदन किया गया। इसके लिए मिशन रीव ने समस्त संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना पर कार्य किया तथा फूड प्रोसेसिंग, एप्पल ग्रेडिंग व पैकिंग मशीन को स्थापित किया। इस प्रोजेक्ट पर अनुमानित लागत 10 लाख 40 हज़ार रुपये थी जिसके लिए मिशन रीव द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत युको बैंक जुब्बल से लिंक करवाकर गौरव शर्मा को यह लोन स्वीकृत करवाया गया। लोन लेने के बाद मिशन रीव ने ही मशीन और उसके उपकरणों को पहचान कर स्थापन में भी सहयोग किया। इस प्रोजेक्ट को बनाने, लगाने तथा क्रियान्वयन में मिशन रीव ने संपूर्ण सहयोग किया। गौरव शर्मा ने द रीव टाइम्स को बताया कि मिशन रीव को आवश्यकता आकलन में रोजगार के लिए आवेदन किया था तथा इस प्रकार की फूड प्रोसेसिंग, एप्पल ग्रेडिंग व पैकिंग मशीन को लगाने पर चर्चा के बाद उसके स्थापन के लिए मिशन रीव ने इस प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाया है। इस प्रोजेक्ट की पूरी रुपरेखा और क्रियान्वयन मिशन रीव के तहत हुआ तथा इसकी स्थापना के बाद न केवल मुझे अपने घर पर ही सम्मानजनक रोजगार प्राप्त हुआ है बल्कि मेरे साथ कई बेरोजगारों को भी रोजगार मिला है। मैं मिशन रीव का बहुत आभारी हूं क्योंकि मुझे इस मशीन और व्यवसाय की जानकारी नहीं थी।

केस स्टडी – 2
सच हुआ सिरमौर के प्रीतम का सपना...

राजगढ़ सिरमौर से प्रीतम ठाकुर ऑटोमोबाइल में प्रशिक्षण लिया है। उन्होंने मिशन रीव के तहत आवश्यकता आकलन में ऑटोमोबाइल, स्पेयरपार्टस और एक्सेसरीज़ के लिए आवेदन किया था। मिशन रीव ने इस आवश्यकता को समयसीमा के तहत ही पूरा करते हुए राजगढ़ में टीम के सहयोग से इसकी पूरी रुपरेखा तैयार कर प्रोजेक्ट तैयार किया गया। यह अनुमानित रुप से 10 लाख रुपये का प्रोजेक्ट था। संबन्धित बैंक से लिंक कर यह लोन स्वीकृत करवाया गया तथा उसके बाद ऑटोमोबाइल, स्पेयरपार्टस और एक्सेसरीज़ को स्थापित कर उद्यमिता के लिए बेहतर शुरुआत की गई। प्रीतम ठाकुर ने बताया कि मुझे ऑटामोबाइल में प्रशिक्षित होने

के बाद भी रोजगार के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा था। न ही मुझे औपचारिकताओं का पता था। ऐसे में मिशन रीव ने मेरा मार्गदर्शन किया तथा प्रोजेक्ट बनाकर, लोन स्वीकृत करवाकर स्थापित कर दिया। मेरे साथ इसमें कई और बेरोजगारों को मैं अब रोजगार दे रहा हूं। मिशन रीव को इसके लिए आभार जताया।

केस स्टडी – 3
अब प्रियंका की अपनी गारमेंटस् शॉप

ऐसा ही उद्यमिता का सफल उदाहरण देहरा गोपीपुर, कांगड़ा की प्रियंका कुमारी का है जिसका मिशन रीव सहारा बना है। प्रियंका गारमेंटस् सेल शॉप के माध्यम से व्यवसाय करना चाहती थी। इसके लिए मिशन रीव ने प्रोजेक्ट तैयार कर समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया तथा बैंक से 9 लाख अस्सी हज़ार का लोन दिलवाने में रीव ने ही सहयोग किया।

आज प्रियंका गारमेंटस् सेल शॉप के माध्यम से अपने रोजगार में बढ़ौतरी करते हुए एक सफल उद्यमी बनने की राह पर है। प्रियंका कुमारी ने द रीव टाइम्स को बताया कि मिशन रीव के माध्यम से उनके उद्यम को राह मिली और उनके इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सका। आज मैं अपनी पसंद का काम कर रही हूं।

ऐसे काम करता है मिशन रीव
उद्यमिता सेवा सहयोग (ईएसएस)

कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय स्वतंत्र रुप से शुरु करना चाहता है या सामुहिक रुप से समयसीमा व अन्य सीमित संसाधनों के माध्यम से इस प्रकार का लघु उद्योगधंधा आरम्भ करना चाह रहा है उसके लिए मिशन रीव सहयोगी की भूमिका में सेवाऐं देगा। हमारे देश में यह विडंबना ही कहा जाऐगा जिसे सर्वे भी मानते हैं कि किसी भी व्यवसाय को शुरु करने के एक वर्ष के भीतर ही समुचित सहयोग और अनुकूल व्यवस्था न मिल पाने के कारण या तो व्यवसाय छोड़ देते हैं या वो असफल हो जाते हैं। इसलिए यहां यह आवश्यक हो जाता है कि इन युवा उद्यमियों को उद्यमिता की बारीकियों से प्रशिक्षित किया जाए तथा इसके लिए एक सहयोगात्मक माहौल तैयार किया जाए। इसके लिए कई गतिविधियों को समावेश करते हुए उन्हें सहयोग दिया जा सकता है। उद्यमिता सेवा सहयोग युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन देता है ।

ये हैं इसकी विशेषताऐं

- लघु उद्योग एवं लघु व्यवसाय के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने में विश्लेषण करना
- सेवा व उत्पाद के चयन में सहयोग करना तथा इसके लिए प्रस्ताव की रुपरेखा तैयार करना
- लघु उद्यम को लगाने में संपूर्ण प्रक्रिया को लाभार्थी को प्रदान करना
- लघु उद्योग की स्थापना करने में प्रबंधकीय कौशल को प्रदान करना
- अन्य समस्त औपचारिकताओं को तकनीकि आधार पर सहयोग करना

विशिष्ट सेवाऐं

- व्यवसाय योजना की पहचान करना
- वित्तिय एवं तकनीकि संस्थानों से उद्यमी को संबद्ध करवाने के प्रयास करना
- समस्त सरकारी लाईसेंस, उनकी स्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि को पूरा करना
- व्यवसाय एवं वित्तिय योजना तैयार करना
- एक वर्ष के लिए मेंटोरशिप सहयोग प्रदान करना

समस्त उपलब्ध सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से होगा।

क्या कहते हैं मिशन रीव के ईडीपी व बी.डी. प्रवीण मिश्रा

मिशन रीव का ध्येय आम लोगों तक सुविधाओं को पंहुचाने के अलावा उद्यमिता के क्षेत्र में बेरोज़गार युवाओं को स्वावलंबी बनाकर अपना व्यवसाय आरंभ करने के प्रति भी सेवाऐं देना है। इसी के तहत जुब्बल – कोटखाई, सिरमौर के राजगढ़ और कांगड़ा के देहरा गोपीपुर में युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में लघु उद्यम आरंभ करवाने में सहयोग किया गया। इसके लिए आरंभ से अंत तक समस्त औपचारिकताओं को मिशन रीव के तहत पूरा किया गया तथा अब ये युवा अपना रोज़गार आरंभ कर अन्य बेरोज़गारों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं ।

इस प्रकार मिशन रीव दिल से सेवा – दिल से भुगतान के मूलमंत्र के आधार पर बैंकिंग, फाइनेंस और इंशोरेंस प्रभाग के अंतर्गत उद्यमिता के क्षेत्र में सेवाऐं दे रहा है और भविष्य के लिए इस प्रकार के प्रयास चल ही रहे हैं।

श्रीकांत बाल्दी ने संभाला मुख्य सचिव का कार्यभारप्रबंध निदेशक डॉ0 एल सी शर्मा ने की शिष्टाचार भेंट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के नए मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने 2 सितंबर को मुख्य सचिव पद का कार्यभार संभाल लिया। उनके पद संभालते ही बीके अग्रवाल मुख्य सचिव पद से रिलीव होकर नई दिल्ली रवाना हो गए। अग्रवाल सचिव लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। डॉ. बाल्दी प्रदेश सचिवालय में सुबह प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के अपने पुराने कार्यालय में ही बैठे।

यहां उनसे लोग मिलते रहे और अहम जिम्मेवारी मिलने पर उन्हें शुभकामनाएं देते रहे। इसके बाद दोपहर को डॉ. बाल्दी मुख्य सचिव कार्यालय गए। वहां बीके अग्रवाल ने उनका स्वागत किया और उन्हें सीएस की कुर्सी पर बैठाया। अग्रवाल ने बाल्दी को मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति के लिए बधाई दी। इसके बाद अग्रवाल खुद रिलीव हो गए और डॉ. बाल्दी उन्हें बाहर तक छोड़ आए।

प्रबंध निदेशक, आईआईआरडी डॉ० एल सी शर्मा ने डॉ० श्रीकांत बाल्दी से सचिवालय कार्यालय में जाकर शिष्टाचार भेंट की तथा उनको नई जिम्मेवारी के लिए शुभकामनाऐं दी। उनके साथ फ्लायर ग्रुप सी ई ओ आन्नद नायर तथा सह संपादक अंजना ठाकुर भी उपस्थित थे।

डॉ० एल सी शर्मा ने मुख्य सचिव को आईआईआरडी आने का न्यौता भी दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि उन्होंने कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में आईआईआरडी में शिरकत की थी तथा भविष्य में भी समय मिलने पर आऐंगे।

फिट इंडिया अभियान का नेहरु युवा केन्द्र संगठन ने किया आगाज़
आईआईआरडी के सहयोग से शनान में लाइव कार्यक्रम हुआ

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हम फिट तो देश फिट..... इस संबोधन से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देशवासियों को फिट रहने के लिए औपचारिक रुप से फिट इंडिया अभियान की शुरुआत करते हुए आवाहन किया और कहा कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सफलता की सीढ़ीयों को तय करता है। फिट इंडिया अभियान के सजीव कार्यक्रम को नेहरु युवा केन्द्र संगठन, हि.प्र. ने आईआईआरडी शिमला के सहयोग से आईआईआरडी कॉप्लेक्स शनान में एक कार्यक्रम में मनाया गया। भारत सरकार ने हर भारतवासी को फिट रहने व स्वस्थ रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा अभियान शुरु किया है। इस अवसर पर दिल्ली से प्रसारित रंगारंग कार्यक्रम में फिट इंडिया की झलक का सभी ने लुत्फ़ उठाया तथा देश को संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से आवाहन किया कि यदि राष्ट्र की उन्नति में मिलकर चलना है तो हमें सर्वप्रथम फिट और स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब यहां के नागरिक स्वस्थ एवं फिट होंगे। कार्यक्रम में निदेशक, नेहरु युवा केन्द्र संगठन, हि.प्र. सुखदेव सिंह ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की और उनके साथ नेहरु युवा केन्द्र शिमला के ज़िला युवा समन्वयक प्रभात कुमार भी उपस्थित रहे। आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डॉ० एल सी शर्मा और निदेशक सुषमा शर्मा ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। निदेशक एनवाईकेएस सुखदेव सिंह ने कहा कि हमें फिट रहने की आवश्यकता हर पल रहती है तथा आज हम बहुत लापरवार हो गए हैं जिससे न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हुआ है बल्कि राष्ट्र का विकास भी प्रभावित होता है। प्रबंध निदेशक डॉ० एल सी शर्मा ने कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए तन और मन दोनों प्रकार से आज मंथन करने की आवश्यकता है। इसके लिए भविष्य में शीघ्र ही नेहरु युवा केन्द्र के साथ एक बड़ी परियोजना पर फिट इंडिया के कांसेप्ट को ध्यान में रखते हुए काम करने की योजना है तथा इसे मिशन रीव के साथ साझा स्तर पर क्रियान्वित किया जाऐगा।

मंत्रिमंडल के निर्णय

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जिला कुल्लू के आनी क्षेत्र के दलाश में राजकीय बहु-तकनीकी संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया। इस संस्थान के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 97 पद सृजित कर भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने जिला ऊना के बंगाणा में युवाओं की सुविधा के लिए उप-रोजगार कार्यालय खोलने का निर्णय लिया। इसके संचालन के लिए चार पदों को सृजित कर भरा जाएगा। बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भुंतर को तेगुबहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विलय कर 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी तथा रेडियोलॉजी विभागों में एक-एक सहायक प्रोफेसर के पदों को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यक्रम अधिकारियों के 27 और चिकित्सा अधिकारियों के दो पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति दी। बैठक में भरमौर, पांगी तथा लाहौल जनजातीय क्षेत्रों में नये खोले गए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर 50 शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों को सृजित करने तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर के लिए रामपुर तथा सिरमौर के लिए नाहन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरणों में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर आशुटंककों के चार पद तथा दैनिक आधार पर सेवादार के चार पदों को सृजित कर भरने

की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल नेरचौक के परिसर में बागी उपमण्डल के तहत विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित करने तथा भरने सहित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया अनुभाग खोलने का भी निर्णय लिया। बैठक में नगर एवं ग्राम योजना विभाग में अनुबंध आधार पर योजना अधिकारी के दो रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की।

प्रदेश को मिले कैम्पा के तहत 1660 करोड़

द रीव टाइम्स ब्यूरो

वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण अधिनियम (कैम्पा) के अन्तर्गत मिले 1660.72 करोड़ रुपये का चैक भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि कैम्पा के पास लगभग पिछले 10 वर्षों से लम्बित थी और इस राशि को जल्द से जल्द जारी करने के मामले को कई बार केन्द्र सरकार के समक्ष रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप यह राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे वृक्षा रोपण, मृद्धा और जल संरक्षण, वनों के आधारभूत विकास, वन्यजीव गतिविधियां, स्कूली बच्चों द्वारा वृक्षारोपण, लैंटाना उन्मूलन, बन्दर नसबन्दी जैसे कार्यक्रमों में किया जाएगा तथा कहा कि यह राशि प्रदेश के लोगों को आजीविका प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की वन सम्पदा, पर्यावरण और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है, जिसके लिए कई कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। गोविन्द सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री का क्षतिपूर्ति वनीकरण राशि (अकांउट प्रोसिजर) नियम - 2018 को संसद में पास करने के लिए आभार व्यक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश को इतने लम्बे अन्तराल के बाद इतनी बड़ी राशि जारी हो सकी है। उन्होंने कहा कि इस राशि के उचित प्रयोग के लिए तीन समितियों का गठन किया गया है, जिसमें कार्यकारी समिति के प्रमुख, प्रधान वन अरण्यपाल होंगे जो प्रारम्भिक स्तर पर एपीओ का आंकलन करेगी।

संचालन समिति जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है, एपीओ को मूल्यांकन के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का शुभारम्भ

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा कि 1 सितम्बर से 15 अक्तूबर, 2019 तक राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनएसवीपी) के माध्मम से मतदाता सत्यापन कार्यक्रम चलाया जाएगा।

उन्होंने इस अवसर पर मतदाताओं के अधिकारों और दावों को दर्शाने वाले पोस्टर को जारी कर मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की विसंगतियों को दूर करने के लिए मतदाता सत्यापन कार्यक्रम को आरम्भ किया है।उन्होंने कहा कि शीघ्र बूथ स्तर की मोबाइल ऐप को आरम्भ किया जाएगा, जिसके माध्यम से बूथ स्तर के अधिकारी नाम, पता, फोटो जैसी जानकारियों को दर्ज कर सकेंगे।

जिससे मतदाता सूचियों को पूर्ण रूप से शुद्ध करने में सहायता प्राप्त होगी। देवेश कुमार ने कहा कि मतदाता वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, कहमन सर्विस सेंटर, लोकमित्र केन्द्र, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय (एसडीएम) और पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग मतदाता) हेल्पलाइन आदि के माध्यम से प्रत्येक मतदाता अपनी संबंधित मतदाता सूची में विद्यमान प्रविष्टियों का सत्यापन कर सकता है।

जल्द हो सकता है उपचुनाव का ऐलान: मुख्यमंत्री

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि दस दिन में उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। पार्टी का टिकट पार्टी तय करेगी। इस कार्य में कार्यकर्ता न उलझें। हिमाचल में सरकार को और मजबूत करना है। एक और मजबूत साथी हमें सरकार में चाहिए जो पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की आवाज को बुलंद करे। सराहां में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के उपरांत विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपक्ष चुनाव से पहले कहता था कि प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस काबिज होगी। लेकिन, परिणामों के बाद कांग्रेस को अपनी जमीनी हकीकत पता लग गई है। सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है विकास कार्य। हिमाचल को वह शीर्ष पर देखना चाहते हैं।

केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं जनता के दिल - दिगाम पर छाप छोड़ रही है। कहा कि राज्य के लोगों के अपार समर्थन के फलस्वरूप ही भाजपा ने प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर रिकार्ड मतों से विजय हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार ने 72 प्रतिशत मत प्राप्त कर रिकार्ड कायम किया है। प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम है कि अनुच्छेद 370 को समाप्त कर एक विधान - एक निशान और एक संविधान की परिकल्पना को मूर्त रूप मिला है।

मिशन रीव का दूसरा संस्करण : दिल से सेवा-दिल से भुगतान

मिशन रीव की सेवाऐं

मिशन रीव में महत्वकांक्षी सेवाओं का समायोजन अपनी तरह का अनूठा प्रयास है जो कि विशेष तौर से ग्रामीण परिवेश में सुविधाओं और व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास का आधार भी है ।

स्वास्थ्य डिविजन

- स्वास्थ्य स्लेट–12 विभिन्न टेस्टों के साथ प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच
- मोबाईल मेडीकल लैब–78 मानकों पर आधारित स्वास्थ्य जांच
- जनऔषधी केंद्र– लोगों को घर द्वार पर सस्ती दवा उपलब्ध कराना
- टेलीमेडीसन– लोगों के घर पर ही स्वास्थ्य जांच और ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा

कृषि डिविजन

- मृदा परीक्षण लैब– सदस्यों और किसानों के लिए सेवाऐं
- जैविक खाद निर्माण–किसानों को जैविक खाद निशुल्क प्रशिक्षण और उनके द्वारा निर्मित खाद को बाजार उपलब्ध कराना
- बीज और कृषि उपकरण–किसानों को उनकी मांग के आधार पर उत्तम किस्म के बीज और आधुनिक उपकरण
- फीड सप्लीमेंट– पशुओं में दुग्ध उत्पादन और स्वास्थ्य सुधार के लिए
- जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना और कृषि विकास के लिए योजना बनाकर किसानों को सहयोग देना

यूटिलिटी, लाइसेंस व अन्य ऑनलाइन सर्विसेज डिविजन

- सरकारी योजनाओं और उन पर मिलने वाली छूट की जानकारी आमजन तक पहुंचाना
- पंजीकरण, लाइसेंस, एनओसी और सर्टीफिकेट व अन्य संबंधित दस्तावेजों के निर्माण में सहयोग करना
- **यूटिलिटी, लाइसेंस व अन्य ऑनलाइन सर्विसेज डिविजन**
- सरकारी योजनाओं और उन पर मिलने वाली छूट की जानकारी आमजन तक पहुंचाना
- पंजीकरण, लाइसेंस, एनओसी और सर्टीफिकेट व अन्य संबंधित दस्तावेजों के निर्माण में सहयोग करना
- बिजली, पानी, व अन्य रोजमर्रा से संबंधित यूटीलिटी सेवाऐं उपलब्ध कराना
- ई– स्टेंप, ऑनलाइन शिकायत व अन्य ऑनलाइन सेवाऐं
- **उद्यमिता और व्यवसाय विकास डिविजन**
- क्षमतानुसार बेहतर व्यवसाय चयन और संसाधन जुटाने में सहयोग
- प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता संवर्द्धन में सेवाऐं
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, लोन दिलाने और व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग
- व्यवसाय शुरु करने से लेकर एक साल तक विभिन्न चरणों में सहयोग
- पहले से स्थापित व्यवसाय को बढ़ाने में सहयोग
- **बैंकिंग, फाइनेंस और इंशोरेंस डिविजन**
- बचत, जमा और अन्य बैंकिंग सेवाओं में सहयोग
- बैंक लोन देना और रिकवरी व देनदारी संबंधि सेवाऐं
- संपत्ति प्रबंधन,जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, पशुधन और फसल बीमा संबंधी सेवाऐं

शिक्षा और प्रशिक्षण डिविजन

- गणित, विज्ञान और अंग्रेजी और अन्य विषयों पर ऑनलाइन कोचिंग
- साइकोमीट्रिक और फिंगर प्रिंट आधारित करियर परीक्षण
- व्यक्तित्व विकास और अन्य विकासात्मक पहलुओं में सहयोग
- बचपन, किशोरावस्था व व्यस्क आयुवर्ग आधार पर काउंसलिंग
- ई–लर्निंग टूल्ज और अन्य तकनीक

सामाजिक सुरक्षा और आपदा जोखिम सेवा डिविजन

- बच्चों और बजुर्गों की देखभाल व महिला सशक्तिकरण व अक्षम वर्ग की देखभाल से संबंधित सेवाऐं
- पेंशन व उपलब्ध समय के सदुपयोग में सहयोग
- किसी भी आपदा और आकस्मिक दुर्घटना के समय सेवाऐं
- सामाजिक समस्या, कुरितियों और बुराईयों के निराकरण में पहल

ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग डिविजन

- गांवों में तैयार होने वाले शुद्ध उत्पादों का क्रय–विक्रय
- खरीददारों तक ग्रामीण उत्पादों को पहुंचाना
- गांवों में मांग आधारित उत्पादों की आपूर्ति करना और गांवों से उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना
- प्रदेश के भीतर आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना

संपत्ति प्रबंधन डिविजन

- संपत्ति संबंधि देनदारियों, पंजीकरण, इंतकाल, राजस्व से संबंधित विभिन्न सेवाऐं
- नक्शा तैयार करवाने और स्थानीय प्राधिकरणों से मंजूरी आदि में सहयोग करना
- विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने में सहयोग
- **मीडिया, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन डिविजन**
- द रीव टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल
- ग्रामीण विकास से जुड़ी समस्याओं को विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना
- मिशन रीव ने इस सेवाओं को सार्वजनिक कर आम आदमी को उसकी परेशानियों से मुक्त करने और देश हित तथा स्वयं के विकास के लिए स्वतंत्रता एवं समय प्रदान करने का एक सुअवसर प्रदान किया है।

दिल से सेवा-दिल से भुगतान : इन चरणों में आपके मध्य

सदस्यता के प्रारुप

- **क. वार्षिक प्रदत/paid सदस्यता**

इस प्रारुप में पहले जैसे ही ढांचे पर एक वर्ष के लिए 2000/– रुपये के भुगतान पर सदस्यता प्रदान की जाएगी।

- **ख. आजीवन सदस्यता**

मिशन रीव के दूसरे संस्करण में आजीवन सदस्यता का नया विकल्प रखा गया है। इसके लिए एक बार के 10,000/रू. के भुगतान पर इसका आजीवन सदस्य बना जा सकता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक पंचायत से जो भी आजीवन सदस्य होंगे उन्हें ही रीव सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनने का अवसर प्राप्त होगा।

- **ग. स्वैच्छिक सदस्यता**

इस प्रारुप में सदस्य बनने के लिए कोई भी भुगतान नहीं किया जाऐगा। इसमें कोई भी सदस्य बन सकता है तथा सदस्य बनने के बाद उनका आवश्यकता आकलन होगा ।

- **12 ज़िलें - 12 ब्लॉक : दिल से सेवा - दिल से भुगतान**

प्राथमिक चरण में दूसरा संस्करण प्रदेश के 12 ज़िलों के 12 ब्लॉक में लागु किया जा रहा है। मिशन रीव अपने 10 प्रभागों में विभाजित समस्त सेवाओं को आम लोगों में ले जाकर आवश्यकता आकलन के आधार पर समस्याओं का समाधान करेगा। दिल से सेवा भाव रखते हुए रीव सेवाकर्मी आपके पास आकर आपसे बात करेंगें और आपके लिए सेवाऐं देंगें। निश्चित भुगतान की स्थिति में भी आपसे हमारे साथी एक मुस्कान और दिल से भुगतान की बात करेंगे ... यही ध्येय मिशन रीव को अन्यों से पृथक करता है।

पहले सेवा - बाद मे आमदन - आपके चेहरे पर मुस्कान

इसी मूलमंत्र को मिशन रीव आपके आंगन में दस्तक दे रहा है। आपकी चिंता ही हमारी सेवा को दिशा देता है। समस्या का निदान हमारा सर्वोपरी लक्ष्य है।

कैशलैस होगी पूरी प्रक्रिया और भुगतान

सदस्यता अभियान और अन्य किसी भी भुगतान की स्थिति में इसे पूर्णतः पारदर्शी रखा जाएगा। इसके लिए कोई भी कैश हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। समस्त भुगतान कैशलैस होगा जिसके लिए पॉस मशीनें एवं अन्य संसाधनों का प्रबन्ध किया जा चुका है। इसकी शुरूआत चम्बा जिला से हो चुकी है।

IIRD
हम जानते हैं गाँव को बेहतर

सदस्यता के लिए किसी भी प्रारूप में जुड़ने के लिए निचे लिखे नम्बरो पर सम्पर्क करें

Website : www.missionriev.in या दूरभाष न. - 0177-2640761, 2844073 पर संपर्क करें।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

हिमाचल में किराये के भवनों में चल रहे 16 873 आंगनबाड़ी केंद्र

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत प्रदेश में चल रहे कुल 18,925 आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में से 16,873 केंद्रों के पास अपने भवन नहीं हैं। ये सभी केंद्र किराये के भवनों में चल रहे हैं। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने बताया कि 656 केंद्रों में शौचालयों की सुविधा भी नहीं है।

हिमाचल में 18,96,059 गैस कनेक्शन

हिमाचल में 18,96,059 गैस कनेक्शन हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व मुख्यमंत्री गृहणी सुविधा योजना के तहत 31 जुलाई, 2019 तक प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 1,20,104 गैस कनेक्शन वितरित किए गए जबकि मुख्यमंत्री गृहणी सुविधा योजना के तहत 1,06,978 गैस कनेक्शन दिए गए हैं।

कंगाली से जूझ रहे निगम को झटका, सरकार ने ग्रांट पर चलाई कैंची

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कंगाली के दौर से गुजर रहे भाजपा शासित नगर निगम को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने शहर के मर्ज एरिया में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए दी जाने वाली वार्षिक ग्रांट पर कैंची चला दी है।

अब तक नगर निगम को सालाना तीन करोड़ रुपये मर्ज एरिया ग्रांट के तौर पर मिलते थे। लेकिन इस बार महज एक करोड़ रुपये मिले हैं। सूत्रों के अनुसार तीन अगस्त को सरकार की ओर से मर्ज एरिया ग्रांट का पैसा निगम के पास पहुंच चुका है। ग्रांट में भारी कटौती होने से नगर निगम प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। निगम में पहले ही आर्थिक तंगहाली चल रही है। पार्षदों की दर्जनों फाइलें बजट की कमी के चलते दफ्तर में धूल फांक रही हैं। शहर में कुल 18 वार्ड मर्ज एरिया में शामिल हैं। इन्हें पहले 14–14 लाख रुपये जारी होते थे। लेकिन इस बार ग्रांट कम होने पर सभी को पांच-पांच लाख रुपये ही नसीब हो सकेंगे। इतने कम बजट से नई सड़कें, पार्किंग, पार्क कैसे बनेंगे, इस पर निगम की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

इसलिए मिलती है मर्ज एरिया ग्रांट

शहर के 18 वार्डों में ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जो साल 2006 में नगर निगम में शामिल किए हैं। यह पहले पंचायतों के अधीन थे। इनमें सड़क, सीवरेज, पेयजल, पार्किंग और पार्क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। इन्हें विकसित करने के लिए सरकार हर साल तीन करोड़ रुपये ग्रांट देती है। लेकिन इस बार यह ग्रांट कम कर दी गई है। इससे पहले साल 2012–13 और 2013–14 के दौरान भी निगम की ग्रांट बंद कर दी थी।

इलाज करवाने आई महिला को बता दिया एचआईवी पॉजिटिव कोमा में जाने के बाद मौत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जिला शिमला के एक निजी अस्पताल का कारनामा देखिए। इलाज कराने आई महिला को एचआईवी पॉजिटिव बता दिया गया। इससे महिला पहले अवसाद में चली गई और फिर कोमा में पहुंच गई। जब उसे आईजीएमसी शिमला में लाया गया तो यहां महिला और उसके पति के एचआईवी टेस्ट कराए गए। दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आई। वहीं अब कोमा में चल रही महिला की आईजीएमसी में मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद परिजनों में रोष है। परिजनों ने मांग की है कि निजी अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। महिला के भाई का आरोप है कि निजी अस्पताल की रिपोर्ट के चलते उसकी बहन की तबीयत बिगड़ी। जानकारी के अनुसार रोहड़ू क्षेत्र की 22 वर्षीय महिला को 21 अगस्त को बच्चेदानी की ट्यूब फटने के बाद वहां के एक निजी अस्पताल में लाया गया था। महिला के टेस्ट करवाए गए तो रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव बता दी।

आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में शामिल किया जाए गुर्दा प्रत्यर्पण, मंत्री ने केंद्र को लिखा पत्र

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर किडनी ट्रांसप्लांट को आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में शामिल करने का मामला उठाया है। इसमें कहा गया है कि हिमाचल में किडनी ट्रांसप्लांट को हाल ही में शुरू किया गया है।इसका खर्च चार लाख रुपये तक है। ऐसे में कई लोग इसका खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने यह पत्र लिखा है। फिलहाल, सालाना चार लाख रुपये से कम आय वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री राहत कोष से निशुल्क सेवा दी जा रही है। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने विधानसभा में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुर्दा प्रत्यारोपण पर खर्च ज्यादा है। चार लाख तथा इससे ज्यादा का खर्च बैठ रहा है।

हिमाचल में पैतृक संपत्ति की वसीयत करने से रोकने को कोई कानून नहीं: हाईकोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल हाईकोर्ट ने पैतृक संपत्ति की वसीयत से जुड़े विवाद में स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी को पैतृक संपत्ति की वसीयत करने से रोके। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने निचली अदालतों के फैसलों को उचित ठहराते हुए वादी की अपील को खारिज कर दिया।

अपीलकर्ता वादी राम सिंह ने प्रतिवादी चरण सिंह के खिलाफ दीवानी मुकदमा कायम कर सभी पक्षकारों को विवादित भूमि का संयुक्त मालिक घोषित करने की गुहार लगाई थी। वादी ने पैतृक संपत्ति की वसीयत को निरस्त करने की गुहार भी लगाई थी।

वादी का कहना था कि वह और उसके पिता विवादित भूमि की वसीयत नहीं कर सकते थे क्योंकि वह एक पैतृक संपत्ति है। वादी ने वसीयत की कानूनी वैधता को भी चुनौती दी थी। प्रतिवादी के अनुसार वसीयत कर्ता चुरू उर्फ चूड़ सिंह ने वादी की शादी के लिए कर्ज लिया था जिसे लौटाने के लिए वादी ने अपने पिता की कोई मदद नहीं की। यह रकम प्रतिवादी ने ही चुकाई।

इतना ही नहीं शादी के बाद वादी अपने पिता से अलग रहने लगा था और उसने अपने पिता का कभी हालचाल जानने की जहमत तक नहीं उठाई। दूसरी तरफ प्रतिवादी ने वसीयतकर्ता का न केवल तन-मन से ख्याल रखा बल्कि खेतीबाड़ी में भी उनका भरपूर साथ दिया। वसीयत कर्ता ने अपनी दो तिहाई भूमि वसीयत के माध्यम से प्रतिवादी के नाम कर दी थी। अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी के दावे को खारिज कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

हिमाचल में 102 डॉक्टरों ने छोड़ी सरकारी नौकरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश से डॉक्टरों का पलायन हो रहा है। इनमें से कई डॉक्टर नौकरी छोड़कर दूसरे राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं जबकि कई निजी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं। हिमाचल से बीते तीन वर्षों में 102 डॉक्टरों ने सरकारी नौकरी छोड़ी है।

इन डॉक्टरों ने निजी कारणों और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार को अपने त्यागपत्र थमाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह ने यह जानकारी विधायक रमेश धवाला की ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है।

कमीशन और बैचवाइज डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। मंत्री ने कहा कि हिमाचल में इस समय के बीच 1134 डॉक्टरों की नई भर्ती की गई। इसमें से 102 चिकित्साधिकारियों को अनुबंध आधार पर और 225 नियमित आधार पर नियुक्त किए गए।

शास्त्रीय संगीत से सजी संध्या

शिमला संगीत संकल्प संस्था ने आयोजित किया कार्यक्रम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

संगीत संकल्प संस्था ने कालीबाड़ी हॉल में शास्त्रीय संगीत का आयोजन किया जिसे आईआईआरडी शिमला द्वारा प्रायोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मशहूर सितार वादक हेतराम ने सितार वादन कर दर्शकों का मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपनी एक घंटे की प्रस्तुति में सबका मन मोह लिया। उसके बाद शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम हुआ जिसमें सविता सहगल ने शास्त्रीय गायन पेश किया। उन्होंने राग की ऐसी सरगम छेड़ी कि दर्शक वाह - वाह करते रहे। इसके अलावा सरस्वती वंदना और स्कूली बच्चों ने कत्थक पर नृत्य किया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० सिकंदर कुमार ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उनके साथ संस्था के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल रहे। अपने संबोधन में डॉ० सिकंदर ने कहा कि संगीत से जीवन है और जब हम बात शास्त्रीय संगीत की करते हैं तो उसका आनंद सबसे अलग होता है। इस अवसर पर आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डॉ० एल सी शर्मा भी उपस्थित रहे।

प्रदेश की पंचायतों के प्रधान को पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर का पाठ

द रीव टाइम्स ब्यूरो

डिजिटल इंडिया के तहत प्रदेश की पंचायतों के प्रधानों को भी अब कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का मुख्य मकसद यह है कि प्रधान खुद कंप्यूटर पर पंचायत से संबंधित कार्य कर सकें। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत ऑनलाइन भुगतान को पारदर्शी बनाने के लिए पंचायतीराज विभाग की ओर यह प्रशिक्षण प्रदेश की 3226 पंचायतों के प्रधानों को दिया जाएगा।

प्रशिक्षण के बाद प्रधान पंचायतों से जुड़ी सभी योजनाओं का हिसाब किताब खुद तैयार कर सकेंगे। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तो मदद मिलेगी ही प्रधानों को भी सुविधा रहेगी। प्रधानों को यह प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनरों की ओर से दिया जाएगा। कंप्यूटर प्रशिक्षण के तहत प्रधानों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारियां मुहैया करवाई जाएगी। इसमें प्रधानों को ईमेल, डाउनलोड और अपलोड करना और वेबसाइट के अलावा ऑनलाइन भुगतान संबंध के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानों को विकास कार्यों के एस्टिमेट कैसे बनेंगे और पंचायत के हिस्से में किस कार्ययोजना को किस आधार पर प्राथमिकता देनी है, इनमें प्रधानों को दक्ष बनाया जाएगा। अब तक अधिकतर कार्य पंचायत सचिव ही करते हैं। यही नहीं कुछ जगह तो ऐसे भी प्रधान हैं जिन्हें कागजात तक पढ़ने नहीं आते हैं। लिहाजा नए नियमों से आने वाले दिनों में अंगूठा टेक और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए अब प्रधान बनना आसान नहीं होगा।

प्रधानों को दक्ष बनाना मकसद : केवल शर्मा

पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने बताया कि कंप्यूटर प्रशिक्षण के तहत प्रधानों को पंचायत से जुड़ी विकास की कार्ययोजना की तैयारी में दक्ष बनाना है। इससे प्रधानों को ऑनलाइन सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने के अलावा पंचायतों में उसका कैसे क्रियान्वयन करना है के बारे में बताया जाएगा।

पीएमकेवीवाई में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को वितरित की किट

युवाओं को प्रशिक्षण के साथ–साथ रोजगार की भी गारंटी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आईआईआरडी द्वारा कौशल विकास निगम के सौजन्य से शनान में बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में युवाओं को आईटी से संबन्धित सॉफ्टवेरय का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के लिए एक बड़ी आईटी लैब स्थापित की गई है तथा सरकार के मानकों पर यह प्रशिक्षण युवाओं को दिया जा रहा है। आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डॉ० एल सी शर्मा ने समस्त प्रशिक्षुओं को एक किट प्रदान की जिसमें एक बैग, डायरी, आईडी कार्ड एवं टैग, टी शर्ट आदि प्रदान की गई। प्रशिक्षण के बाद इन युवाओं को रोजगार भी दिया जाऐगा।

चांशल में बादल फटा, महिला मंडल भवन बहा

गढशाली नाले में बाढ़ आने से तीन पुल बहने से खरशाला और शीलादेश का यातायात संपर्क भी टूटा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रोहड़ू दृचिड़गांव क्षेत्र चांशल घाटी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने से खरशाली के गढशाली के नाले में बाढ़ आ गई, जिससे नाले के साथ लगते क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। इससे तीन पुल नाले में बह गए, जिसमें एक पुल वाहनों का था और दूसरा पुल पैदल यात्रियों के लिए था। बादल फटने से तीन परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रभावित परिवारों के सेब के पौधे नाले में बह गए। ग्राम पंचायत खरशाली के गढसारी नाला में बाढ़ आ जाने से महिला मंडल भवन क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं भवन का शौचालय भी क्षति ग्रस्त हो गया। महिला मंडल भवन में कुछ समय से गांव की प्राथमिक पाठशाला गडशाली भी चल रही थी। कुछ दिन पहले हुई बरसात में स्कूल भवन के क्षतिग्रस्त होने के बाद स्कूल महिला मंडल भवन में शिफ्ट करना पड़ा था। लोगों के सामने यह भी अब बड़ी समस्या हो गई है कि स्कूल की पाठशाला अब कहां ले जाएं। खरशाली और शीलादेश जाने के लिए जहां पैदल पुलों को यह नाला अपने साथ बहा ले गया वहीं गांव को जोड़ने वाली सड़क को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सितंबर माह के शुरू होते ही इस क्षेत्र में सेब तुड़ान भी शुरू हो जाता है। यदि टूटी हुई सड़क को बहाल नहीं किया तो बागबानों को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। किसान सभा के सचिव सुखदेव चौहान ने बताया कि बागबानों को सेब सीजन शुरू करने से पहले बारदाना लाना पड़ता है और सड़क टूट गई है तो अब बागबान कैसे बारदान लाएंगे। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि सेब बहुल क्षेत्रों में सड़कों की हो रही टूट-फूट को प्राथमिकता से पूरा करना होगा। अन्यथा बागबानों और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

जिले के 42 स्कूल आ सकते हैं विभागीय कार्रवाई के लपेटे में

द रीव टाइम्स, ऊना

जिले में 42 सरकारी और गैर सरकारी स्कूल विभागीय निर्देश न मानने और लापरवाही बरतने पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई के लपेटे में आ सकते हैं। एडीसी ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के साथ हाल ही में बैठक कर साप्ताहिक फोलिक एसिड टेबलेट्स न लेने वाले सरकारी स्कूलों पर कार्रवाई करने व निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद भी लापरवाह 16 निजी और 26 सरकारी स्कूलों ने शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय से साप्ताहिक फोलिक एसिड टेबलेट्स अभी तक भी नहीं ली हैं। शिक्षा विभाग ने लापरवाह और विभागीय निर्देशों को न मानने पर अब कार्रवाई करने का मन बना लिया है। उच्च शिक्षा उपनिदेशक पीसी राणा ने बताया कि साप्ताहिक फोलिक एसिड टेबलेट्स को जिला कार्यालय से प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी। उसके बाद भी जिन स्कूलों ने इन टेबलेट्स को प्राप्त नहीं किया तो उन लापरवाह स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और निजी स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

शिक्षा विभाग का अलर्ट, बच्चों की सुरक्षा स्कूल मुखिया की जिम्मेदारी

द रीव टाइम्स, ऊना

आए दिन छोटे बच्चों और नौनिहालों के अपहरण की अफवाहों के चलते शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही स्कूल मुखिया को विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बीते दिन उपमंडल अंब के मैडी में स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही 11वीं की छात्रा पर कोई स्प्रे करने का मामला सामने आया था। हालांकि इस घटना की वास्तिवकता की जांच की जा रही है। लेकिन इन तमाम अफवाहों के बीच शिक्षा विभाग ने स्कूल परिसर में विद्यार्थियों की पूर्ण सुरक्षा का जिम्मेदारी स्कूल मुखिया को सौंपी है। कोई अनहोनी घटना होती है तो स्कूल मुखिया सहित स्टाफ सदस्य विभागीय कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी का वर्दी में आना अनिवार्य किया है। इससे पता लग सके कि स्कूल का कोई भी विद्यार्थी विद्यालय परिसर से बाहर तो नहीं घूम रहा। शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे स्कूल से आते और जाते समय अकेले न जाएं। विद्यार्थी पांच से सात बच्चों का समूह बनाकर विद्यालय पहुंचे और विद्यालय से घर जाएं। बता दें कि कई दिनों से जिले में विद्यार्थियों के अपहरण के मामलों की अफवाहें सामने आ रही है। उच्च शिक्षा उपनिदेशक पीसी राणा ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने स्कूलों में अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने जनता और अभिभावकों से अनुरोध किया कि अगर स्कूल से बाहर ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इससे समय रहते शातिरों पर कार्रवाई हो सके।

सोलन में डेंगू, डायरिया के बाद पीलिया ने पसारे पांव

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

सोलन में डेंगू और डायरिया के बाद अब पीलिया ने भी पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। इसके चलते क्षेत्रीय अस्पताल में पांच मामले हेपेटाइटिस - बी (पीलिया) पॉजीटिव के आने से हड़कंप है। इससे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग बारिश से पीलिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने की बात कह रहा है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पूरे जिला भर से 12 दिनों के भीतर 34 मामले सामने आए हैं। इनमें से क्षेत्रीय अस्पताल में आए पांच मरीजों में हेपेटाइटिस - बी पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि, अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी पीलिया के मामले ज्यादा संख्या में न आने का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन बारिश के कारण पीलिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। जलजनित बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के पास सभी ब्लॉकों में दवाइयां उपलब्ध हैं। इसके साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पीलिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टास्क फोर्स भी ब्लॉक सहित जिला भर में तैनात हैं। इसी के साथ लोगों को जलजनित रोगों के प्रति जागरूक करने के साथ बावड़ियों का पानी न पीने और पानी को उबाल कर पीने की सलाह दी जा रही है।

पांवटा में अवैध खनन करते पकड़े 10 ट्रैक्टर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जिला खनन अधिकारी समेत संयुक्त टीम ने बीते दिनों गिरि नदी में अवैध खनन पर दबिश देते हुए अवैध खनन करते 10 ट्रैक्टरों को पकड़ लिया। 3 ट्रैक्टर संचालकों को 30 हजार जुर्माना किया गया। जबकि, सात ट्रैक्टरों को जब्त कर अदालत में मामला बना कर भेज दिया गया है। इससे पूर्व भी एमओ की टीम ने छापामारी कर 4 ट्रैक्टरों को अवैध खनन करते हुए पकड़ा था। बिते दिनों जिला खनन अधिकारी सरित चंद्र के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने पांवटा के बांगरन पुल के आसपास से नवादा पुल के बीच क्षेत्रों में छापामारी की। टीम में राजबन पुलिस चौकी प्रभारी रवि कुमार व आरओ सुप्रभात समेत संयुक्त टीम ने दिन भर विभिन्न स्थलों पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। बांगरन पुल के समीप तथा नवादा के पास गिरी नदी के क्षेत्रों में छापा मार कर 10 ट्रैक्टर पकड़ लिए गए। जिसमें 3 ट्रैक्टर संचालकों से मौके पर ही 30 हजार जुर्माना राशि वसूली गई। इनमें से सात ट्रैक्टरों को जब्त कर वन थाना परिसर पुरुवाला में ले जाया गया है। इनके मामले अदालत में भेजे जा रहे हैं। उधर, जिला खनन अधिकारी सरित चंद्र ने कहा कि खनन विभाग, राजबन पुलिस चौकी व आरओ पांवटा समेत संयुक्त टीम ने छापामारी की गई है। इस दौरान कुल 10 ट्रैक्टर अवैध खनन करते पकड़े हैं। 3 ट्रैक्टर संचालकों से 30 हजार जुर्माना वसूला गया है। 7 ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर इनके मामले अदालत में आगामी कार्यवाही को भेज दिए है।

अंतरराष्ट्रीय कबड्डी को जल्द अलविदा कह सकते हैं अजय ठाकुर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

खेल क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद पद्मश्री अजय ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी को अलविदा कह सकते हैं। इसके बाद अपने पैतृक गांव दभोटा में अकादमी चलाकर हिमाचल के युवक - युवतियों को कबड्डी के दांवपेंच सिखाएंगे। बीते दिनों मीडिया में प्रकाशित समाचारों के मुताबिक खुद अजय ठाकुर ने इसका खुलासा किया है। डीएसपी अजय ठाकुर ने कहा कि उनका सपना था कि वे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए जाएं। माता-पिता और गुरुओं के आशीर्वाद से अर्जुन अवार्ड के लिए नामित होने से उनका सपना साकार होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि वे प्रो - कबड्डी लीग के लिए भी एक - दो सीजन ही खेलेंगे। इसके बाद दभोटा में ही अकादमी चलाएंगे। अजय ठाकुर को इसी वर्ष 11 मार्च को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद देश का यह चौथा बड़ा सम्मान है। अब उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। पद्मश्री अजय ठाकुर ने देश - विदेश में अपनी प्रतिभा का डंका बजाया है। सरकार ने उन्हें डीएसपी के पद से नवाजा है। उनकी पोस्टिंग बिलासपुर में है। आजकल वह प्रो - कबड्डी लीग में तमिल थलाईवा टीम की कप्तानी कर रहे हैं। अजय को वैसे तो घर से ही स्पोर्ट्स का माहौल मिला है, लेकिन उन्होंने खेल कॅरिअर की शुरुआत दभोटा में जन सहयोग से बनाए खेल मैदान से की है। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एवं एनआईएस कोच राकेश कुमार से खेल की बारीकियां सीखीं। इसके बाद साई हॉस्टल बिलासपुर से कबड्डी में अपने कॅरिअर को आगे बढ़ाया। अजय ठाकुर के कॅरिअर को उड़ान प्रो - कबड्डी लीग से मिली। पहले ही सीजन में बंगलूरू बुल्स से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया। अजय ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अपितु एक मंच मिलने की आवश्यकता है। नालागढ़ में हरियाणा और चंडीगढ़ की तर्ज पर एक ही स्थल पर सभी सुविधाओं तथा खेल मैदान वाला स्पोर्ट्स कांप्लेक्स होना चाहिए। यदि स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बन जाता है तो अन्य कई खिलाड़ी प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं।

कंट्रोलर नवनीत मरवाह का तबादला, भ्रष्टाचार का आरोपी सहायक नियंत्रक भूमिगत

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

सहायक दवा नियंत्रक के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई के 24 घंटे के भीतर ही सरकार ने दवा नियंत्रक नवनीत मरवाह को भी पद से हटा दिया। 24 अगस्त का शनिवार के दिन छुट्टी होने पर भी तबादला आदेश जारी कर सरकार ने उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा निदेशालय में बतौर ओएसडी लगा दिया। मरवाह लंबे समय से बद्दी में विभिन्न पदों पर तैनात रहे हैं। निदेशालय में अब वह बतौर ओएसडी निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा का सहयोग करेंगे। उन्हें खाद्य सुरक्षा का काम सौंपा है। सूचनाओं के मुताबिक सहायक दवा नियंत्रक सरीन के कई बार दौरों पर जाने और कार्रवाई न होने के अलावा मरवाह के खिलाफ भी कई शिकायतें सरकार को मिली थीं। उधर भ्रष्टाचार का केस दर्ज होने के बाद भूमिगत सहायक दवा नियंत्रक निशांत सरीन काफी समय तक सामने नहीं आया। आरोपी के खिलाफ विजिलेंस के सोलन थाने में मामला दर्ज हुआ है। जांच के दौरान बद्दी दवा नियंत्रक कार्यालय में करीब ढाई घंटे तक टीम फाइलें खंगालती रहीं। छानबीन के दौरान चंडीगढ़ में आरोपी की रिहायश से विदेशी शराब और जीरकपुर से नकदी बरामद हुई है। इस दौरान दबिश की भनक लगते ही सरीन गायब हो गया। विजिलेंस ने सभी ठिकानों से मिले दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। आरोपी के सामने आते ही मामले से जुड़े अन्य पहलुओं का भी खुलासा होगा।

कालाअंब – साढौरा संपर्क सड़क की हालत खस्ता

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

औद्योगिक क्षेत्र के कालाअंब - साढौरा (हरियाणा) हाईवे पर स्थित उद्योगों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग की हालत बदतर हो गई है। बरसात में ये मार्ग उफनती नाले में तबदील हो रहा है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल व हरियाणा की सीमा पर ओगली मौजा के तहत खारा-खारी इलाके में कैल्शियम कार्बोनेट व दवा निर्माण से जुड़े एक दर्जन उद्योग स्थित हैं। ये उद्योग व खारी गांव हरियाणा के यमुनानगर हाईवे से एक कच्चे संपर्क मार्ग के माध्यम से जुड़ते हैं। भारी बरसात होने पर ये मार्ग उफनते नाले में तबदील हो जा रहा है, जिससे ग्रामीणों के साथ-साथ उक्त उद्योगों में कार्यरत कामगारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आधा रास्ता हरियाणा व आधा हिमाचल की सीमा में आता है। उक्त क्षेत्र के उद्योगों में 500 से ज्यादा श्रमिक काम करते हैं जिनमें 200 के करीब महिलाएं भी शामिल हैं। कामगारों में शीला, नम्रता, राजेश, मंसूर, आरिफ, रेखा, बिमला व राजू आदि ने बताया कि बरसात के दिनों में रास्ते में अक्सर बाढ़ जैसी स्थिति बनी रहती है। दो राज्यों की सीमा होने के कारण कोई भी सरकार इसकी हालत नहीं सुधार रही। औद्योगिक संगठन लघु उद्योग भारती कालाअंब के अध्यक्ष संजय सिंगला ने बताया कि खारी इलाके के उद्योगों को जाने वाला ये मार्ग दो राज्यों की सीमा में आता है, जिसका अधिकांश भाग हरियाणा क्षेत्र में आता है। उद्यमियों ने अपने स्तर पर हरियाणा सरकार को उपायुक्त यमुनानगर के माध्यम से इस मार्ग को सुधारने के लिए ज्ञापन भेजा था जिस पर हरियाणा सरकार कार्रवाई कर रही है। साथ ही प्रदेश सरकार को भी लिखा गया है।

गिद्धों की घटती संख्या, पर्यावरण संतुलन के लिए खतरा

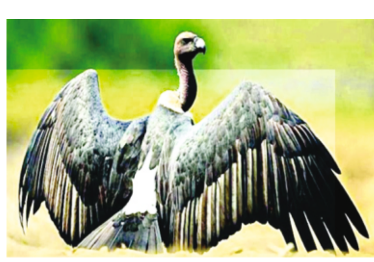

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

गिरिपार क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन के लिए अहम माने जाने वाले गिद्धों की लगातार घटती संख्या चिंता का विषय बन गई है। आसमान में विचरण करते गिद्धों के बड़े - बड़े समूह अब बिरले ही नजर आते हैं। इसको लेकर पर्यावरण प्रेमी भी चिंतित हैं। गिद्धों की घटती संख्या पर्यावरण संतुलन के लिए बड़ा खतरा है। गिद्ध खुद पर्यावरण को साफ बनाने का काम करते हैं। खुले में किसी भी जानवर के मरने के बाद गिद्ध इसे अपना भोजन बनाकर पर्यावरण को साफ व सुथरा बनाने में अहम योगदान देते हैं। लेकिन, इनके दुर्लभ होने के बाद जानवरों के खुले में मरने से संक्रमण का खतरा बन रहता है। केंद्रीय जू अथॉरिटी ने करीब 15 साल पहले इस सिलसिले में हिमाचल को सचेत किया था। इसमें कहा गया था कि यदि गिद्धों की संख्या हिमाचल में इसी तरह कम होती रही तो यह पर्यावरण संतुलन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि, इसके बाद वाइल्ड लाइफ विंग द्वारा वर्ष 2004 से इनके संरक्षण के लिए कार्य शुरू किया गया। वाइल्ड लाइफ विंग ने इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रजनन कार्य पर ध्यान दिया। उधर वन अरण्यपाल बीएस राणा ने बताया कि गिद्धों की घटती संख्या चिंता का विषय है। लेकिन, पिछले कुछ वर्षों से वन्य प्राणी विभाग ने इसको लेकर कार्य किया है। इससे इनकी संख्या में सुधार आया है। वाइल्ड लाइफ विंग के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन, सिरमौर जिले में गिद्धों की संख्या की हकीकत दावों से बेहद परे है। करीब 20 साल पहले तक सिरमौर जिला के आसमान में जहां सैकड़ों की संख्या में गिद्धों का समूह ऊंची उड़ान भरते नजर आता था। वहीं अब इक्का - दुक्का गिद्ध बड़ी मुश्किल से नजर आते हैं। भारत में लगभग हर प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं। इनमें यूरेशियन ग्रीफन, हिमालयन ग्रीफन, व्हाइट - बैक्ड और सलेंडर बिल्ड जैसी प्रजातियां प्रमुख हैं। अब देश के सभी क्षेत्रों में इन सभी प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट छा गया है। मसलन यूरेशियन ग्रीफन, हिमालयन ग्रीफन, व्हाइट - बैक्ड और सलेंडर बिल्ड प्रजातियों के गिद्धों की अच्छी संख्या वाले राज्यों में शुमार हिमाचल प्रदेश में अब इन्हें वन्य प्राणियों की सूची में क्रिटिक्ली एंड डेंजर्ड घोषित कर दिया गया है। वर्ष 2019 आते-आते स्थिति यह बन गई है कि हिमाचल में गिद्ध नाममात्र के ही रह गए हैं। कई स्थानों पर तो ये नजर आना ही बंद हो गए हैं।

सिरमौर में अभी भी कई सड़कें बंद

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

बारिश तो थम गई है लेकिन तीसरे दिन भी सिरमौर में लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। सिरमौर में अभी भी 53 सड़कें बंद पड़ी हैं। हालांकि, लोक निर्माण विभाग सड़कों को बहाल करने में जुटा है लेकिन, कई संपर्क सड़कें आवाजाही के लिए बहाल नहीं हो पाईं हैं। ऐसे में यात्री ही परेशान नहीं है, बल्कि किसान, स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी और कामकाजी लोग भी दिक्कतें झेल रहे हैं। किसान अपनी नकदी फसलों को बाजार तक पहुंचाने में असमर्थ हैं। इन दिनों बरसाती सीजन चल रहा है। इस सीजन में मूली, धनिया, टमाटर, शिमला मिर्च, बीन्स और गोभी आदि अन्य नकदी फसलों को बाजार तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। नाहन क्षेत्र में अभी चार सड़कें बलसार-झाजर, शंभुवाला - मातर भेड़ों, जलालपुल-शिरू माइला और बिरला-धायली संपर्क सड़कें बंद हैं। इसके अलावा राजगढ़ मंडल में आठ सड़कों पर आवाजाही ठप है। संगड़ाह इलाके में 11 सड़कों पर यातायात बहाल नहीं हुआ है। जबकि, शिलाई क्षेत्र में सबसे ज्यादा 30 सड़कें बंद हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

फर्जी हाजरियां लगाने पर तीन के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा
विधानसभा क्षेत्र गगल के निकटवर्ती गांव वैदी के तीन लोगों पर मनरेगा में फर्जी हाजिरी लगाने पर मुकद्दमा दर्ज हुआ है। यह केस रितेश गार्गी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। गार्गी ने ग्राम पंचायत वैदी की प्रधान पिंकी देवी व उपप्रधान राजेश कुमार पर पंचायत प्रधान के बेटे विशाल की मनरेगा में फर्जी हाजिरी लगाने व मनरेगा की राशि का दुरुपयोग करने के बारे में सात अगस्त को प्रदेश पुलिस के डीजीपी से शिकायत की थी। वहीं डीजीपी के निर्देशों के अनुसार गगल पुलिस थाना में 21 अगस्त को मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं पुष्टि करते हुए डीएसपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। आरोपियों में प्रधान, उपप्रधान और प्रधान का बेटा शामिल है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में पंचायत के प्रधान व उपप्रधान पर आरोप लगाए हैं कि प्रधान के बेटे की जहां आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र नगरोटा बगवां में हाजिरी लगी है, वहीं उन्हीं दिनों मनरेगा में भी उसकी फर्जी हाजिरी लगाई गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने पीएम को लिखा पत्र

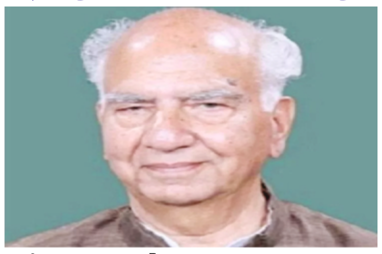

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा
पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में शांता कुमार ने लिखा है कि कश्मीर मसले को हल करने के बाद अब आप अपनी कार्य सूची में जनसंख्या नियंत्रण को शामिल करें। शांता ने पत्र में लिखा है कि सरकार द्वारा रोजगार देने के बाद भी बढ़ती आबादी के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। कुछ निराश - हताश नौजवान अपराध करने और आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। कहा कि 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री की ओर से इस समस्या के जिक्र से उन्हें ही नहीं, बल्कि देश को यह विश्वास हो गया है कि कश्मीर समस्या के समाधान के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण अवश्य होकर रहेगा।

जिले में 10 मकान ढहे, 20 को नुकसान और 23 गोशालाएं गिरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर
जिले में भारी बारिश से करीब 24 करोड़ का प्रारंभिक नुकसान आंका गया है पिछले 24 घंटे में बारिश से लोनिवि, आईपीएच, कृषि, बागवानी, बिजली बोर्ड और राजस्व विभाग को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा एक गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई है। इस हादसे में गाड़ी चालक की मौत हो गई है। जबकि जिले में 10 मकान जमींदोज, 20 को पहुंचा नुकसान और 23 गोशालाएं ध्वस्थ हो गईं हैं। इससे लाखों का नुकसान हुआ है। सभी नेशनल हाईवे समेत अन्य सड़कें बंद होने से लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी। जिला प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बारिश के कारण बिलासपुर जिले में लोक निर्माण विभाग की 84 सड़कें बंद हो गई हैं जिससे विभाग को करीब 12.80 करोड़ का नुकसान प्रारंभिक रिपोर्ट में आंका गया है। जिले में सड़कों को बहाल करने के लिए 53 जेसीबी लगाई गई हैं। अकेले स्वारघाट से लेकर छड़ोल तक करीब 35 स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। इसके अलावा घुमारवीं में 25 बीघा जमीन को नुकसान पहुंचा है। जबकि पूरे जिले में राजस्व विभाग को करीब आठ करोड़ रुपये का नुकसान आंका जा रहा है। जबकि बागवानी, कृषि और राजस्व विभाग को भी बारिश के कारण आठ करोड़ के करीब नुकसान की बात कहीं जा रहा है। हालांकि इसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जबकि बिजली बोर्ड को बारिश से 11 लाख का नुकसान आंका गया है। कार्यकारी उपायुक्त विनय धीमान ने बताया कि बारिश के कारण प्रारंभिक जांच में जिले में करीब 25 करोड़ का नुकसान आंका गया है।

पट्टा पंचायत के बलोह गांव में मिलेगी आपदा पीड़ित परिवारों को जमीन

द रीव टाइम्स, बिलासपुर
घुमारवीं के कसारू पंचायत के गांव करयालग में रविवार सुबह भूस्खलन की चपेट में आने से बेघर हुए लोगों को प्रशासन की ओर से पट्टा पंचायत के बलोह गुगा मंदिर के साथ ही जमीन दिखाई गई है। वहीं पीड़ित परिवारों ने भी इस जमीन को अपनी सहमति जता दी है। पीड़ित परिवारों को साथ लेकर कुछ दिन पूर्व को प्रशासन ने जमीन देखी। हर पीड़ित परिवार को मिलेगी तीन बिस्वा जमीन। यह जमीन पट्टा पंचायत के बलोह गांव में गुगा मंदिर के साथ ही है। पीड़ित परिवारों के लिए दुख सिर्फ इतना ही होगा कि उन्हें जमीन अपनी पारिवारिक भूमि से लगभग तीन किलोमीटर दूर तथा दूसरी पंचायत पट्टा में मिलेगी। पीड़ित परिवारों के प्रति प्रशासन हर तरह से मदद के लिए तैयार है। इन पीड़ित परिवारों को पट्टा पंचायत के गांव बलोह के गुगा मंदिर के पास जमीन दिखा दी है तथा सभी परिवारों ने अपनी सहमति जता दी है तथा शीघ्र ही प्रशासन के द्वारा जमीन उपलब्ध करवा दी जाएगी।

एसडीएम का औचक निरीक्षण अभियान तेज, स्कूल में पाई खामियां

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर
उपमंडल अधिकारी नागरिक सुजानपुर शिल्पी बेक्टा ने हाल ही में पंचायत लंबरी के छोनटी गांव में चल रहे प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान इस सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों से मिलने वाली सुविधाओं और दिक्कतों के संबंध में सवाल पूछे। निरीक्षण के दौरान स्कूल के भवन के साथ-साथ तमाम मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने स्कूली बच्चों से भी बातचीत की। उन्होंने पाया कि स्कूल के एक भवन की हालत खस्ता है, जो कभी भी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। इस पर उन्होंने स्कूल प्रशासन को इसकी रिपोर्ट बनाकर लोक निर्माण विभाग के सुपुर्द करने को कहा और विभागीय उच्चाधिकारियों को भी अवगत करवाने के लिए कहा है। खुद मौके पर उपमंडल अधिकारी ने स्कूल के खस्ताहाल भवन को जल्द बजट उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। उपमंडल अधिकारी शिल्पी बेक्टा ने बताया कि स्कूल के औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षा का स्तर, मूलभूत सुविधाओं के बारे में विस्तृत से जानकारी ली है। स्कूल भवन के लिए बजट का प्रावधान हो, इसके लिए उच्च अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। सुजानपुर उपमंडल अधिकारी लगातार इस तरह के औचक निरीक्षण पर निकल रही हैं। इससे पहले बुधवार को अधिकारी ने सुजानपुर पुलिस के साथ देर रात्रि तक शहर की पेट्रोलिंग की। खुद महिला अधिकारी ने पुलिस के साथ सुजानपुर की नजदीकी पंचायतों का दौरा किया और देर रात 11 बजे तक यह निरीक्षण अभियान चलता रहा।

कमजोर छात्रों को पास करने का नया फार्मूला

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने निम्न और मध्य स्तर के बच्चों को पास करने के लिए फार्मूला तैयार कर दिया है। फार्मूले के तहत निम्न और मध्य स्तर के बच्चे आसानी से पास हो सकेंगे। लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक लेने के लिए बच्चों को सही तैयारी करनी होगी। बोर्ड नौवीं से 12वीं कक्षा की मार्च – 2020 की वार्षिक परीक्षाओं से 40/40/20 फार्मूले से प्रश्नपत्र का पैटर्न तैयार करेगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा होती है, जबकि नौवीं और 11वीं की परीक्षा के लिए भी बोर्ड ही पेपर तैयार करके देता है। इसमें 40 – 40 फीसदी प्रश्न औसत से कम और औसत श्रेणी वाले होंगे, जबकि 20 फीसदी प्रश्नों का आधार उच्च और कठिन होगा। वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्र बोर्ड की निर्धारित पुस्तकों और पाठ्यक्रम से ही होंगे। निजी प्रकाशकों, सहायक पुस्तकों और गाइड से वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न नहीं डाले जाएंगे। 40/40/20 अनुपात में तैयार होने वाले प्रश्नपत्रों में 40 फीसदी प्रश्न औसत से निचले स्तर के होंगे। इसमें जमा दो फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, बायोलॉजी, जियोग्राफी, लेखांकन, हिंदी एवं इतिहास, 10वीं की गणित, सोशल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्नपत्रों में दस फीसदी प्रश्न मल्टीपल च्वाइस के होंगे। 40 फीसदी प्रश्न औसतन और 20 फीसदी कठिन होंगे। बोर्ड सचिव धर्मेश कुमार रामोत्रा ने बताया कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने को अध्यापकों को गाइडलाइन जारी की गई हैं। जमा एक और जमा दो के फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित और बायोलॉजी के प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होंगे। पांचवीं का ईवीएस और गणित, आठवीं का ईवीएस, गणित, सोशल साइंस और साइंस का प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। पूर्व में एक प्रश्नपत्र की तीन सीरीज में प्रश्नपत्रों का क्रमांक बदलकर कई बार एक ही प्रश्न तीनों सीरीज में डाल दिया जाता था, लेकिन अब हर सीरीज में अलग प्रश्न होंगे और पिछले साल पूछे गए प्रश्न इस बार दोहराए नहीं जाएंगे।

आनलाइन ठगी की शिकार हुई महिला, साढ़े 66 हजार निकले

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा
ऑनलाइन ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामले में देहरा के साथ लगते क्षेत्र की एक महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई है। महिला पति के साथ यूपी के लखनऊ में रहती है। उसके पति एसएसबी में कार्यरत हैं। पीड़ित महिला के पिता ने थाना देहरा में ऑनलाइन ठगी की शिकायत सौंपी है। महिला के पिता महेंद्र सिंह निवासी डिगन (बरबाड़ा) तहसील देहरा ने बताया कि उनकी बेटी शिल्पा अपने पति के साथ लखनऊ में रहती है। दो-तीन दिन पहले उसने ऑनलाइन शापिंग से सामान मंगवाया था और उसकी पेमेंट भी कर दी थी। लेकिन तकनीकी कारणों से सामान नहीं पहुंचा। इसके बाद संबंधित कंपनी ने उसे चेक के जरिये पेमेंट वापस कर दी। उनका अकाउंट एसबीआई कांगड़ा में है। ज्यादा जानकारी के लिए उसने लखनऊ से नेट पर सर्च करके एसबीआई कांगड़ा बैंक का नंबर निकाला और उस पर फोन किया। संबंधित फोन पर व्यक्ति ने बताया कि वह बैंक मैनेजर ही बोल रहा है और आपके अकाउंट में कुछ तकनीकी खराबी है और पेमेंट नहीं हो रही है। इसलिए आप अपने एटीएम कार्ड का 16 डिजिट का नंबर लिखा दें। उनकी बेटी ने कार्ड के नंबर बता दिए। करीब आधे घंटे बाद उसके खाते से करीब 66 हजार 711 रुपये निकल गए। महेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी बेटी लखनऊ से खुद शिकायत देने नहीं आ सकती। इसलिए वह स्वयं थाना देहरा में शिकायत देने पहुंचे हैं।

नादौन अस्पताल में एक बिस्तर पर दो से तीन मरीज

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर
भवन की कमी के कारण नादौन अस्पताल में एक ही बिस्तर पर दो से तीन रोगियों का उपचार किया जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई रोगी तो अस्पताल से अपनी जिम्मेवारी पर छुट्टी लेकर कहीं और उपचार करवाने जा रहे हैं। ऐसी हालत में अस्पताल प्रशासन भी मजबूर है। भवन की कमी के कारण एक ही बिस्तर पर तीन-तीन रोगियों का उपचार चल रहा है। दस बिस्तर के इस अस्पताल में दाखिल किए जाने वाले रोगियों की संख्या रोजाना पैंतीस-चालीस तक रहती है। वहीं इसके अलावा रात को आने वाले रोगियों की संख्या अलग से है। जबकि रोजाना दो सौ से अढ़ाई सौ तक की ओपीडी चल रही है। ऐसे में यहां के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिन के समय में भी चिकित्सकों के कमरों के बाहर लंबी लाइनों को अक्सर देखा जा सकता है। अस्पताल के निर्माणाधीन भवन का कार्य कछुआ चाल से चल रहा है। सरकार बनते ही स्वास्थ्य मंत्री ने नादौन दौरे के समय दावा किया था कि एक साल में इस नए भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे, परंतु अभी भी जिस गति से कार्य चल रहा है उससे लगता है कि भवन के लिए लोगों को और अधिक इंतजार करना पड़ेगा। लोगों ने भवन का कार्य शीघ्र पूर्ण करने की मांग की है ताकि, उनकी परेशानियों का हल हो सके। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार का कहना है कि भवन निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

राजस्व विभाग के फिल्ड स्टाफ को बनानी होगी महीने की टुअर डायरी

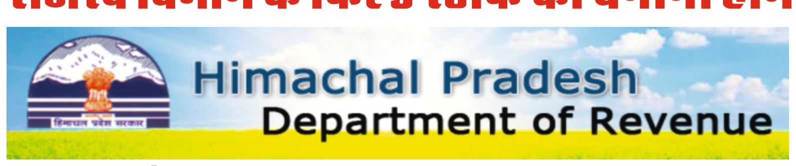

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर
राजस्व विभाग के फिल्ड स्टाफ को अब पूरे महीने की टुअर डायरी पहले बना कर तहसील ऑफिस में जमा करनी होगी। जबकि एक कापी नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी। इसके बाद पूरा महीने का कार्य इसी टुअर डायरी के अनुसार किया जाएगा। उक्त आदेश एसडीएम बिलासपुर नरेंद्र आहलूवालिया ने आरटीआई की अपील की सुनवाई के दौरान दी। वहीं उन्होंने विभाग के जनसूचना अधिकारी को भी आदेश दिए हैं कि वह किसी भी सूचना की समय पर जानकारी दें। उल्लेखनीय है कि फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने कार्यालय तहसील सदर के जनसूचना अधिकारी से क्षेत्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों, क्षेत्रीय कानूनगो की टैंटेटिव टुअर डायरी की मांग की थी जिस पर अढ़ाई महीने बीत जाने पर भी आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने बहस के दौरान उपमंडलाधिकारी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि क्षेत्रीय कानूनगो अपने टुअर के दौरान समय पर पटवार सर्कलों में उपस्थित नहीं होते हैं।

आम लोगों को इनसे संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर भी नहीं होते, अगर होते हैं तो फोन नहीं उठाते, अगर उठाते हैं तो फिर सही से बात नहीं करते। जबकि सूचना पट्ट पर कोई जानकारी अंकित नहीं होती। इस पर एसडीएम बिलासपुर नरेंद्र आहलूवालिया ने सभी फिल्ड स्टाफ को आदेश जारी किए हैं कि वह नियमानुसार टैंटेटिव टुअर डायरी तैयार करेंगे जिसकी एक प्रति कार्यालय में उनके द्वारा जमा करवाई जाएगी तथा एक कापी सूचना पट्ट पर लगाना सुनिश्चित करेंगे।

दलित बस्ती भपराल को जाने वाला रास्ता किया बंद, लोग परेशान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर
जिले की ग्राम पंचायत भपराल की दलित बस्ती को जाने वाली सड़क पर गड्ढा डाल कर लोगों को तंग करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। हालांकि मामला एसडीएम घुमारवीं और पुलिस के पास भी पहुंच गया है लेकिन इसके बाद भी सड़क बहाल नहीं हो पा रही है। वहीं लोगों ने साफ कर दिया है कि 20 अगस्त तक सड़क बहाल नहीं करवाई गई तो वह उपायुक्त बिलासपुर के कार्यालय का घेराव करेंगे। हालांकि पुलिस ने मौके पर आकर रास्ते को बहाल करने का प्रयास किया लेकिन एक पक्ष की दबंगई के कारण स्थिति यथावत बनी हुई है। सड़क को जबरदस्ती तोड़ने के कारण लोगों की गाड़ियां गांव में फंसी हैं। जबकि यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसे मुख्य सड़क तक लाने के लिए कोई भी विकल्प नहीं बच रहा है। ऐसे में दलित बस्ती के ग्रामीणों जिनमें अन्य वर्ग के लोग भी शामिल हैं ने एसडीएम घुमारवीं के पास भी गुहार लगाई थी तथा एसडीएम की ओर से उनके पक्ष में फैसला आया था कि सड़क को दुरुस्त किया जाए लेकिन सड़क को तोड़ने वालों ने एसडीएम के फैसले को ठेंगा दिखा दिया है। यही नहीं मौके पर गई पुलिस भी असहाय साबित हुई है। उन्होंने बताया कि गांव में छह बुजुर्ग 90 साल की अधिक उम्र के हैं। यदि किसी समय पर कोई बीमार हो जाता है तो किस तरह स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया जाए यह एक चुनौती का विषय है। वहीं कुछ दिन पहले ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरु रविदास सभा बैरी रजादियां के अध्यक्ष टीडी बंसल की अगुवाई में सहायक उपायुक्त से मिला जहां उन्होंने सारी व्यथा सुनाई। जहां सहायक उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर मार्ग न सिर्फ खुलवा दिया जाएगा बल्कि दुरुस्त भी करवा दिया जाएगा। लोगों ने बताया कि 20 अगस्त को प्रशासन द्वारा दी गई समय अवधि समाप्त हो रही है। यदि इस समय तक सड़क को बहाल कर दिया गया तो ठीक है अन्यथा ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने से भी गुरेज नहीं करेंगे।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

देवी-देवताओं को मिला दशहरा का निमंत्रण, तैयारियां शुरू

द रीव टाइम्स, कुल्लू

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव को लेकर देव समाज ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दशहरा उत्सव समिति की ओर से देवी-देवताओं को भेजे गए निमंत्रण पत्र मिल गए हैं। ऐसे में देव समाज ने देवी-देवताओं के मुख मोहरों को सजाने का काम आरंभ कर दिया है। ढालपुर में आठ अक्तूबर से रघुनाथ की अगुवाई में आयोजन होगा। दशहरा उत्सव समिति ने दशहरा के लिए 200 से अधिक देवी-देवताओं का बुलावा भेजा है। जिलावासियों के साथ देव समाज को भी आठ अक्तूबर से शुरू होने वाले दशहरा को लेकर बेसब्री से इंतजार रहता है। देवी-देवताओं के कारकून देवी-देवताओं के मुख मोहरों व ढोल-नगाड़ों की मरम्मत करने में जुट गए हैं। दशहरा में देवता बिजली महादेव के साथ बाह्य सराज के अधिष्ठाता खुडीजल, टकरासी नाग, ब्यास ऋषि, कोट पझारी, चोतरू नाग, देवता चंभू, सप्त ऋषि, शेष नाग ने दशहरा में आने की हामी भर दी है।

भगवान रघुनाथ की अध्यक्षता वाले दशहरा उत्सव में साल दर साल देवी-देवताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। दशहरा पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2009 में 224 देवी-देवता शामिल हुए थे। जिला कारदार संघ के महासचिव नारायण चौहान ने कहा कि दशहरा उत्सव समिति की ओर से भेजे गए निमंत्रण पत्र देवी-देवताओं को मिलने शुरू हो गए हैं। उधर, भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने शिमला में जाकर राज्यपाल कलराज मिश्रा को दशहरा के लिए निमंत्रण दिया है।

पूर्व प्रधानमंत्री के अंगरक्षक रहे 73 वर्षीय डालू राम का निधन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

सेना में रहते हुए 1962 और 1971 की लड़ाई लड़ने वाले और बाद में पुलिस में भर्ती होकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और इंद्र कुमार गुजराल के अंगरक्षक रहे डालू राम का देहांत हो गया है। वे 73 वर्ष के थे और कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में उनका उपचार चल रहा था। डालू राम के निधन से बंजार घाटी में शोक की लहर दौड़ गई है। डालू राम स्थायी तौर पर कुल्लू जिला के बंजार स्थित खुंदन के रहने वाले थे। आर्मी से सेवानिवृत्त होने के बाद वे पंजाब पुलिस में भर्ती हुए। पंजाब पुलिस में होनहार होने पर उन्हें दिल्ली पुलिस में लिया गया। वे सब इंस्पेक्टर के पद से वर्ष 2001 में सेवानिवृत्त हुए। दिल्ली पुलिस में रहते हुए उन्हें पीएम सेल में कार्य करने का मौका मिला। बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी ने उनके निधन पर शोक जताया है।

फोरलेन प्रभावितों का मुआवजा डेढ़ महीने में दें

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

किरतपुर-नेरचौक-मनाली फोरलेन परियोजना के प्रभावितों के 17 करोड़ रुपये के शेष मुआवजे का भुगतान डेढ़ महीने में किया जाए। यह निर्देश उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को दिया। हाल ही में हुई बैठक में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने फोरलेन परियोजना से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को परियोजना से जुड़ी अड़चनों को जल्द निपटाने को कहा। राष्ट्रीय उच्चमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना अधिकारियों को फोरलेन की जद में आने वाले भवनों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिग्री कॉलेज पनारसा के भवन निर्माण के लिए निर्धारित साइट पर मलबे की डंपिंग को एक हफ्ते में साफ करवाएं। इसके अलावा मलबे की डंपिंग से अवरुद्ध हुए हणोगी नाले के बहाव को सही किया जाए। कहा कि एनएचएआई डंपिंग के लिए लोक निर्माण विभाग की संपर्क सड़कों का प्रयोग कर रहा है।

संबंधित एजेंसी उन संपर्क सड़कों की मरम्मत का जिम्मा ले। डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि पंडोह के पास डयोड में कटिंग के कारण पहाड़ी में आई दरारों से जिन तीन परिवारों के मकानों को खतरा पैदा हुआ है, एनएचएआई उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करे। खतरे को देखते हुए जल्द इन परिवारों के जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का मामला बनाए। उन्होंने आईपीएच विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि फोरलेन के लिए जहां-जहां सुरंगें बनाई जा रही हैं, उनकी वजह से पहाड़ियों पर स्थित पानी के प्राकृतिक स्रोतों के सूखने की आशंका के निर्मूलन के लिए उपयुक्त कदम उठाएं। उन्होंने परियोजना अधिकारियों को सड़क मरम्मत कार्य में गुणवत्ता का ख्याल रखने के निर्देश दिए।

नगर पंचायत के फंसी लाखों की देनदारी

द रीव टाइम्स, कुल्लू

नगर पंचायत भुंतर में उपाध्यक्ष को पद से हटाने के बाद नपं की बैठक में कोरम पूरा नहीं हो रहा है। इससे लोगों का लाखों का लेनदेन नगर पंचायत के पास फंसा हुआ है। कोरम पूरा न होने से कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। भुंतर मेले को संपन्न हुए दो महीनों से अधिक समय हो चुका है। लेकिन नगर पंचायत ने अभी मेले में लगे हुए साउंड, सजावट और कलाकारों की अदायगी रुकी हुई है। इसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत में मेले के लिए प्लॉट आवंटन किया था, जिससे नपं को लाखों की कमाई भी हुई। कलाकारों, लाइट एंड साउंड, टेंट हाउस, साउंड सिस्टम और सजावट करने वालों ने मसले को तहसीलदार भुंतर के समक्ष भी रखा। लेकिन तहसीलदार ने यह कहकर टाल दिया है कि इस बारे में अभी कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। नगर पंचायत भुंतर के प्रधान कर्ण सेठी ने कहा कि कोरम पूरा न होने से नगर पंचायत के सदस्यों की बैठक नहीं हो पा रही है। इससे पेमेंट देने में परेशानी आ रही है। मेले में जितना खर्चा हुआ है, उसका प्रस्ताव तहसीलदार भुंतर को दे दिया गया है। जैसे ही प्रस्ताव पास होकर आता है तो भुगतान कर दिया जाएगा। उधर, तहसीलदार भुंतर दीक्षांत ठाकुर ने कहा नगर पंचायत भुंतर की ओर से प्रस्ताव आया है। खर्चे को अप्रूवल करवाकर लाने को कहा गया है। लेकिन नपं की कोई भी हाउस मीटिंग नहीं हुई है। इसके बाद ही आगामी प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।

पहाड़ी दरकने से बाढ़ का खतरा, गांव में खौफ का माहौल

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

हिमाचल के कुल्लू जिले की सैंज खड्ड किनारे बसी बस्तियों में रह रहे ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। खड्ड का जलस्तर बढ़ते ही यहां माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। घाटी के लोग 2004 में बाढ़ के दिए जख्मों को अभी भूले नहीं हैं। इस बाढ़ ने पूरे सिउंड बाजार को नक्शे से ही गायब कर दिया था और सैंज बाजार में भी भारी नुकसान होने से लोग आज भी बाढ़ के नाम से खौफ खाते हैं। 15 वर्ष पहले जीवानाला में बादल फटने से मची तबाही का मंजर लोगों को अब भी याद है। हालांकि, अब सैंज खड्ड पर बिजली परियोजनाओं के दो डैम बने हैं और पानी का बहाव टनल के भीतर मोड़ा गया है। बावजूद इसके बरसात में डैम से पानी छोड़ने पर लोग सिहर उठते हैं। निहारनी डैम के आगे किली-री-परेशी की पहाड़ी दरकने से बाढ़ का खतरा अब भी बरकरार है। हाल ही में हुई भारी बारिश के दौरान निहारनी बांध से पानी छोड़ा गया तो इस पहाड़ी से भूस्खलन होना शुरू हो गया। संभावित खतरे को देख न्यूली गांव के लोगों ने अपना समान समेटना शुरू कर दिया। लोगों को डर है कि अगर यह पहाड़ी खिसकी तो खड्ड का बहाव रोक देगी। दरअसल, किली-री-परेशी के पास पहाड़ियां काफी संकरी हैं। भूस्खलन होने की स्थिति में यहां मलबा सीधा नदी में पहुंच रहा है। इस तरह से खड्ड में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लंबे समय से किली-री-परेशी में भूस्खलन को रोकने की मांग उठती रही है लेकिन कोई समाधान न होने से लोग निराश हैं। गाड़ापारली पंचायत के प्रधान भाग चंद, शैंशर के प्रधान नरेश कुमार, शांघड़ की प्रधान सवित्रा देवीतप प्रधान भगत राम और पंचायत समिति सदस्य जयवंती देवी ने कहा कि किली-री-परेशी में भूस्खलन होने से खड्ड का जलस्तर बढ़ रहा है। डैम से पानी छोड़ने से हाल ही में न्यूली में दो दुकानें, एक पुल और कई घराट बह गए। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह भूस्खलन जानमाल को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। किली-री-परेशी का खिसकना सैंज घाटी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। एसडीएम बंजार एमआर भारद्वाज ने कहा कि मौके पर जाकर स्थिति का जायजा किया जाएगा। भूस्खलन रोकने के उचित प्रबंध किए जाएंगे।

सुंदरनगर अस्पताल में अब एक्सरे हुआ महंगा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

नागरिक अस्पताल सुंदरनगर की रोगी कल्याण समिति की बैठक में एक्सरे की दर में बीस रुपये की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। पहले एक्सरे 80 रुपये में होता था अब 100 रुपये लगेंगे। प्राइवेट वार्ड रूम की दर में भी पचास रुपये की बढ़ोतरी की गई है। रेडक्रॉस सोसायटी मंडी ने सशर्त एक्स-रे प्लांट सुंदरनगर अस्पताल को मुहैया करवाया था। यहां एक्स-रे मशीन खराब चल रही थी। अब एक्स-रे की दरें बढ़ाने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इसमें एक सहायक की सेवाएं भी समाहित की गई हैं। लिहाजा वेतन को निकालने के लिए एक्स-रे की दर बढ़ाई है। गवर्निंग बॉडी की वार्षिक बैठक में अध्यक्ष एवं उपमंडल अधिकारी (ना.) राहुल चौहान की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। इस मौके पर रोगी कल्याण समिति के सचिव एवं प्रभारी नागरिक अस्पताल सुंदरनगर डॉ. चमन ठाकुर भी शामिल रहे। सुंदरनगर अस्पताल में रोजाना छह सौ के करीब ओपीडी है। अस्पताल में यूजर चार्जिज में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। बैठक में समिति के सदस्य डॉ. जितेंद्र रुदकी, बीडीसी चेयरमैन सोहन लाल, व्यापार मंडल प्रधान घनश्याम गुप्ता, बलविंद्र सोढी, बरागी राम, जिला परिषद सदस्य नीलम कुमारी एवं अस्पताल वेलफेयर कमेटी के प्रधान वीवी कौशल सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। सुंदरनगर नागरिक अस्पताल में किडनी रोगियों को जल्द ही डॉयलिसिस की सुविधा मिलेगी। यहां डॉयलिसिस सेंटर खोला जाएगा। इसमें मरीजों की सुविधा के लिए चार बेड स्थापित किए जाएंगे। डॉयलिसीस सेंटर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से निर्धारित आउटसोर्स नीति के अनुरूप मरीजों की सुविधा के लिए रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से चलाया जाएगा।

मंडी में सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे पंचायत भवन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

जिले में ग्राम पंचायत भवन और बीडीओ कार्यालय सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे। इन भवनों और कार्यालयों की छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। यह बात उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बुधवार को डीआरडीए भवन में कही। उन्होंने कहा कि मंडी जिले में 469 पंचायतों में से 300 पंचायत भवनों और सभी बीडीओ कार्यालयों की छत पर सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके लिए वर्क ऑर्डर दे दिया गया है। इससे करीब 40 से 50 लाख रुपये सालाना बिजली बिल की बचत होगी। उपायुक्त ने कहा कि जिले में पंचायत भवनों और बीडीओ कार्यालयों की छतों पर 1 से 5 किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाकर बिजली तैयार की जाएगी। इस तरह तैयार बिजली को कार्यालय में इस्तेमाल किया जाएगा, इससे बिजली बिल में बचत होगी। इसके अलावा जो बिजली कार्यालयों में इस्तेमाल से बच जाएगी, यानी अतिरिक्त उत्पादित बिजली को राज्य बिजली बोर्ड खरीदेगा। इसकी एवज में राज्य नियामक आयोग की ओर से निर्धारित दरों पर पैसों का भुगतान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमऊर्जा ने इस साल पूरे प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में उपयोग के लिए 2 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा है। इसका करीब 50 फीसदी लक्ष्य अकेले मंडी जिले ने पूरा कर दिया है। लोगों को घरों की छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार 70 प्रतिशत और राज्य सरकार 4,000 रुपये प्रति किलोवाट सब्सिडी दे रही है। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग, हिमऊर्जा के परियोजना अधिकारी रमेश ठाकुर उपस्थित रहे।

धर्मपुर के रियूर में बच्चा चोर समझ कर महिला को पीटा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

मंडी धर्मपुर के रियूर में अपने बच्चे को लेकर घूम रही मानसिक रूप से बीमार एक महिला को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने पीट डाला। इससे बवाल मच गया। सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। महिला की शिनाख्त के बाद पता चला कि वह मानसिक रूप से बीमार है और गलती से हिमाचल पहुंच गई है। पुलिस ने अब महिला को अपनों तक पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है ताकि महिला और उसका बच्चा सुरक्षित अपनों के पास पहुंच सके। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले एक महिला बरोटी की तरफ से सड़क पर चलती हुई बनाल पंचायत के रियूर गांव पहुंची। उसके साथ एक बच्चा था। बच्चा चोर गिरोह की अफवाह के बीच ग्रामीणों ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो उसने कुछ भी बताने से इंकार किया और अजीब हरकतें करने लगी। उसे लगा कि ग्रामीण उसके बच्चे को छीन रहे हैं। महिला ग्रामीणों को मारने के लिए दौड़ी। इस पर लोगों ने महिला को बच्चे से अलग किया और महिला की पिटाई शुरू कर दी। सूचना धर्मपुर पुलिस थाना को मिली। बात पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। धर्मपुर पुलिस थाना की टीम थाना प्रभारी सुरम सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। जब महिला से पूछताछ की तो महिला ने बताया कि वह गोधरा गुजरात से है। शिनाख्त के बाद महिला को अपनों के पास भेजने की धर्मपुर पुलिस ने कवायद शुरू कर दी। पुलिस थाना प्रभारी धर्मपुर ने लोगों से अपील की कि वह अफवाहों पर विश्वास न करें तथा अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध दिखाई देता है तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाना या चौकी को दें।

मणिमहेश यात्रा : गौरीकुंड के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के लिए आखिरकार रक्षा मंत्रालय ने हेली टैक्सी सेवा शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। रक्षा मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद 27 अगस्त से भरमौर से गौरीकुंड के लिए हेली टैक्सी सेवा आरंभ हो गई है। इससे हजारों शिवभक्तों ने राहत की सांस ली है। गौरीकुंड से मणिमहेश डल झील करीब डेढ़ किलोमीटर दूर है। उधर, चंबा - भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ामुख में पहाड़ को खोदकर रास्ता निकाल दिया गया है। सुबह से बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा में हेली टैक्सी सेवा का एक तरफ किराया 2750 रुपये निर्धारित किया है। यात्रियों को दोनों तरफ की हेली यात्रा करने पर 5500 रुपये चुकाने पड़ेंगे। बीते वर्ष मणिमहेश यात्रा के लिए दोनों तरफ का किराया 5800 रुपये था, जबकि एक ओर की यात्रा करने पर 2900 रुपये चुकाने पड़ते थे। बुकिंग के लिए 50 फीसद ऑनलाइन व 50 काउंटर टिकट का प्रावधान किया गया था। मगर इस बार प्रशासन ने ऑनलाइन बुकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब श्रद्धालुओं को काउंटर से ही टिकट लेनी होगी। भरमौर में हेली कंपनियों के दो हेलीकॉप्टर तैनात हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

कानून की यह जानकारी आपको बनाएगी जिम्मेदार और सजग नागरिक

ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है कि हमें सड़क चलते कोई पुलिस वाला डांट - फटकार देता है और हम कुछ नहीं कह पाते है। हालांकि, होना तो यह चाहिए कि हम अपने कानूनी अधिकारों को जानते हों और उस पुलिस वाले को यह बतला दें कि आपका इस तरह व्यवहार उचित नहीं। तो आपको ऐसे कानूनों के बारे में बताते हैं जो आपको ज्ञात होने ही चाहिए। इनको जान लेने के बाद आप कानूनी तौर पर गलत और सही का अंतर समझ पाएंगे और अपने साथ दूसरे नागरिकों को सुरक्षा और जागरूकता देंगे।

गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा...

भारतीय कानून के मुताबिक, देश में कोई भी कंपनी गर्भावस्था के दौरान किसी महिला कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर कार्रवाई का प्रावधान है।

टॉयलेट में पानी मुहैया कराना...

भारतीय कानून के मुताबिक देश में सारे होटलों को बिना किसी शुल्क के टॉयलेट में पानी मुहैया कराना होगा। ऐसा न करना कानूनन अपराध है।

गिरफ्तारी के दौरान अपराध जानने का अधिकार...

किसी भी शख्स को गिरफ्तारी से पहले यह जानने का अधिकार है कि उस पर क्या आरोप लगे हैं। साथ ही यह भी कि किस आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है ?

महिला कांस्टेबल है जरूरी...

पुलिस किसी भी महिला को बिना महिला पुलिस कांस्टेबल के हिरासत में नहीं ले सकती। यहां तक कि घर में दबिश देने के दौरान भी महिला कांस्टेबल होनी जरूरी है।

महिला को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता..

पुलिस किसी भी महिला को सुबह होने से पहले और सूर्यास्त के बाद कानूनन गिरफ्तार नहीं कर सकती।

बेटा-बेटी का हक बराबर है...

पैतृक संपत्ति में बेटों के साथ-साथ बेटियों का भी बराबर हक होता है। बेटियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

बलात्कार पीड़िता को आजादी...

बलात्कार और यौन हिंसा की शिकार महिला को स्वतंत्रता है कि वो पुलिस स्टेशन जाने के बजाय घर पर ही अपना बयान दर्ज करा सकती है।

गाड़ी चलाते वक्त सारे कागजातों की ज़रुरत नहीं...

ऐसा जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी या दोपहिया चलाते वक्त सभी असली कागजात साथ रखें। ड्राइविंग करते वक्त लाइसेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट असली होने चाहिए। इंश्योरेंस और कार के RC की फोटो कॉपी भी चल जाएगी। इसके लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याऐं सादर आमंत्रित है। आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप वर्मा अगले अंक में देंगे। प्रश्न हमारी मेल आई डी पर पूछे जा सकते है।

मोतियाबिंद

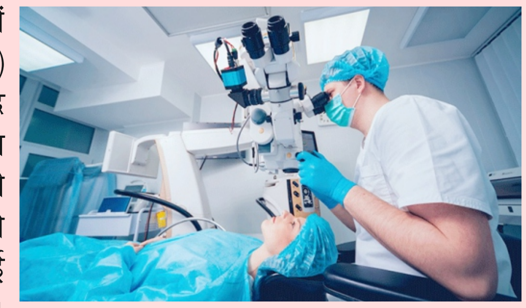

मोतियाबिंद को अंग्रेजी में कैटरेक्ट (cataract) कहा जाता है। मोतियाबिंद आँखों की वह समस्या जिसमें धीरे-धीरे आँखों की रोशनी में धुंधलापन आने लगता है जिससे दिखाई देना कम हो जाता है। मोतियाबिंद की बीमारी जन्मजात भी हो सकती है। मोतियाबिंद एक आँख में भी हो सकता है या फिर दोनों आँखों में भी हो सकता है। आम भाषा में कहा जाए तो आँखों के लेंस के ऊपर एक तरह की परत का जम जाना, इसके कारण आँखों की रोशनी धीरे-धीरे कम हो जाती है।

मोतियाबिंद का कारण क्या है?

- बढ़ती उम्र
- डायबिटीज की समस्या
- आंखों पर देर तक सूरज की रोशनी पड़ना
- आंख में किसी तरह की चोट या सूजन होना
- धूम्रपान का सेवन
- अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के संपर्क में आना
- रेडिएशन थेरेपी
- अनुवांशिक
- **मोतियाबिंद के क्या लक्षण होते हैं?**
- आँखों से धुंधला या स्पष्ट न दिखाई देना।
- शाम होने के बाद देखाई देने में मुश्किल होना।
- दो दिखाई देना।
- रोशनी के प्रति संवेदनशीलता।
- रंगों को पहचाने में उलझन-
- **मोतियाबिंद कितने प्रकार के होते हैं?**
- सेकेंडरी मोतियाबिंद
- टॉमेटिक मोतियाबिंद -
- कन्जेनिटल मोतियाबिंद -
- रेडिएशन मोतियाबिंद
- **मोतियाबिंद से किस तरह बचाव किया जाए?**
- समय पर आँखों की जाँच -
- खान-पान का ध्यान -
- चश्मा -

रोग - अगर आपको मधुमेह,रक्तचाप आदि जैसी समस्या है तो नियमित रूप से डॉक्टर से जाँच करवाते रहें।

नशा- किसी भी तरह का नशा शरीर को नुक्सान पहुंचाता है इसलिए जल्द से जल्द नशे का सेवन बंद कर दें।

मोतियाबिंद का इलाज

मोतियाबिंद का इलाज मरीज की दृष्टि पर निर्भर करता है क्योंकि किसी - किसी केस में चश्मे के नंबर लेंस को बदल कर भी इलाज संभव है। यदि मोतियाबिंद का स्तर बढ़ जाए तो सर्जरी की जाती है।

डॉ0 के आर शांडिल
द रीव क्लिनिक, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें: hem.raj@iirdshimla.org

पर्सनेलिटी प्रोफाइल साइकोमेट्रिक टेस्ट

पर्सनेलिटी प्रोफाइल साइकोमेट्रिक टेस्ट एक नयी टेस्ट विधि है। भविष्य में इस टेस्ट के और अधिक बढ़ने की संभावना है क्योंकि यह उन संस्थाओं के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है, जो अपने कार्य के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। एक पर्सनालिटी प्रोफाइल टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट की श्रेणी में आता है। पर्सनालिटी प्रोफाइल टेस्ट नियोक्ता को यह पता लगाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है कि क्या कैंडिडेट के पास जॉब की जरुरी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है अथवा नौकरी के लिए आवश्यक स्किल्स है या नहीं। नियोक्ता आमतौर पर उम्मीदवार में उन व्यवहारों की तलाश करता है जो नौकरी प्रोफाइल में महत्वपूर्ण होता है। इससे नियोक्ता को कैंडिडेट के पर्सनालिटी से जुड़े लक्षणों को समझने में भी मदद मिलती है। वस्तुतः इस इस टेस्ट के जरिये विभिन्न परिस्थितियों में उम्मीदवार द्वारा लिए गए त्वरित निर्णय तथा उपलब्ध सूचनाओं का सही उपयोग किये जाने की कला एवं ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। उम्मीदवार को कई परिस्थितियों में से एक को चुनकर उससे सम्बंधित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। उसके उत्तर के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। साथ ही परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था अथवा नियोक्ता के मानकों के अनुसार उम्मीदवार उपरोक्त जॉब के लिए उपयुक्त (सही) है या नहीं इस पर विचार किया जाता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में उम्मीदवार की परीक्षा तीन स्तरों पर ली जाती है। पहला, एबिलिटी टेस्टिंग, एप्टीट्यूड टेस्टिंग और पर्सनालिटी असेस्मेंट। एक तरह से इस टेस्ट के जरिए कंपनियां और संगठन संभावित कर्मचारी की काम और संस्थान के संबंध में व्यवहार की अनुकूलता को परखने की कोशिश करते हैं इसमें एक कर्मचारी की सोचने - समझने की क्षमता, टीम के रूप में काम करने की योग्यता और उम्मीदवार की निजी वरीयताओं को जांचा और परखा जाता है। एबिलिटी टेस्ट में एक तरह से सामान्य क्षमता की जांच होती है, जिसमें संख्यात्मक, मौखिक, गैर - मौखिक और स्थान संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जाता है। रही बात पर्सनालिटी प्रोफाइल टेस्ट की तो इसमें उम्मीदवार के कार्य संबंधी व्यवहार की जांच की जाती है। पर्सनेलिटी प्रोफाइल टेस्ट के जरिये उम्मीदवार जिस क्षेत्र के लिए आवेदन कर रहा है और जिस परिवेश में उसे काम करना है, उस संबंध में उसके व्यवहार की अनुकूलता को परखा जाता है। आपको बता दें कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की चुनाव प्रक्रिया में उन्हीं उम्मीदवार का साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होता है जो कि सब्जेक्ट नॉलेज में पास हो चुके होते हैं। इस टेस्ट के जरिए एम्प्लॉयर को उम्मीदवार के व्यक्तित्व से जुड़े पक्षों को समझने में मदद मिलती है।

साइकोमेट्रिक पर्सनेलिटी प्रोफाइल टेस्ट में सही या गलत उत्तर के विषय में न सोंचे

पर्सनेलिटी प्रोफाइल टेस्ट में कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर अपनी सूझ बूझ तथा अपने अन्दर की

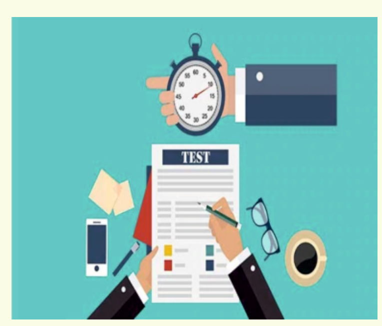

गट फीलिंग के आधार पर दें। कभी भी बनावटी या देखा देखी के आधार पर उत्तर नहीं दें। सबके सोचने, समझने तथा अनुभव करने का तरीका अलग होता है। इसलिए अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर सही गलत का विचार करते हुए अपना उत्तर देने का प्रयास करें। आम तौर पर ऐसे प्रश्नों के लिए सीमित निर्धारित समय सीमा होती है ताकि आप तत्काल सहज जवाब दे सकें और प्रश्नों के बारे में बहुत अधिक न सोंच पाएं।

कुछ लोकप्रिय पर्सनेलिटी प्रोफाइल साइकोमेट्रिक टेस्ट

यूँ तो हजारों टाइप के पर्सनेलिटी प्रोफाइल साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं लेकिन आजकल दो मुख्य रूप से प्रचलन में हैं-

- मायर्स - ब्रिग्स
- फेरो - बी

इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्सनेलिटी प्रोफाइल साइकोमेट्रिक टेस्ट एक नयी टेस्ट विधि है। भविष्य में इस टेस्ट के और अधिक बढ़ने की संभावना है क्योंकि यह उन संस्थाओं के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है, जो अपने कार्य के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल यह बहुत सारी संस्थाओं के लिए केवल क्वालिफाइंग है लेकिन भविष्य में इसमें प्राप्त होने वाले नंबरों को अंतिम सूची में जोड़ा जा सकता है। इसलिए ईमानदारी से इस परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के जवाब दें। इस टेस्ट के लिए किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

Why should a Government with Majority have Fear?

The recent case of Vidhan Sabha on leasing out prominent HPTDC properties in Himachal created a different impression on the governance, besides leaving a question whether a government with the absolute majority should react so lightly to "invite" humiliation.

As per the news and reports, the Department of Tourism of Himachal reportedly posted EOIs on a website promoting investment in the state for leasing out the hotels in some tourist destinations to private parties. On this, the opposition party protested in Vidhan Sabha and levelled charges against the government for selling public assets. The Chief Minister, who is heading the Tourism Department as well, revealed his ignorance on the same and declared to take necessary action on the matter. This issue ended with the withdrawal of the Department from the then Additional Chief Secretary (Tourism) and removal of the EOIs from the website concerned. This is all about this story...

Now, I am coming to my present experience with HPTDC's hotel and its management; about four months back, I had a chance to stay in HPTDC's property in Parwanoo. I checked different rooms and finally opted for the best suite available with the hotel and found the conditions highly pathetic.

The walls of my suite appeared so dull as if waiting for a decade for getting the varnish done to get rid of visible spots. The marching of cockroaches on "ancient" and unattractive furniture, curtains, etc., disturbed a bit. And while checking out I gave a detailed note on the feedback register on the second day with special mention to expect a call back from the higher authorities; the call is still awaited. I was briefed that the authorities didn't pay attention to that property, it might be due to it being a loss-making unit.

The second instance of relevance in some different context is the management of Himachal Bhawan in New Delhi, which serves well in terms of room service and other facilities that a guest can expect for the price they pay. The food system is very basic but comparatively cheaper. This year I noticed in the menu board "Himachali Thali" which included sepu badi, madra, rice, roti and a sweet dish. About six months ago, I tasted challai kheer as part of Himachali Thali, which has been now replaced with boondi-meetha, full of sugar and ready to make people diabetic. No improvement in the food system has been noticed there for decades and on a 5-minute drive from Mandi House, there is Andhra Bhawan in Delhi where people from all over India visiting Delhi stand in a queue to buy lunch coupons in the canteen. On average, more than 1,000 people are served every day there and the institute is being run profitability by the management for years.

But we have been unable to learn to make the venture profitable, attract more people towards our services and promote our Pahari dishes with optimum cost.

I could not understand the logic or intention behind serving the food at cheap prices or making the rent economic especially when 90% occupancy is of the government functionaries, who besides being capable of affording the services even at a marginally high price, even claim their TA/DA from the government.

There might be many loss-making units in Himachal where HPTDC is struggling for sustainability with the conventional weak management. And there are possibilities that the government might have thought to involve private players to sustain the business and in return get handsome revenue. When we find something difficult to handle, why shouldn't we take others' support? And if the government tried to do the same, what was wrong there?

Being in government, it is not judicious to run the commercial ventures at a loss, but it is important to make optimum utilization of resources created out of the public money.

The government could have firmly come up with its plan and justification on a sound footing to convince the opposition as the condition of these properties suffered the same fate during the tenure of the opposition party as well (if the reason was to overcome continued loss and if the posting of the EOI was not a mistake). The matter could have been dealt with confidence and more strength, and the ACS concerned would not have faced withdrawal of Department.

Today, everyone understands that nothing moves in the government system without proper approval and consent at the required level. If we take decisions genuinely, we need to have the courage to defend them too.

And we wish to play very safely, though different strategies can be adopted to involve reasonably genuine opposition representatives in recommendations on such crucial issues. Such practices, when well thought out and implemented, may help in reducing the criticism on the floor.

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

ABSOLUTE UNIFICATION OF INDIA

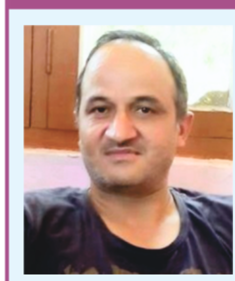

We should not allow blunders of past ruin our present and future permanently. Political parties, for fear of disrepute, are always reluctant to rectify past mistakes. Nehru, the infallible would himself have easily abrogated 370 before joining the great majority, had he not made it Petronius' Sybil by taking the issue to UN. Blaming Nehru for everything despicable happened to India will not only be wrong but also downplaying all other achievements of this statesman. Declaration of ceasefire in a hope to subdue Pakistani claim in future on Kashmir was an erroneous idea. Ideally, congress should have conceded to this fact earlier to avoid consistent decline as a national party. Understandably, Nehru had very little to choose from. Want of tested friends unlike during subsequent conflicts with Pakistan, Nehru prevented all possible escalations on this issue. Without any margin for error Nehru judiciously consolidated Indian position to LOC leaving little scope for further aggravation of conflict. To add, and rightly so he did not want a strong uprise by disturbing present demography of Kashmir minus POK as Muslim majority Pakistan sympathisers would have made it difficult for India to tame separatists. As Nehru saw plebiscite to be a likely possibility, he thought Indian side of Kashmir to be with demographic balance and hopeful to win Muslim favour by insertion of 370. If 370 was an inevitable evil, 35A was first undemocratic insertion into Indian constitution which never was tabled on the floor of the house. Nehru's incessant ambition to evolve as global torch bearer of peace led him sign Indus treaty imprudently against national interest. He served unsatiating Pakistani table by offering bulk of river treasures to Pakistan whereas major parts of India suffered famines and scarcity of water. But worst was yet to come. If 370, 35A or Indus treaty were blunders, Shimla agreement of 1972 between Pakistani premier Mr Bhutto and Prime Minister of India Mrs Indira Gandhi was a sin. A war marked by surrender of over ninety thousand Pakistani soldiers, largest in recorded history, Indira Gandhi setting aside the sacrifices of Indian army signed a toothless accord without reclaiming Pakistan occupied Kashmir. Again let's take it for those rare exceptions but it was possibly nothing else but appeasement politics that prevented Govt revoking 370 during Hindu exodus from Kashmir in 1989 and afterwards. Especially when Islamization was at its peak and Abdullah had already changed names of around 2500 native villages to Islamic names. In fact, Kashmir has never been an issue of self-determination. This has just been an attempt of Islamic fundamentalists to annex valley to Pakistan on religious homogeneity. But implementing unconstitutional provisions like 370 and 35A to win Muslim support in India's favour detached them even further. In fact we do not want to acknowledge or address the real problem. Muslims never wanted to live in non-muslim majority countries. India was divided on religious lines. It was geographical disconnectivity of Silchur, Junagarh or Hyderabad to Pakistan that forced them merge to India without much confrontation. It is false narrative that Hindus wanted secular India especially after Pakistan was carved out of greater India on religious lines. This sense of betrayal among Hindus led to assassination of Gandhi. Article 370 never allowed people of valley integrate to rest of India. Separatists and politicians of Jammu & Kashmir misused this tool for their individual gains. The state was kept incarcerated for more than seven decades. India is the only country where people are systematically taught to forget their own glorious heritage and glorify the histories of invaders. This absurdity is called 'secularism', a word forced unconstitutionally into Indian constitution during years of emergency. Eventually 370 is a thing of past now. But discomfort and desperation of opposition parties on this issue will sure make them behave irresponsibly and against the interest of the nation. Kashmir issue has not been resolved permanently. In fact the issue will remain unresolved as long as Pakistan continues fueling religious sentiments of Kashmir. The fundamental difference that changes the scenario of now and before in Kashmir is that separatists of valley lose their political patronage completely. The quasi autonomous administrative structure of Kashmir that offered them a leverage to manipulate system to their advantage has been put to a complete halt now. No doubt the protests for separate identity will continue to float but at least law of land will take its course. Culprits will be made accountable thus discouraging unlawful activities in Kashmir. India has stepped into a new era today and any voice of protest threatening Indian integration should be crushed with iron fist. Present dispensation has shown decisive character but will be a challenge for new governments ruling India. We have created a history and India today stands as tall as Himalayas. On papers India had won freedom on 15th August 1947 but on the ground the ancient plundered land was not unified in a nation until 5th August 2019. In its true sense we adopted our constitution only now thus making all Hindus, Muslims or Sikhs as equals before the law without falling prey to appeasement politics for fear of disintegration. India yawns into a new dawn of unified nation.

Kamlesh Sharma, Shimla (HP)
(Guest Writer) 9817540956

चुनाव जीतने के बाद आम आदमी नहीं रहते माननीय

वी० आई० पी ० श्रेणी में आजीवन रहने का सौभाग्य प्राप्त है

प्रथम विधानसभा में 500 मानदेय से आज 55,000 की ऊंची छलांग का वेतन

अनेक भत्तों सहित एक विधायक को मिलते हैं 2 लाख 10 हज़ार प्रतिमाह, पेंशन सुविधा भी

एक बार लाल बहादुर शास्त्री से पत्रकारों ने पूछा कि आपकी पार्टी तो आज भारत की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित राजनैतिक दल है और आप उसके अध्यक्ष भी हैं । लेकिन मीडिया में अपका नाम कहीं नहीं आता है और इसका श्रेय कोई और ही ले जाता है। इस पर पत्रकार से शास्त्री जी ने कहा कि आगरा में ताजमहल को देखने के लिए भारत ही नहीं वरन् पूरी दुनिया से लोग आते हैं। लोग आते हैं और ताज़महल की नक्क़ाशी, चित्रकला, बनावट और संगमरमर की भरपूर प्रशंसा करते हैं। कोई भी यह नहीं कहता कि यह ताजमहल जिन पत्थरों पर खड़ा है वो गहन अंधेरे में ज़मीन के नीचे पड़े हैं । उन नींव के पत्थरों पर ही यह पूरा ताजमहल खड़ा है। शास्त्री जी ने बोला कि मैं भी उस पत्थर की तरह हूं और पार्टी के लिए गुमनाम रहकर सेवाओं को देने में विश्वास रखता हूं। ऐसा व्यक्तित्व क्या हमारे माननीयों में आज देखा जा सकता है? ऐसे उदाहरण अब बिरले ही हैं। ये वो नेता थे जिनको मानदेय और अन्य भत्तों के नाम पर बेहद कम सुविधा सरकारी तौर पर उपलब्ध थी। आम लोगों में एक नेता की छवि विशुद्ध समाजसेवी और समर्पण की भावना से स्वेच्छा से सेवाऐं देने तक सीमित थी । इस सादे जीवन पर महात्मा गांधी विचारों का भी प्रभाव था। लेकिन धीरे - धीरे स्थितियां बदलती गई और हमारे टोपी वाले नेता जींस-पैंट में कॉस्मेटिक होते गए। सिर्फ पहनावे से ही नहीं, सोच और कर्म का व्याकरण भी तेज़ी से बदलता गया। आज राजनीति और माननीयों की श्रेणी आम आदमी की नहीं रही अपितु इसे अति विषिश्ट और अति महत्वपूर्ण श्रेणी का दर्ज़ा हासिल है। हो भी क्यों न? आम आदमी का वोट इतना सस्ता थोड़ा ही होता है कि वो किसी आम आदमी जैसे दिखने वाले नेता को अपना वोट डाले और वो आम से बेहद ख़ास न हो जाए ! यही तो कमाल है यहां के पत्थर तोड़ते हुए, खून-पसीना बहाने वाले मज़दूर के हाथों की उंगली का कि पत्थर को तराशे तो वो मंदिर में रखने के बाद भगवान हो जाए और उसी उंगली पर नीली स्याही लगने के बाद किसी आम को बेहद खास बना कर राजा की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है जिसे हम अपने माननीय कहते हैं।

RTI अनुबंध "ख"

विधायकों के वेतन वृद्धि से सम्बन्धित हुए संशोधनों का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या:	वर्ष	मासिक मूल वेतन
1	1971	500/-
2	1992	1000/-
3	1994	1500/-
4	1998	2500/
5	2006	8,000/-
6	2007	10,000/-
7	2010	15,000/-
8	2012	20,000/-
9	2013	30,000/-
10	2016	55,000/

Scanned with CamScanner

मानदेय से वेतन तक चौंकाने वाली वृद्धि

जब सूचना के अधिकार में सूचना की उपलब्धता हुई तो कई ऐसी बातें ज्ञात हुई जो चुल्हे में फूंक मारती गांव की चाची और बूढ़ी मां के अलावा मनरेगा में दिहाड़ी की आस में पसीना बहाते हुए मज़दूर को भी पता होना ही चाहिए कि जिसे वो चुनते हैं वो आख़िर क्या करते हैं, कैसे रहते हैं और विधानसभा तक आते-आते कितनी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं ? हालांकि यह जानकारी एक भाग में ही प्राप्त हुई दूसरी जानकारी के लिए अलग विभाग को प्रेषित किया गया जिसमें कुछ अन्य पहलुओं की जानकारी प्राप्त होना शेष हैं।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चयनित विधायकों को सचिवालय द्वारा कुल 2 लाख 10 हज़ार रुपये मासिक वेतन भत्तों के साथ दिए जाते हैं । इसमें मूल 55,000/प्रतिमाह, विधानसभा क्षेत्र भत्ता 90,000/प्रतिमाह, दूरभाष / टेलिफोन भत्ता 15,000 / प्रतिमाह, कार्यालय भत्ता 30,000 / प्रतिमाह, डेटा ऑपरेटर भत्ता 15,000 / प्रतिमाह शामिल है। दैनिक भत्ता 1800 / प्रतिदिन के हिसाब से माननीय लेते हैं। जिसमें असेंबली की बैठक में शामिल होने के लिए आना - जाना हो, बैठक में शामिल होने के लिए एक दिन पूर्व और एक दिन बाद में मिलने वाला भत्ता शामिल है।

यात्रा भत्ता भी अलग-अलग स्तर पर माननीयों को प्राप्त होता हैं। अपनी कार से यात्रा पर 18/ रुपये प्रति किलोमीटर, बस, टैक्सी या निजी वाहन से 2/ प्रति कि.मी. मिलता है। इतना ही नहीं... किसी भी विधायक को एक वित्तिय वर्ष में 2,50,00/- यानि अढाई लाख रुपये सिर्फ यात्रा के लिए मिलते हैं। यानि सदस्य किसी भी यात्रा प्रारुप को अपनाकर यात्रा कर सकते है। ट्रेन, कार या हवाई जहाज से यात्रा कर सकता है और उनके साथ उनका परिवार भी इस दायरे में आते हैं। बस टिकट दिखाकर अपना यात्रा का खर्चा ले सकते हैं। सदस्य को 25,000/ रुपये अग्रिम राशि के रुप में भी मिल जाते हैं। अपनी यात्रा के दौरान माननीय को यदि हिमाचल सरकार का आवास नहीं मिल पाता है तो वो किसी भी बड़े होटल में रह सकते हैं जिसके लिए उन्हें 7500/ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं।

घर पर लगे दूरभाष का खर्चा भी आम जनता ही उठाती है। विधायक सदन में सभी विधायकों के लिए आवास की पूर्ति की जाती है जिसमें 15,00/वेतन से कटते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा के चयन के समय विधायक को कुल 500/ मानदेय मिलता था। ध्यान देने वाली बात ये है कि उस समय इसे मानदेय कहा जाता था। लेकिन एक जन प्रतिनिधि यानि विधायक को जिस आदर और सम्मान के साथ देखा जाता था वो एक सामाजसेवी के लिए बड़े अदब की बात होती थी। क्योंकि नेता की उस समय जो छवि थी वो एक समाजसुधारक की ही होती थी। 1971 में मासिक

मूल वेतन 500/ रुपये था, 1992 में वो 1000/ हो गया। 1994 में 1500/, 1998 में 2500/, 2006 में इसे 8000/ कर दिया गया । एक वर्श के बाद ही 2007 में इसे और बढ़ाकर 10,000/ किया गया। 2010 में सीधा 15,000/, 2012 में 20,000/, 2013 में इसे 30,000/ और फिर 2016 में सारी ही ग़रीबी पर चादर डालते हुए इसे 55,000/ कर दिया गया। यहां ग़ौर करने वाली बात ये है कि 2006 के बाद तो ऐसा प्रतीत होता है कि विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा वेतनमान में वृद्धि का ही हो।

विधायक बनाने वाली जनता से तो पूछो कभी

यह एक ऐसा मसला है जिस पर जनता की ओर से कभी भी सहमति नहीं मिल सकती है लेकिन विधायकों द्वारा कभी विरोध नहीं किया जा सकता है। विधानसभा में मुद्दों पर एक - दूसरे से भिड़ने वाले सभी राजनैतिक दलों के विधायक वेतनमान में वृद्धि के मसले पर एक ही स्वर और बाहों में बाहें डाल कर समर्थन में आ जाते हैं और खूब ज़ोर-शोर से मेज थपथपाकर समर्थन करते हैं। क्या इनका नैतिक कर्तव्य नहीं कि इस मुद्दे को जनता की राय के लिए सामने लाया जाना चाहिए। एक सर्वे करवाकर देख लो... जनता की राय इस विषय पर स्पष्ट हो जाएगी। इतनी वेतनमान वृद्धि तो रात-दिन अध्ययन करके संघर्ष करके लगे कर्मचारियों को नहीं मिलती है। उनके लिए तो सरकार के पास चुटकी भर दाने ही होते हैं तो बड़ी मांग उठने या संघर्ष करने के बाद बंटते हैं। लेकिन माननीयों को तो बस विधानसभा में प्रस्ताव लाना होता है और फिर एक बार मेज थपथपानी होती है । हो गया कल्याण। ये विषय उस जनता से अलग कैसे हो सकता है जो एक आम आदमी को वोट देकर, चयनित कर विधानसभा भेजती है और फिर देखते ही देखते वो आम आदमी से ख़ास या विशेष होता चला जाता है । एक सीमा तक तो यह ठीक है लेकिन ये सफर भी तो मात्र 5 वर्ष का है। पुनः विजयी हो गए तो ठीक, नहीं तो पेंशन पक्की है और अन्य वीवीवीआईपी सुविधाओं का पिटारा तो आजीवन खुला ही रहता है। किसी भी जन प्रतिनिधि का भाग्य जनता की राय के लिए जनता के बीच ही आनी चाहिए। यानि जनता तय करे क्योंकि उसी की अनुकंपा के कारण माननीय बनने और सुविधाओं को प्राप्त करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है ।

RTI अनुबंध (ग)

पूर्व विधायकों की पैंशन में किए गए संशोधन का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र० सं०	वर्ष	मूल पैंशन की राशि
1.	31.12.1976	300/-
2.	02.11.1991	500/-
3.	14.05.1994	1000/-
4.	24.08.1998	1500/-
5.	17.05.2005	5000/-
6.	19.09.2009	10000/-
7.	16.09.2010	14000/-
8.	09.05.2012	18000/-
9.	21.09.2013	22000/-
10.	10.05.2016	36000/-

Scanned with

बस एक बार विधायक और वीआईपी पेंशन की गारंटी

ये मसला पांच वर्ष का नहीं है। एक बार विधायक बनने के बाद दुबारा न जीत पाने या चुनाव न लड़ने के बाद भी माननीय पेंशन के हकदार हो जाते हैं। अगर आरटीआई में प्राप्त सूचना की बात करें तो 31.12.1976 को मूल पेंशन 300/ थी, 2.11.91 को 500/, 14.5.94 में यह 1000/ हो गई। 24.8.1998 को 1500/, 17.5.2005 को सीधा बढ़कर मूल पेंशन 5000/ हो गई। 19.9.2009 को डबल होकर 10,000/, 16.9.2010 को 14000/, 9.5.2012 को यह 18,000/, 21.9.2013 को 22,000/ और 10.5.2016 को बेइंतहाशा वृद्धि के साथ मूल पेंशन 36,000/ हो गई। यह मूल पेंशन है। यानि कुल मिलाकर आंकड़ा कितना है यह स्पष्ट समझा जा सकता है। यहां सवाल यह है कि एक कर्मचारी जो अब नौकरी में चयनित होकर उम्रभर सेवाऐं देता है, उसे तो पेंशन का हकदार नहीं बनाया गया है और उसके इस अधिकार पर हथौड़ा चला दिया गया। लेकिन एक व्यक्ति जो राजनीति में मात्र इसलिए आता है कि उसे जनता की सेवा का पांच वर्ष के लिए अवसर मिले, उसे भारी भरकम तनख़्वाह के साथ पूर्व विधायक बनने पर अच्छी पेंशन का तोहफा मिल जाता है। इतना ही नहीं आगामी कार्यकाल के लिए 1000/ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रत्येक वर्ष मूल पेंशन में वृद्धि के रुप में प्रदान की जाती है। ऐसा भेदभाव और संस्कृति सबके सामने ही है। इसलिए समाज में एक संदेश तो साफ ही है कि एक बार बस कैसे भी विधायक बनो, फिर चाहे उम्र भर कुछ न करना पड़े, वीआईपी कोटे से जीवन सुरक्षित हो जाता है। ऐसी बातें आम जनता करती तो है किंतु जनता तो जनता है, वो न तो वीआईपी है और न ही उसकी गिनती बुद्धिजीवियों की

RTI में खुलासा

2. विधायकों को इस सचिवालय द्वारा मु0 2,10,000/-रू0 मासिक वेतन (भत्तों सहित) प्रदान किया जाता है
3. विधायकों को दिये जाने वाले समस्त मासिक भत्तों की प्रति अनुबंध "क" पर संलग्न है ।
4. हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधान सभा के चयन के समय विधायक को मु0 500/-रू0 मानदेय मिलता था ।
5. विधायकों के वेतन की वृद्धि से सम्बन्धित संशोधनों की सूचना अनुबंध "ख" पर संलग्न है ।
6. वर्तमान में एक विधायक को मु0 2,10,000/- वेतन (अन्य भत्तों सहित) प्रदान किया जाता है ।
9. सूचना ग्रामीण विकास विभाग, हि0 प्र0 सरकार से सम्बन्धित है ।
10. विधायक को पूर्व विधायक होने पर प्रारूपानुसार प्रथम कार्यकाल हेतु मूल पैंशन मु0 36,000/- रू0 तथा आगामी कार्यकाल के लिए मु0 1000/-रू0 की अतिरिक्त राशि प्रत्येक वर्ष मूल पैंशन में वृद्धि के रूप मे प्रदान की जाती है ।
11. विधायक को पूर्व विधायक होने की स्थिति में देय पैंशन में आरम्भ से आज तक हुए संशोधनों की सूचना अनुबंध "ग" पर संलग्न है ।
12. विधायक केवल जनप्रतिनिधि होने के कारण वी0आई0पी0 की ही श्रेणी से सम्बन्धित हैं ।
13. विधायक बनने के लिए किसी भी नागरिक को सम्बन्धित राज्य का नियमानुसार स्थाई निवासी होना आवश्यक है तथा इसके अतिरिक्त अन्य जानकारियां उक्त द्वारा ही नामांकन भरते समय स्वयं स्तर पर निर्वाचन विभाग को निर्धारित प्रपत्र पर देनी होती है जिनका ब्यौरा उक्त विभाग में ही उपलब्ध रहता है ।

Scanned with CamScanner

श्रेणी में हो पाती है। इसलिए उसकी बात को सुनना भी क्यों ? जनता एक बार नहीं तो 10 बार बोलेगी...फिर शहर-गांव का मुद्दा बदल जाऐगा। बहस बदल जाऐगी। और व्यवस्था पर चर्चा किसी और ही दिशा में चली जाऐगी। विधायक केवल जनप्रतिनिधि होने के कारण वी०आई०पी० श्रेणी में आते है। आम लोगों के साथ और आम से ख़ास हो जाने पर ये जो विभाजन सामने दिखता है उस पर मंथन तो आवश्यक है। बेझिझक और बिना कोई मापदंड के बेहिसाब वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं को जनहित में हमारे माननीयों को ही स्वीकार करने में आपत्ति होनी चाहिए जो कि शायद असंभव सी बात है। एक बार पूर्व मुख्यमंत्री और साहित्यकार शांता कुमार ने इस पर विरोध भी किया था जिसकी जनता ने खूब सराहना की थी। लेकिन इस बात को स्वीकार करना होगा कि जहां सरकारी रोजगार नहीं है उस घर में एक भी रोजगार नहीं मिल पाता और जिस घर से सरकारी रोजगार है वहां सभी नौकरीशुदा कैसे हो जाते हैं? और जो सरकारी रोजगार के सामान्य प्रारुप में दाखिल होता है उसे पहले अनुबंध पर भी नहीं रखा जाता है। कुछ वर्षों के बाद उसे अनुबंध पर किया जाता है और फिर दिहाड़ीदार से नियमितिकरण होता है वो भी बिना पैंशन की करार के साथ। इस भेदभाव को राजनीति में कोई भी जननायक नहीं बोल पाता है और प्रयास तो दूर की बात है। यहां ऐसे भी लोग विधानसभा में पहुंचे जो कभी ख़्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन अब उनके ठाठ और जीवनशैली राजयोग से कम नहीं है। ये अलग बात है कि जनता के लिए तो पांच वर्ष के बाद वोट डालने की प्रतीक्षा के अलावा और कुछ नहीं हासिल होता है न ही होगा! आज़ादी के लिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि ने प्राण तक न्यौछावर कर दिये थे और इसी आशा के साथ की हिन्दुस्तानी गुलामी से मुक्त होकर एक स्वतंत्र एवं एक समान भारत की नींव रखी जाऐगी। लेकिन एक डर तो उन्हें भी था.... जो आज सच हो चुका है। अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है और ग़रीब और अधिक ग़रीब......। ऐसे में हमारी विधानपालिका को सोचने की आवश्यकता है कि दूध में पानी तो मिलाया जा सकता है लेकिन पानी में दूध नहीं....

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

बंडारु दत्तात्रेय हिमाचल के राज्यपाल नियुक्त कलराज मिश्र राजस्थान स्थानांतरित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल के 29वें राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 सितंबर को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन ने वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। मिश्र हिमाचल में 41 दिन तक ही राज्यपाल रहे और अब वह राजस्थान में कल्याण सिंह की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। दत्तात्रेय आंध्र प्रदेश से भाजपा के वरिष्ठ नेता है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वह केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे। इसके अलावा वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रह चुके हैं। दत्तात्रेय कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए आपातकाल के दौरान जेल भी गए थे।

मुख्यमंत्री ने निवेश आकर्षित करने के लिए ठोस मीडिया प्लान पर बल दिया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में अपेक्षित औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि मीडिया प्लान लक्ष्य एवं क्षेत्र पर आधारित हो। मुख्यमंत्री राईजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के संदर्भ में स्क्वेयर मीडिया लिमिटेड की ओर से मीडिया प्लान पर एक प्रस्तुतिकरण की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया प्लान का उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध व्याप्त निवेश क्षमता को निवेशकों के सम्मुख प्रस्तुत करना है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि मीडिया का समुचित उपयोग किया जाए। इसके माध्यम से प्रदेश की उपलब्धियों और गतिशील शासन को भी दर्शाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया अभियान का केन्द्र भारतीय एवं वैश्विक निवेशक समुदाय, प्रभावशाली व्यक्ति और आम आदमी होना चाहिए। जय राम ठाकुर ने कहा कि मीडिया प्लान के मुख्य बिंदु व आठ क्षेत्र होने चाहिए जिन्हें प्रदेश सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए निर्धारित किया है, इनमें एग्री-बिजनेस, उत्पादन एवं फार्मा, पर्यटन एवं आतिथ्य, हाइड्रो एवं नवीकरणीय ऊर्जा, वैलनेस एवं स्वास्थ्य देखभाल, आवास निर्माण व शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं कौशल विकास शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अतिरिक्त ऊर्जा है और यहां ऊर्जा दर भी न्यूनतम है। इसके अलावा व्यापार में सुगमता के मामले में भी यह राज्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तरी भारत व प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रों के साथ राज्य की क्नेक्टिविटी बहुत अच्छी है। राज्य में भूमि बैंक व शांत माहौल की सुविधा के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक वृद्धि की क्षमता मौजूद है।

100 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले स्कूलों में नहीं भरे जाएंगे इन शिक्षकों के पद

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में 100 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले मिडल स्कूलों में फिलहाल ड्राइंग मास्टर और फिजिकल एजूकेशन टीचर (पीईटी) के रिक्त पद नहीं भरे जाएंगे। 27 अगस्त को भाजपा विधायकों विनोद कुमार, जवाहर ठाकुर के सवाल पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि पहले हाई स्कूलों में पद भरना प्राथमिकता है। उसके बाद ही मिडल स्कूलों पर विचार किया जाएगा। भारद्वाज ने बताया कि 100 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले मिडल स्कूलों में डीएम और पीईटी के पद नहीं भरने का केंद्र सरकार ने कानून बनाया है। हिमाचल सरकार इस नियम का पालन कर रही है। उन्होंने बताया कि अगर किन्हीं मिडल स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 90 के आसपास होगी तो प्रदेश सरकार उपलब्ध बजट और शिक्षकों की संख्या के हिसाब से वहां भर्ती करने का विचार करेगी।

मुख्यमंत्री ने 7वीं आर्थिकी गणना का शुभारम्भ किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने देश में सभी आर्थिक प्रतिष्ठानों के विभिन्न परिचालन और संरचनात्मक पहलुओं पर विभिन्न जानकारी देने के लिए साख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा 2019 में संचालित 7वीं आर्थिकी गणना (7वीं ईसी) का शुभारम्भ किया। आर्थिक गणना भौगोलिक विस्तार, आर्थिक गतिविधियों के समूहों, ओनरशिप पैटर्न, परिसरों या निर्धारित परिसरों के बिना आर्थिक गतिविधियों में शामिल संस्थानों से जुड़े व्यक्तियों इत्यादि की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। 7वीं ईसी के संचालन के लिए एमओएसपीआई ने अर्थशास्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कार्यन्वयन एजेंसी सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसिज इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। सीएससी द्वारा शामिल किए गए गणनाकारों तथा सुपरवाईसरों को डाटा एकत्रित करने, सत्यापन, रिपोर्ट तैयार करने और प्रसार करने के लिए विकसित किए गए मोबाइल ऐप पर डाटा एकत्रित करने का प्रशिक्षण दिया गया है। सचिव वित्त, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और योजना अक्षय सूद, उप महानिदेशक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (फील्ड परिचालन प्रभाग) हिमाचल प्रदेश क्षेत्र और आर्थिक सलाहकार विनोद राणा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

हिमाचल को पोषण अभियान में मिले तीन राष्ट्रीय पुरस्कार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश को पोषण अभियान के अंतर्गत तीन राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार पोषण अभियान के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य, जिला, खण्ड और आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रदान किए गए। प्रदेश के लिए इन पुरस्कारों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने प्राप्त किया। महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक कृतिका कुलहारी और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश को तीन राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया था, जिनमें कन्वर्जेंस एवं कम्युनिटी मोबिलाईजेशन, आईसीडीएस - सीएएस और पोषण अभियान के अंतर्गत कुल प्रदर्शन शामिल थे। प्रदेश को इन पुरस्कारों के अंतर्गत 2.25 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के अंतर्गत बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मण्डी और किन्नौर जिला के कल्पा को कन्वर्जेंस पुरस्कार, शिमला शहरी खण्ड को पोषण अभियान के अंतर्गत खण्ड स्तरीय लीडरशिप एवं कन्वर्जेंस पुरस्कार जबकि इस अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार सोलन को मिला है। सोलन जिला को मिले पुरस्कार को उपायुक्त के.सी. चमन ने प्राप्त किया। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए महिला एवं बाल विकास को तीन राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तत्परता के साथ पोषण अभियान को क्रियान्वित कर रही है ताकि एक स्वस्थ एवं मजबूत राष्ट्र के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह ने भी इस शानदार उपलब्धि के लिए विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है।

हिमाचल में 9700 मेधावियों को मिलने वाले लैपटॉप के टेंडर रद्द

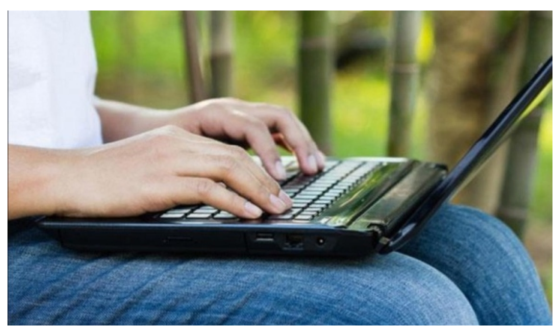

द रीव टाइम्स ब्यूरो

स्कूल-कॉलेजों के 9700 मेधावियों को श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत मिलने वाले लैपटॉप के टेंडर रद्द हो गए हैं। टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद के बीच जयराम सरकार ने 27 अगस्त को यह बड़ा फैसला लिया। अब नए सिरे से लैपटॉप खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। दो कंपनियों को टेंडर देने और खरीद के लिए पांच करोड़ का बजट बढ़ने से मामला विवादित हो गया था। 22 अगस्त को विधानसभा में कांग्रेस ने भी इसको लेकर खूब हंगामा किया था। इसी बीच सरकार ने लैपटॉप का रि - टेंडर करने का फैसला लिया है। लैपटॉप खरीद का जिम्मा राज्य इलेक्ट्रानिक निगम को दिया गया था। उच्च शिक्षा निदेशालय ने खरीद के लिए करीब 18 करोड़ का बजट निर्धारित किया था जबकि टेंडर में चुनी गई कंपनियों ने 23 करोड़ के बजट में लैपटॉप देने की बात कही।

कारपोरेशन ने लैपटॉप खरीद के लिए पहली बार दो कंपनियों का चयन किया। एल वन कंपनी को 60 फीसदी और एल टू कंपनी को 40 फीसदी सप्लाई आर्डर देने की बात कही गई। बजट बढ़ने से शिक्षा निदेशालय की मुश्किलें बढ़ गई थीं।

पावर प्रोजेक्टों से पीने और सिंचाई लायक नहीं रहा सतलुज का पानी

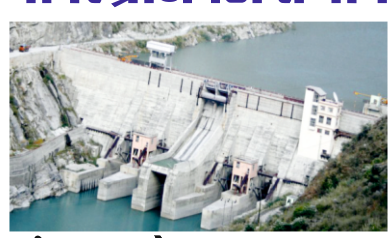

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में अवैज्ञानिक तरीके से बिजली परियोजनाओं का निर्माण करना पर्यावरण संतुलन और मानव जीवन के लिए घातक हो सकता है। परियोजना के निर्माण से न केवल वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, बल्कि जल प्रदूषण के साथ भूमि में प्रदूषण का सामान्य स्तर भी गड़बड़ाने लगा है। इसका खुलासा एक शोध से हुआ है, जिसकी रिपोर्ट अगले माह नौ से 13 सितंबर तक जर्मनी के बर्लिन में होने वाले यंग अर्थ साइंटिस्ट कांग्रेस में पेश की जानी है। राष्ट्रीय जीबी पंत संस्थान मौहल के वरिष्ठ वैज्ञानिक भीम चंद ने 2013 से लेकर 2018 तक किन्नौर जिले की शौंगटोंग और रामपुर बिजली परियोजना के प्रभावित क्षेत्र पर शोध किया है। रिपोर्ट में परियोजना निर्माण के दौरान बढ़े वायु प्रदूषण को भी दर्शाया है। वायु में पीएम - 10 की मात्रा 100 माइक्रोग्राम पाई गई है, जिसे सेहत के लिए काफी घातक माना जाता है। सतलुज के पानी की गुणवत्ता घटती जा रही है। नदी के पानी को मापने की विधि टरबीडीटी मीटर 30 एनटीयू (नफेलोमीटर टरबीडीटी यूनिट) से 150 एनटीयू तक पाई गई, जबकि पर्यावरण की दृष्टि से इसका पैमाना अधिकतम दस होना चाहिए। एनटीयू का स्तर असाधारण होने से सतलुज नदी का पानी पीने और सिंचाई लायक नहीं है। इस पानी से सिंचाई करने पर फसल पैदावार घटेगी। इसी तरह से भूमि प्रदूषण में नाइट्रोजन की मात्रा 130 से 210 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पाई गई, जो कृषि - बागवानी के लिए नुकसानदायक है। फसल के लिए भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा 224 से अधिक होनी चाहिए। यह परियोजना फिलहाल निर्माणाधीन है। वैज्ञानिक भीम चंद ने 412 मेगावाट की रामपुर जल विद्युत परियोजना के प्रभावित क्षेत्रों का शोध किया है। शौंगटोंग परियोजना में 2013–14 में वायु प्रदूषण की मात्रा पीएम – 10 की मात्रा 102.8 से 111.9 माइक्रोग्राम थी। साल 2015–16 में 107.3 से 119.3 माईक्रोग्राम हो गई। दोनों ही वर्ष मात्रा 100 माइक्रोग्राम की सीमा से अधिक है। वहीं तैयार हो चुकी रामपुर परियोजना के प्रभावित क्षेत्र में पीएम - 10 की मात्रा न्यूनतम 17.8 और अधिकतम 65.5 माइक्रोग्राम पाई गई है।

विद्यार्थी लाइव देख सकेंगे चंद्रयान – 2 की लैंडिंग

द रीव टाइम्स ब्यूरो

स्कूली बच्चे इसरो (इंडियन स्पेस रिसर्च अर्हगेनाइजेशन) के आसान सवालों के जवाब देकर चंद्रयान-2 की चंद्रमा पर लैंडिंग का लाइव टेलिकास्ट देख सकते हैं। इसरो के बंगलूरू सेंटर में चंद्रयान-2 का सात सितंबर को लाइव टेलिकास्ट का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इसरो के बंगलूरू सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चंद्रयान-2 की लैंडिंग देखने के लिए स्कूली बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके लिए इसरो ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू की है। भारत सरकार की MyGov.in साइट पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में देश भर के आठवीं से जमा दो तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हर राज्य के टॉप-2 बच्चों को इसरो में जाकर पीएम मोदी के साथ चंद्रयान-2 की चंद्रमा पर लैंडिंग का सीधा प्रसारण देखने का मौका मिलेगा। बच्चों में इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम में रुचि बढ़ाने के लिए यह प्रश्नोत्तरी शुरू की गई है। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान सहित चंद्रयान-2 से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उधर, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. प्रमोद चौहान ने बताया कि प्रश्नोत्तरी में हिमाचल के अधिक से अधिक बच्चें भाग ले सकें, इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के उच्च शिक्षा उप निदेशकों के माध्यम से स्कूल प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बच्चे वेबसाइट पर जाकर स्वयं प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकते हैं।

धर्मशाला में पहली बार कोहली की कप्तानी में उतरेगी टीम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में बतौर कप्तान विराट कोहली पहली बार मैदान में उतरेंगे। जबकि, धोनी के बिना टीम यहां पहली बार खेलने जा रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका टी-20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा के बाद जहां धोनी प्रशंसकों में मायूसी है, वहीं कोहली प्रशंसकों के चेहरे खिले हैं। धर्मशाला में 15 सितंबर को पहला मौका होगा, जब कोहली की कप्तानी में टीम खेलेगी। इसके अलावा भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में सात खिलाड़ी ऐसे हैं, जो धर्मशाला मैदान में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच खेलेंगे। इससे पूर्व मार्च-2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के निर्णायक मैच में अंजिक्या रहाणे ने कप्तानी की थी। विराट को रांची टेस्ट में कंधे में चोट लगने के कारण बाहर होना पड़ा था। दिसंबर में भारत बनाम श्रीलंका के साथ खेले गए एक दिवसीय मैच में रोहित शर्मा ने भारत की कप्तानी की थी। रोहित टीम की कप्तानी करके भारत के 24वें कप्तान बने थे। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के लिए भारतीय टीम में शामिल नवदीप सैणी, दीपक चाहर, खलील अहमद, राहुल चाहर, वॉशिंगटन सुंदर, कुणाल पांड्या और ऋषभ पंत में पहली बार यहां खेलेंगे।

ये है भारतीय टीमः– कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा उप-कप्तान, शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जड़ेजा, कुणाल, पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल चाहर, खलील अहमद, दीपक चाहर और नवदीप सैणी टीम में शामिल हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

'नो फर्स्ट यूज' परमाणु नीति में हो सकता है बदलाव

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रक्षा मंत्री ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर भारत के नो फर्स्ट यूज सिद्धांत में बदलाव के संकेत दिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर भारत अपने नो फर्स्ट यूज सिद्धांत पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है लेकिन भविष्य में क्या होगा यह समय पर निर्भर करेगा, यह महत्वपूर्ण बयान रक्षा मंत्री ने पोखरण में दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पोखरण वह जगह है जो अटल बिहारी वाजपेयी के दृढ़ निर्णय का गवाह बना। भारत ने मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि भारत कभी खुद पहल नहीं करेगा लेकिन अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर प्रतिशोध के साथ प्रतिक्रिया देगा।

रवि शास्त्री फिर बने टीम इंडिया के कोच

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रवि शास्त्री को एक बार फिर भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। वे साल 2021 तक टीम इंडिया के हेड कोच बने रहेंगे। तीन सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और शांता रंगास्वामी ने रवि शास्त्री को भारतीय टीम के मुख्य कोच पद पर बरकरार रखा है। सीएसी ने 16 अगस्त 2019 को संवाददाता सम्मेलन कर इस बात की जानकारी दी। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के लिए अब तक 16 बार कोच चुने हैं। इनमें से चार कोच विदेशी रहे। जुलाई 2017 में दूसरी बार कोच बनने के बाद रवि शास्त्री की कोचिंग में भारतीय टीम ने 21 टेस्ट मैच खेले, जिसमें भारत को 13 में जीत मिली। रवि शास्त्री ने भारत के लिए 80 टेस्ट और 150 वनडे खेले हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने किया सीडीएस का घोषणा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और भारतीय नौसेना के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए इस पद की घोषणा की है। सुरक्षा विषय के जानकार बहुत समय पहले से ही इस सिस्टम की मांग करते रहे हैं। सरकार ने उनकी मांग और सेना में बेहतर समन्वय की जरूरतों को देखते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ की व्यवस्था करने की बात कही है। सीडीएस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा युद्ध के समय होगा। युद्ध के समय तीनों सेनाओं के बीच प्रभावी समन्वय कायम किया जा सकेगा। इस सिस्टम के द्वारा दुश्मनों को सक्षम तरीके से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। युद्ध के समय तीनों सेनाओं के लिए एक ही आदेश जारी किया जा सकेगा। इससे सेना की रणनीति पहले से अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। इससे काफी हद तक हम अपना नुकसान होने से बचा पाएंगे।

एक दशक में 20,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने विराट कोहली

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विराट कोहली ने 20 हजार रन बनाकर इतिहास रच दिया है। विराट कोहली ने यह उपलब्धि वेस्टइंडीज के विरुद्ध 14 अगस्त 2019 को तीसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अपने 43वीं शतकीय पारी के दौरान हासिल की। विराट कोहली ने टेस्ट तथा टी20 अंतर्राष्ट्रीय में साल 2010 में पदार्पण किया था। उन्होंने वनडे में साल 2008 में ही पदार्पण किया था। विराट कोहली ने बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेजी से दस हजार रन भी पूरे किए।

विराट कोहली ने 176 पारियों में ये कारनामा किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड रिकी पॉन्टिंग के नाम था जिन्होंने इसे 225 पारियों में अंजाम दिया था। विराट कोहली ने इस वनडे सीरीज में लगातार दूसरा वनडे शतक लगाया लेकिन ये उनका वेस्टइंडीज में लगातार तीसरा शतक है।

चंद्रिमा शाह विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनीं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चंद्रिमा शाह साल 2020 से अपना कार्यभार संभालेंगी। वे अजय कुमार सूद की जगह लेंगी। यह जानकारी भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने अपनी वेबसाइट पर दी है। चंद्रिमा शाह को विज्ञान को जनसमूहों के मध्य प्रचलित करने की जिम्मेदारी होगी। उन्हें साथ ही विदेशी संस्थानों के साथ करार पर अधिक ध्यान देना होगा। इनकी सबसे ज्यादा प्राथमिकता लोगों के बीच विज्ञान को अधिक तीव्रता से बढ़ावा देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारतीय वैज्ञानिकों की सर्वोच्च संस्था है। यह अकादमी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सभी शाखाओं का प्रतिनिधित्व करती है। वे साल 2020 से साल 2022 के बीच भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की अध्यक्ष होंगी। वे पहली महिला हैं जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है।

श्रीनगर और जम्मू के मेयरों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) एवं जम्मू नगर निगम (जेएमसी) के मेयर को उनके क्षेत्रीय अधिकार के तहत राज्यमंत्री के स्तर का दर्जा दिया गया है। नगर निगमों के लिए चुनाव 13 साल के अंतराल के बाद अक्टूबर 2018 में चार चरणों में हुआ था। सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त सचिव सुभाष छिब्बर की ओर से 21 अगस्त 2019 को इस आशय का आदेश जारी किया गया था।

विश्व कप – ओवरथ्रो की समीक्षा करेगा एमसीसी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

एमसीसी सितंबर 2019 में विश्व कप के 12वें सीजन के फाइनल में मार्टिन गप्टिल के थ्रो पर बेन स्टोक्स को दिए गए 6 रनों की समीक्षा करेगी। एमसीसी ने कहा की ऐसा फैसला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के फाइनल को ध्यान रखते हुए किया गया। विश्व क्रिकेट समिति (डब्ल्यूसीसी) का कहना है कि कानून पूरी तरह से स्पष्ट है, लेकिन इस मामले की समीक्षा कानून की उप - समिति सितंबर 2019 में करेगी। आईसीसी के 19.8 नियम के मुताबिक, फील्डर के हाथ से गेंद थ्रो होने से पहले बल्लेबाज अगर एक - दूसरे को क्रॉस कर चुके होते हैं और गेंद किसी कारण से बाउंड्री पार कर जाती है तो रन पूरा (दौड़ा हुआ रन और बाउंड्री से 4 रन) माना जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो रन अधूरा ही माना जाएगा।

केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की सेवानिवृत्ति आयु तय की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

गृह मंत्रालय का यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के जनवरी 2019 में दिए गए फैसले के बाद आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि सभी रैंक के लिए एक सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित करें। फैसला से पहले अलग - अलग रैंक के लिए अलग - अलग सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित थी। वर्तमान में पांच प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं। मौजूदा नीति के अनुसार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और असम राइफल्स के जवान 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। हालांकि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में कांस्टेबल से कमांडेंट स्तर के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 57 वर्ष है जबकि उनसे उच्च पदस्थ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है।

ऐश्वर्या पिस्सी मोटर स्पोर्ट्स में विश्व कप खिताब जीतने वाली बनी पहली भारतीय महिला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ऐश्वर्या पिस्सी दुबई में पहला दौर जीतने के बाद पुर्तगाल में तीसरा, स्पेन में पांचवां और हंगरी में चौथा स्थान हासिल किया। वे इससे 65 अंकों के साथ शीर्ष पर रहीं। एश्वर्या ने चैंपियनशिप के अंतिम दौर में बाद एफआईएम विश्व कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया। ऐश्वर्या पिस्सी बेंगलुरू की रहने वाली है। ऐश्वर्या साल 2018 में थकाऊ बाजा एरागोन रैली में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला राइडर बनी थीं। ऐश्वर्या पिस्सी के दो बड़े दुर्घटना हो चुके हैं। ऐश्वर्या साल 2017 में गिर गई थी, जिससे उनका कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया था। उनकी सर्जरी हुई और वे लगभग दो माह तक अस्पताल में रहीं।

केरल सरकार का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी सेवा और पीएसयू में होगी महिला ड्राइवरों की नियुक्ति

द रीव टाइम्स ब्यूरो

यह फैसला मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस फैसले से इस क्षेत्र में दशकों से चला आ रहा पुरुषों का वर्चस्व खत्म होगा। इस फैसला को लेकर सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। फिलहाल अभी तक केवल पुरुष ही सरकारी सेवा और पीएसयू में ड्राइवर के पोस्ट के लिए आवेदन करते रहे है, लेकिन इस संशोधन के बाद अब महिलायें भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकती है। राज्य सरकार ने हाल ही में महिला और बाल विभाग बनाया है। सरकार ने हाल ही में पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश के तौर पर 550 सदस्यों वाली पहली महिला बटालियन स्थापित की थी। केरल में परिवहन विभाग में महिलाओं के लिए अब तक बहुत सीमित नियुक्तियां रही हैं।

विश्व फोटोग्राफी दिवस 2019

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्व फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना, विचारों को एक - दूसरे के बीच साझा करना तथा सबको प्रोत्साहित करना है। ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कोर्स्के आरा ने साल 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना की शुरुआत की। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर 19 अगस्त 2010 को पहले वैश्विक ऑनलाइन गैलरी का आयोजन किया गया था। यह दिवस विश्वभर में फोटोग्राफरों के एकजुट करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अमेरिकन फोटोग्राफर रॉबर्ट कॉर्नेलियस ने साल 1839 के शुरूआती महीने में एक सेल्फी ली थी।

डॉक्टरों की ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा की अनिवार्य शर्तों को लेकर एक समान नीति बनाए केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच जस्टिस एल नागेश्वर राव एवं हेमंत गुप्ता ने कहा कि कि सरकारें प्रत्येक मेडिकल छात्र पर बड़ी रकम खर्च करती हैं इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक करना है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अपने अधिकारों का उपयोग कर डॉक्टरों को अनिवार्य सेवा देने हेतु कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़नेवाले छात्रों हेतु एक निश्चित अवधि तक ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों में सेवा देने का अनिवार्य कानून होना चाहिए। यह नियम अभी तक आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना एवं बंगाल में अनिवार्य है।

अक्षय फोर्ब्स के टॉप टेन में

द रीव टाइम्स ब्यूरो

फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एक्टर्स की सूची जारी की। अक्षय कुमार इस सूची में शामिल होने वाले मात्र एक बॉलीवुड अभिनेता हैं। इस सूची में पहले स्थान पर 'द रॉक' के नाम से मशहूर रेसलर से अभिनेता बने ड्वेन जॉनसन (रॉक) का है। यह पिछले एक साल में 89.4 मिलियन डॉलर (6,39,54,97,200 रुपए) कमाकर सबसे आगे हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर क्रिस हेम्सवर्थ (76.4 मिलियन डॉलर) और तीसरे स्थान पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर (66 मिलियन डॉलर) है।

चंद्रयान - 2 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इसरो के अनुसार, इस मिशन का अगला बड़ा कदम 02 सितंबर को होगा जब ऑर्बिटर से लैंडर निकल जाएगा। इसरो ने बताया की चांद के 3 लाख 84 हजार किलोमीटर के सफर पर निकला चंद्रयान - 2 अब अपने मिशन से मात्र 18 हजार किलोमीटर दूर है। इसरो के मुताबिक, यह अभियान सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर रोवर पहुंचाने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य चांद की सतह का नक्शा तैयार करना, खनिजों की मौजूदगी का पता लगाना, चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना और किसी न किसी रूप में पानी की उपस्थिति का पता लगाना है।

केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा कैबिनेट सचिव नियुक्त

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने राजीव गौबा को कैबिनेट सचिव के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनका कार्यकाल 30 अगस्त 2019 से दो साल या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक होगा। राजीव गौबा, पी. के. सिन्हा की जगह लेंगे। पी. के. सिन्हा इस पद पर चार साल पूरा करने के बाद कार्यकाल विस्तार के तहत काम कर रहे थे। राजीव गौबा ने 31 अगस्त 2017 को गृह सचिव के तौर पर कामकाज संभाला था।

बजरंग और दीपा को राजीव खेल रत्न

द रीव टाइम्स ब्यूरो

महिला एथलीट दीपा मलिक तथा पहलवान बजरंग पुनिया को खेल का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न दिए जाने की घोषणा हुई है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रति वर्ष खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन को पहचानने और सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

भारत-पाक के बीच तनाव घटाने में मदद करना जी-7 में उठाए गए पांच प्रमुख मुद्दों में से एकः व्हाइट हाउस

द रीव टाइम्स ब्यूरो

व्हाइट हाउस ने दावा किया कि हाल ही में सम्पन्न हुए जी-7 शिखर सम्मेलन में उठाए गए पांच प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मदद करना था। जी-7 सम्मेलन से इतर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस ने दावा किया कि हाल ही में सम्पन्न हुए जी-7 शिखर सम्मेलन में उठाए गए पांच प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा भारत - पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मदद करना था। जी-7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने गए थे। जी-7 का आयोजन फ्रांस के बिआरित्ज शहर में 24 से 26 अगस्त के बीच किया गया था। व्हाइट हाउस ने कहा, 'जी - 7 में उठाए गए पांच बड़े मुद्दे थे - एकता का संदेश देना, एक अरब डॉलर के व्यापार सौदे की सुरक्षा, अमेरिका - मेक्सिको - कनाडा समझौते (यूएसएमसीए) को आगे बढ़ाना, यूरोप के साथ मजबूत व्यापार संबंध विकसित करना और भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करना। 'उन्होंने कहा, 'भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक में राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की जरूरत पर जोर दिया और हमारे देशों के बीच महान आर्थिक संबंध बनाने की बात भी की।

G-7 समिट में हांगकांग पर जारी संयुक्त बयान पर बिफरा चीन, जताई कड़ी आपत्ति

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बीजिंग ने मंगलवार को G7 में तमाम नेताओं द्वारा हांगकांग को लेकर दिए गए संयुक्त बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा, यह पूरी तरह चीन का आंतरिक मामला है। बता दें कि फ्रांस में G7 देशों के नेताओं की बैठक में हांगकांग की स्वायत्तता का समर्थन किया गया। साथ ही हांगकांग में शांति की अपील की गई। वर्ष 1984 में ही ब्रिटेन और चीन के बीच समझौते में हांगकांग की स्वायत्ता तय की गई थी। हांगकांग पूरी तरह चीन का आंतरिक मामला बीजिंग ने विदेशी सरकारों पर हांगकांग के मामले में हस्तक्षेप का आरोप लगाया और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, 'G7 मध्यस्थता कर तनावों को बढ़ावा दे रहा है।' बीजिंग में गेंग ने कहा, 'हांगकांग मामले पर G7 समिट में तमाम नेताओं द्वारा दिए गए बयान पर हम कड़ी आपत्ति जताते हैं।'

हमने अनेकों बार कहा है कि हांगकांग पूरी तरह चीन का आंतरिक मामला है और इसमें विदेशी सरकार, संस्थान या किसी का भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं।' उन्होंने कहा, 'हांगकांग के लिए चीन और हांगकांग की जनता से अधिक कोई नहीं सोच सकता है।' G7 बयान में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मन, इटली, जापान और अमेरिका ने शांति बनाए रखने की अपील की। बीजिंग ने पूर्व औपनिवेशिक शक्ति ब्रिटेन को आरोपी बताया जिसने 1997 में अर्धस्वायत्त क्षेत्र हांगकांग का अधिकार चीन को सौंप दिया था।

बहरीन में PM मोदी को मिला 'द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनसां' सम्मान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पीएम मोदी G-7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए बहरीन से फ्रांस रवाना हो गए है। इससे पहले उन्होंने श्रीनाथजी मंदिर के दर्शन किए। बता दें यूएई के बाद बहरीन में भी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। बहरीन के राजा के साथ मुलाकात के दौरान पीएम मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनसां (The King Hamad Order of the Renaissance) से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने बहरीन की ओर से यह सम्मान मिलने के बाद कहा, 'मैं द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनसां से सम्मानित होने से खुद को सम्मानित और सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा की यह पूरे भारत के लिए सम्मान की बात है। यह बहरीन और भारत के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है।

कोई भी कानून से ऊपर नहीं, डॉ. जाकिर नाइक भी नहीं मलेशिया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय अधिकारी कथित धनशोधन और घृणा भाषणों के जरिए चरमपंथ भड़काने के मामलों में 2016 से नाइक की तलाश कर रहे हैं। आतंकी गतिविधियों के आरोप में भारत में वांछित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के बारे में मलेशिया के गृहमंत्री एम. यासीन ने कहा है कि वह कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, डॉ. जाकिर नाइक भी नहीं। इससे पहले मलेशिया की सरकार ने जाकिर नाइक के भाषण देने पर रोक लगा दी थी। मलेशियाई अधिकारियों ने जाकिर नाइक को हिंदुओं एवं चीनियों के खिलाफ कथित नस्ती टिप्पणी करने के मामले में दूसरी बार तलब किया था। इससे कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने विवादित भारतीय इस्लामी धर्म उपदेशक को कहा था कि उसे देश में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की इजाजत नहीं है। न्यूज एजेंसी ने पुलिस कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के हेड दातुक असमावती अहमद के हवाले से लिखा है, 'हां, ऐसा आदेश सभी पुलिस थानों को दिया गया है, और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और नस्लीय सौहार्द बनाए रखने के लिए किया गया है। बता दें, आधिकारिक बरनामा संवाद समिति ने खबर दी थी कि नाइक को रॉयल मलेशिया पुलिस मुख्यालय, बुकित अमन में उसका बयान दर्ज कराने के लिए दूसरी बार बुलाया गया था। भारतीय अधिकारी कथित धनशोधन और घृणा भाषणों के जरिए चरमपंथ भड़काने के मामलों में 2016 से नाइक की तलाश कर रहे हैं। सीआईडी के निदेशक हुजीर मोहम्मद ने बताया कि जाकिर दंड संहिता की धारा 504 के तहत अपना बयान देने के लिए बुकित अमन आने वाला है। यह धारा शांति भंग करने के लिए उकसाने की मंशा के साथ जानबूझकर अपमान करने से जुड़ी हुई है। खबर में बताया गया कि 53 वर्षीय उपदेशक ने पहली बार 16 अगस्त को अपना बयान दर्ज कराया था। वह मुस्लिम बहुल मलेशिया का स्थायी निवासी है।

देशों की सूची से निकालने पर फिलिस्तीन ने अमेरिका की निंदा की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

फिलिस्तीन को देशों और प्रांतों की अपनी सूची से निकालने पर फिलिस्तीन के अधिकारियों ने अमेरिका की निंदा की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, फिलिस्तीन के सरकारी प्रवक्ता नबिल अबु रुदैनेह ने एक आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस निर्णय में अमेरिका की विदेश नीति में अभूतपूर्व गिरावट दिखती है। फिलिस्तीन को देशों और प्रांतों की अपनी सूची से निकालने पर फिलिस्तीन के अधिकारियों ने अमेरिका की निंदा की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, फिलिस्तीन के सरकारी प्रवक्ता नबिल अबु रुदैनेह ने रविवार को एक आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस निर्णय में अमेरिका की विदेश नीति में अभूतपूर्व

गिरावट दिखती है। रुदैनेह ने कहा, ''यह निर्णय एक बार फिर दिखाता है कि अमेरिका ना सिर्फ इजरायल का पक्ष ले रहा है, बल्कि इजरायल के कट्टर दक्षिणपंथ की योजनाओं के पूरे सहयोग में है।''इससे पहले इजरायल रेडियो ने बताया था कि अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट से फिलिस्तीनी सीमा या फिलिस्तीनी प्रशासन से संबंधित सभी जानकारियों को डिलीट कर दिया। दिसंबर 2017 में जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद से फिलिस्तीन और अमेरिका के बीच राजनीतिक संबंध नाजुक दौर में पहुंच चुके हैं। मई 2018 में वाशिंगटन ने इजरायल में अपने दूतावास को स्थानांतरित कर दिया था। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने भी फिलिस्तीन या फिलिस्तीनियों को संबोधित करने वाले सभी शब्दों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटाने के लिए अमेरिका की निंदा की थी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''वर्तमान अमेरिकी सरकार दो-राष्ट्र समाधान को नष्ट करने और अपने अधिकारों से बचने के लिए इजरायल की योजना को लागू करती है।''

रुस - सीरिया के बीच इदलिब शहर को लेकर हुआ समझौता

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सीरिया के शहर इदलिब पर रूस की तरफ से कोई भी आक्रमण नहीं किया जाएगा। रूस सरकार की तरफ से बयान आया है कि वह अब इदलिब में सीजफायर नहीं करेगा। इसको लेकर दोनों सरकार के बीच समझौता हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले सीरिया में तरह - तरह के हमले हुए हैं। इसमें रूस भी शामिल है। दरअसल रूस का मानना है कि सीरिया में आतंकी संगठन ISIS बारह - बार हमला करता है जिससे निपटने के लिए रूस की तरफ से सीरिया में हमला किया जाता था। नए समझौते के बाद अब इस प्रकार के हमलों पर प्रतिबंध लग जाएगा। सीरिया और रूस में लंबे समय से इस प्रकार का युद्ध चल रहा है। इस दौरान सीरिया के कई शहरों में रूस कई बार हमले कर चुका है। पिछले दिनों विद्रोही ठिकानों पर सरकारी और रूसी विमानों द्वारा किये गए हवाई हमलों में आठ बच्चों सहित कम से कम 21 नागरिक मारे गए थे। रूस का मानना है कि सीरिया में कम से कम 3 हजार आतंकवादी सीरिया में मौजूद है। जिसे रोकने के लिए लंबे समय से रूस ने अपने सैनिकों की तैनाती सीरिया में हुई है।

पाकिस्तानी राष्ट्रपति को ट्विटर का नोटिस

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कश्मीर की स्थिति पर ट्वीट करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को ट्विटर ने नोटिस भेजा है। मानवाधिकार मंत्री शिरीन मंजरी ने राष्ट्रपति अल्वी को ट्विटर के अधिकारियों से मिले मेल का स्क्रीन शॉट पोस्ट किया है और कहा कि नोटिस सही नहीं है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति अल्वी ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें कश्मीर मुद्दे को लेकर प्रदर्शन होता दिख रहा है। संचार मंत्री मुराद सईद ने कहा कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट से उन्हें भी नोटिस मिला है कि उनके एक ट्वीट से भारतीय कानूनों का उल्लंघन हुआ है।

पाकिस्तान में गहराया रोटी का संकट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे पाकिस्तान में रोटी का संकट गहराता जा रहा है। पाकिस्तान में गेहूं की कीमतें आसमान छूने लगी है। इसी महीने में इसकी कीमतों में तीसरी बार इजाफा हुआ है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में सामान्य श्रेणी के आटे की कीमत 44.50 प्रति किलो जबकि सुपर फाइन और फाइन श्रेणी के आटे की कीमत 47.50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। यही नहीं वेबसाइट NUMBEO के मुताबिक, अच्छे किस्म के चावल की कीमत 130.47 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, इस साल अप्रैल के बाद से सामान्य श्रेणी के आटे की कीमतों में 11 रुपये प्रति किलो की दर से इजाफा हुआ है। देश में गहराती खाद्यान्न समस्या से पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रांतीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आटे की लगातार बढ़ रही कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिशें तेज करें। रिपोर्ट के मुताबिक, इस महीने बकरीद के मौके पर कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया था। इसके बाद दूसरी बार कीमतें बीते 22 अगस्त को बढ़ी थीं। पाकिस्तान की आटा मिलें 10 किलो के आटे के बैग की कीमत 450 रुपये वसूल रही हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सिंध जोन के अध्यक्ष मोहम्मद जावेद यूसुफ ने बताया कि देश में गेहूं की कीमतें 4,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई हैं।

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उतरा ह्यूमनॉएड रोबोट, अंतरिक्ष यात्रियों की करेगा मदद

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रूस के पहले रोबोट को लेकर रवाना हुआ सोयूज अंतरिक्षयान (Russian Soyuz Spacecraft) इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (International Space Station) पर उतर गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई ह्यूमनॉएड रोबोट, आइएसएस पर गया है। नासा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सोयूज अंतरिक्षयान आइएसएस पर सफलतापूर्वक उतर गया है। फेडोर नामक यह रोबोट दस दिनों तक आइएसएस पर रहेगा और अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करना सीखेगा। रूस ने धरती की परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह आइएसएस पर पहली बार रोबोट भेजा है।

आपातकालीन बचाव प्रणाली की जांच के लिए भेजा गया

फेडोर नामक रोबोट को लेकर सोयूज एमएस-14 अंतरिक्ष यान पिछले हफ्ते कजाखस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से आइएसएस के लिए रवाना हुआ था। इसे पिछले हफ्ते आइएसएस पर पहुंचना था। सोयूज आमतौर पर अंतरिक्षयात्रियों को लेकर आइएसएस पर जाता है, लेकिन इस बार आपातकालीन बचाव प्रणाली की जांच के लिए इसे मानवरहित रवाना किया गया है।

गगनयान मिशनमें रुस करेगा भारत की मदद 12 में से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को देगा ट्रेनिंग

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी परियोजना गगनयान के लिए चयनित होने वाले 12 संभावित भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों में से चार को रूस अपने यहां ट्रेनिंग देगा। इन सभी अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देने का काम नवंबर से शुरू होगा और 15 महीने तक चलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष के सीवान ने बताया कि भारत 12 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस भेजेगा जिसमें से वह खुद चार का चयन करेंगे और उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग देंगे। इस मिशन के लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। मिशन का लक्ष्य है कि भारत कम सम कम अपने तीन अंतरिक्ष यात्रियों को 5 से 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा जहां वह अलग-अलग तरह के माइक्रो ग्रैविटी टेस्ट को अंजाम देंगे। रसियन स्पेश एजेंसी रॉस्कोमोस के महानिदेशक दिमित्रा रोगोजिन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल की मॉस्को में मीटिंग हुई। इसी दौरान दोनों पक्ष मास्को स्थित यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में चार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस मिशन के लिए तैयार करने को लेकर सहमित बनाई गई थी। जैसे ही इन सभी की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी वैसे ही ये भारत लौट आएंगे और 2022 में लॉन्चिंग से पहले के कुछ महीनों में बाकी की तैयारियां करेंगे।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करंट अफेयर्स

THE CURRENT AFFAIRS 2019

- हाल ही में जिस पूर्व भारतीय बल्लेबाज का चेन्नई में 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है – वी.बी. चंद्रशेखर
- वह भारतीय खिलाड़ी जो किसी एक दशक (दस वर्ष) में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गये हैं – विराट कोहली
- जिस राज्य सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) के चेयरमैन के. सिवन को 'डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार' से सम्मानित किया – तमिलनाडु सरकार
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर जितने प्रतिशत करने की घोषणा की है – 27 प्रतिशत
- 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर 3 लोकसभा क्षेत्रों के बीच कम से कम जितने मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे – एक
- भारतीय पहलवान दीपक पुनिया ने हाल ही में जूनियर विश्व चैम्पियनशिप में जो पदक अपने नाम किया है – स्वर्ण पदक
- जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने छात्रों के मन में देश के प्रति प्रेम जगाने हेतु अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है – दिल्ली
- जिस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने कम लागत वाली ब्लड टेस्ट डिवाइस का विकास किया है – आईआईटी खड़गपुर
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संस्थान का निर्देशक जिसे नियुक्त किया गया है – हर्षद पांडुरंग ठाकुर
- हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में जितने प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की – चार प्रतिशत
- जिसे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर चक्र से सम्मानित किया गया – अभिनंदन वर्धमान
- वर्ष 2019 का संस्कृत दिवस जिस दिन मनाया गया – 15 अगस्त
- विश्व हाथी दिवस जिस दिन को मनाया जाता है – 12 अगस्त
- केंद्र सरकार ने छह शहरों – भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जोधपुर, पुणे, अहमदाबाद और जिस शहर की पहचान की है जिन्हें सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा – हैदराबाद
- जिस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पहली बार एनोड के रूप में हल्के स्टील का प्रयोग करके रिचार्जेबल आयरन आयन बैटरी का निर्माण किया है – आईआईटी मद्रास
- हाल ही में गोगाबील को जिस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है – बिहार
- हाल ही में वन विभाग ने जिस वन्यजीव अभयारण्य में शामिल करने हेतु लगभग 300 हेक्टेयर भूमि की पहचान की है – कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य
- Doodle for Google 2019 प्रतियोगिता का पुरस्कार जिसने जीता है – Arantza Pena Popo
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लॉन्च किये जाने के साथ – साथ जिस मोबाइल एप्प को भी लॉन्च किया गया है – स्वच्छ नगर एप्प
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, जिस शहर में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत अपशिष्ट की खुले में डंपिंग और दहन हैं – दिल्ली
- वह राज्य सरकार जिसने 9 साल की लड़की एलंगबाम वैलेंटिना को राज्य का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया है – मणिपुर
- हाल ही में जिस देश ने भारत के लिये कार्य – वीजा नियमों को आसान करने का आश्वासन दिया है – न्यूजीलैंड
- अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्थान द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत जिस स्थान पर है – 13वें
- हाल ही में भारत और जिस देश ने खेल, संस्कृति तथा पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में चार समझौतों पर हस्ताक्षर किये है – चीन
- मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जिस आईआईटी में टेकएक्स नाम की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया – आईआईटी दिल्ली
- दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए जो देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप आयातक बन गया है – भारत
- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का अध्यक्ष जिसे बनाया गया है – चंद्रिमा शाह
- केंद्र सरकार ने जितने प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ विचार – विमर्श के बाद 'पीपुल्स प्लान' अभियान शुरू करने का फैसला किया है – 16
- वैज्ञानिकों ने दुर्लभ पौधों की प्रजातियों की खोज की है जो प्रायद्वीपीय भारत तथा जिस देश के बंगाल की खाड़ी में उपस्थित द्वीपों से अतीत के महाद्वीपीय संबंधों को जोड़ने में मदद कर सकती है – श्रीलंका
- नीति आयोग ने हाल ही में जिस शहर में वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का चौथा संस्करण लॉन्च किया है – दिल्ली
- वह देश जिसने भारत को मादक पदार्थों द्रव्य के पारगमन या अवैध मादक पदार्थों के उत्पादक देशों की सूची में शामिल किया है – अमेरिका
- केंद्र सरकार ने जिस योजना के दूसरे चरण के तहत राज्यों में 5595 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है – फेम इंडिया योजना
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया के तहत किसानों को तकनीक से जोड़ने हेतु जिस मोबाइल एप का लॉन्च किया है – मेघदूत मोबाइल एप
- हाल ही में जिस सरकार ने राज्य के स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है – आंध्र प्रदेश
- हाल ही में मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच जिस नदी पर बने सरदार सरोवर बांध में पानी छोड़ने को लेकर विवाद सामने आया है – नर्मदा नदी
- हाल ही में जिस मंत्रालय ने किसी पुरुष के सिंगल पेरेंट होने की स्थिति में चाइल्ड केयर लीव के लिए मंजूरी दी है – रक्षा मंत्रालय
- एम. वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति पद पर दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर जिस नाम से पुस्तक लॉन्च की गई है – Listening, Learning and Leading
- परिवार में बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सहायता प्रदान करने के लिए जिस राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री मदद योजना' आरंभ की है – मध्य प्रदेश
- इसरो के जनक का यह नाम है जिनके जन्मदिवस के अवसर पर गूगल ने डूडल पेश किया है – विक्रम साराभाई
- विश्व मानवतावादी दिवस जिस दिन को मनाया जाता है – 19 अगस्त
- हाल ही में बिहार के जिस पूर्व मुख्यमंत्री का 83 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया – डॉ जगन्नाथ मिश्रा
- भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जिस योजना को अधिक उदार बनाते हुए जमाकर्ताओं को अपने सोने को सीधे बैंकों और रिफाइनरों के पास जमा करने की अनुमति दे दी है – स्वर्ण मुद्रीकरण योजना
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में वृद्धि के फलस्वरूप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.620 बिलियन डॉलर बढ़कर जितने बिलियन डॉलर हो गया है – 430.572 बिलियन डॉलर
- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हाल ही में जितने नये भौगोलिक संकेतकों को पंजीकृत किया है – चार
- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जिस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पहला वर्चुअल न्यायालय शुरू किया है – फरीदाबाद
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 में जिसे राजीव गाँधी खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया – दीपा मलिक
- विश्व फोटोग्राफी दिवस जिस दिन मनाया जाता है – 19 अगस्त
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस देश में मांगदेछू पनबिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है – भूटान
- भारत सरकार द्वारा अध्यापक शिक्षा पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जिस स्थान पर किया गया – नई दिल्ली
- हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने अपने कार्यकाल का जितने साल पूरा कर लिया है – एक साल
- भारत और जिस देश के बीच 'विशेष' द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर दो दिवसीय दौरे पर ढाका पहुचें हैं – बांग्लादेश
- पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को हाल ही में जिस राज्य से राज्य सभा सदस्य चुन लिया गया है – राजस्थान
- 'उमराव जान, बाजार, कभी – कभी, जैसी फिल्मों के लिए गीतों की धुन बनाने वाले संगीतकार का यह नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है – मोहम्मद जहूर खय्याम
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में यहाँ पर भूमिगत बंकर म्यूजियम का उद्घाटन किया है – मुंबई
- भारत के पहले केन्द्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना जिस राज्य में की जाएगी – गुजरात
- फर्नीचर का कारोबार करने वाली स्वीडन की प्रमुख कंपनी IKEA ने हाल ही में भारत में जिस स्थान पर ऑनलाइन स्टोर खोला है – मुंबई
- गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सेवानिवृत्ति आयु अब यह होगी – 60
- जलवायु परिवर्तन के कारण आइसलैंड के जिस ग्लेशियर ने अपनी पहचान खो दी है – ओकजोकुल
- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ जायद' प्रदान किया जाएगा – संयुक्त अरब अमीरात
- मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री (अगस्त 2004 से नवंबर 2005) का यह नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है – बाबूलाल गौड़
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में जिस संक्रामक बीमारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है – खसरा
- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने कुछ निश्चित प्रकार के विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देने हेतु जिस चैनल की शुरुआत की है – ग्रीन चैनल
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वय प्रणाली के लिये विशेष उद्देश्य न्यास कोष में जितने लाख डॉलर का योगदान दिया है – 10 लाख डॉलर
- चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम जिस दिन ऑर्बिटर से अलग होगा – 02 सितंबर
- जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व भर में बढ़ रहे जल प्रदूषण के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है – World Bank
- जिस संस्था द्वारा निर्मित मोबाइल मैटेलिक रैंप हाल ही में भारतीय सेना को सौंपा गया है – डीआरडीओ
- जिस दिन वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है – 21 अगस्त
- अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में जिस देश को 'एफ-16' युद्धक विमान बेचे जाने की मंजूरी दे दी है – ताइवान
- कोलैबोरेटिव क्लीन एयर पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जिस देश में वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण घरों में ठोस ईंधन को जलाना है – भारत
- दुनियाभर में विश्व मच्छर दिवस जिस दिन को मनाया जाता है – 20 अगस्त
- भारत और जाम्बिया ने हाल ही में रक्षा सहित कारोबार एवं निवेश संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए जितने सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए – छह
- केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसे रक्षा सचिव नियुक्त किया है – अजय कुमार
- भारत के पूर्व वित्त मंत्री जिन्हें हाल ही में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया है – पी. चिदम्बरम
- जिसे हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर नियुक्त किया गया है – राजीव गौबा
- वह राज्य जिसने हाल ही में सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राईवरों की भर्ती के लिए अनुमति प्रदान की है – केरल
- हाल ही में जिस राज्य के हाई कोर्ट ने राज्य में डीजे बजाने पर प्रतिबन्ध लगाने का फैसला सुनाया है – उत्तर प्रदेश
- हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवार के लिए पारिवारिक आय की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर जितना करने की घोषणा की है – 15,000

हिमाचल सामान्य ज्ञान

- डाक्टर वाईएस परमार की कौन सी जंयती मनाई जा रही है – 113वीं
- कृषि विश्वविद्यालय ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया – 11वां
- मुंख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत कितनी सब्सिडी दी जाती है – 80 और 85 प्रतिशत
- बालिका गौरव उद्यान योजना कहां शुरू की गई थी – मंडी में
- सौरभ वन विहार कांगड़ा में कहां पर है – पालमपुर
- हिमाचल में कितने ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं – 358
- मंडी जिले के किस क्षेत्र को ईको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाएगा – जंजैहली
- किस शिक्षक को टीचर इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया – चंबा में भटियात उपमंडल के तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला कहारी के अध्यापक आशीष बहल को
- हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी मिनी पंजाब के नाम से प्रख्यात है – बल्ह घाटी जिला मंडी
- सुकेती खड्ड किस घाटी में बहती है – बल्ह घाटी
- हिमाचल प्रदेश ने किस देश से भेड़ों की उन्नत किस्म की खरीद करेगा – आस्ट्रेलिया
- बच्चों को बौनेपर और कुपोषण भगाने में हिमाचल ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है – हिमाचल प्रदेश
- शानन जन विद्युत परियोजना कहां पर है – मंडी के जोगिंद्रनगर में 110 मेगावाट
- हिमाचल में कितने स्कूलों में सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे – 312

आर्थिक सर्वेक्षण

- वर्ष 2018–19 में घरेलु उत्पाद कितना है

1 लाख 51 हजार 835, जबकि 2017–18 में यह 1 लाख 36 हजार 542 था

2018–19 के लिए विकास दर कितनी अनुमानित है

- 7.3 प्रतिशत जबकि 2017–18 में 6.5 प्रतिशत

चालू कीमतों पर हिमाचल में प्रतिव्यक्ति आय 2018–19 में क्या है

1 लाख 76 हजार 968 जो 2017–18 (1 लाख 60 हजार 711) से 10.1 प्रतिशत अधिक है।

- जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

प्राथमिक क्षेत्र का योगदान – 13,738

द्वितीय क्षेत्र का योगदान – 47, 819

तृतीय क्षेत्र – 43,220

- 2017–18 में कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्रों का योगदान –

कृषि व सहायक क्षेत्र – 8.8 प्रतिशत

उद्योग क्षेत्र – 29.2 प्रतिशत

सेवा क्षेत्र – 43.3 प्रतिशत

- वर्ष 2018–19 के लिए अनुमानित विकास दर

7.3 प्रतिशत जबकि 2017–18 में 6.5 फीसदी रही।

- 2018–2019 की राजस्व प्राप्तियां क्या रही

कर से प्राप्त – 8 हजार 248 करोड़

गैर कर से प्राप्त – 1 हजार 981 करोड़

वित्तीय घाटे की दर 2017–18 में क्या रही 1.92 प्रतिशत

- हिमाचल में न्यूनतम मजदूरी – 225 रूपये प्रतिदिन
- टेली मेडीसन सेवा – शिमला, सिरमौर और चंबा

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

वन समृद्धि – जन समृद्धि योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आबादी की आमदनी बढ़ाने के लिए वन समृद्धि-जन समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के जरिये ग्रामीण लोग औषधीय पौधे की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। हिमाचल में जहां फसलों पर जंगली जानवरों की मार है वहां पर औषधीय खेती एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से कुछ समय पहले ही वन समृद्धि-जन समृद्धि योजना शुरू की गई है। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह इस योजना का लाभ लेकर अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव ला सकते हैं और कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

क्या है वन समृद्धि–जन समृद्धि योजना

वन समृद्धि-जन समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य बहुमूल्य जड़ी बूटियों को संरक्षित और सुरक्षित करना है। इलाज और दवाई बनाने में काम आने वाले औषधीय पौधे की खेती आसानी से की जा सकती है। सरकार इसके लिए ग्रामीणों को बीज समेत तमाम मदद उपलब्ध कराएगी और उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनकी बाजार कीमत पर बिक्री की व्यवस्था करेगी। इस योजना के माध्यम से सरकार उन औषधीय पौधे का संरक्षण भी कर सकेगी जो धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं।

योजना की मुख्य बातें

हिमाचल सरकार वन समृद्धि जन समृद्धि योजना के माध्यम से उन ग्रामीण परिवारों की आर्थिक आय बढ़ाने के प्रयास कर रही है जो औषधीय पौधे की खेती में जुटे हैं। सरकार फसल तैयार होने के बाद कटाई, मूल्य वृद्धि और उसके विपणन पर ध्यान देगी। ग्रामीण अपनी जमीन पर औषधीय पौधे उगा सकते हैं, इसके लिए राज्य सरकार उन्हें 25 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। जब औषधीय पौधे, बीज, फूल, पत्तियां तैयार हो जायेंगे तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इसकी बिक्री की जाएगी। इन चिकित्सीय उत्पाद को उस विशेष जड़ी बूटी के बाजार मूल्य पर खरीदा जाएगा। खेत या जंगल से इस तरह की जड़ी-बूटियों की बिक्री अवैध तरीके से नहीं की जा सकेगी। हिमाचल सरकार वास्तव में राज्य के जंगल-खेतों में उगाए जाने वाले औषधीय पौधे की किसानों को उचित कीमत दिलाना

चाहती है। अब तक इस तरह के उत्पादों का कोई खास बाजार नहीं है और इस वजह से औषधीय पौधे की खेती से किसान को विशेष लाभ नहीं हो पाता। हिमाचल सरकार इस समय प्रदेश के उन 5 जिलों में मैपिंग कर रही है जहां ऐसे औषधीय पौधे पाए जाते हैं। सरकार की कोशिश यह है कि इन इलाके के किसानों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराया जाए और चिकित्सीय पौधे का उत्पादन बढ़ाया जाए। औषधीय पौधे की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। सरकार की यह योजना जड़ी बूटियों के संरक्षण में लाभदायक सिद्ध होगी।

स्वंय सहायता समूह को प्रशिक्षण

हिमाचल सरकार का वन विभाग जंगल से जड़ी-बूटी निकालने, चुनने के लिए स्वंय सहायता समूह के सदस्यों को विषेश प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। इनमें इनमें सताव, औंरा, बंदरा, काली तुलसी, वन बैगन, सिकटी, हर्रे, घृत कुमारी, पीपर, नीम, सफेद मुसली, सर्पगंधा, मीठा नीम, हरला-वाकस, जंगली (लाल) प्याज, रीठा, सीता पत्ता, मैदा वृक्ष, गुड़माड़ वृक्ष, बेलपत्र, इंदुजा, राम दतवन, धतुरा, कैकटस, सफेद पलास, काली हरदी, सफेद चंदन, दुधी लता, बहेड़ा, सोमराज, वायडींग, पुनर्नवा, ब्राम्ही, चाल जैसे औषधीय पेड़-पौधों सहित अन्य जड़ी-बूटियां शामिल हैं। हिमाचल वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, जंगल में औषधीय पौधों की करीब 1038 प्रजातियां हैं जिनसे 3,400 प्रकार की अमूल्य जड़ी-बूटियां मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश वन समृद्धि जन समृद्धि योजना इन अनमोल जड़ी बूटियों के संरक्षण और सुरक्षा में मदद करेगी। हिमाचल सरकार कैंपा फंड के जरिये प्रदेश भर में 22 वन विहार, ईको पार्क स्थापित करेगी। इन इलाके में भी औषधीय पौधे की खेती की जा सकेगी। वन समृद्धि जन समृद्धि योजना के जरिये जड़ी बूटी इकट्ठा करने, प्रसंस्करण और विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बेटी है अनमोल

योजना क्या है

बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों की लड़कियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य लड़की की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत पहली से 12वीं तक की छात्राओं को छात्रवृति देने का प्रावधान तो है ही, साथ ही बेटी के जन्म पर एफडी कराने का भी प्रावधान है।

यहां समझे वित्तीय सहायता का लाभ

बीपीएल परिवार की सूची में नामित परिवार मे जब कोई बेटी जन्म लेती है तो जन्म का पंजीकरण होने के साथ ही वह योजना का लाभ लेने की पात्र हो जाती है। तय प्रावधानों के मुताबिक जन्म पंजीकरण होने पर बेटी के खाते में 10 हजार की एफडी के तौर पर सरकार की ओर से महिला एवं बाल कल्याण विभाग के माध्यम से बेटी के नाम से खाते में जमा किये जाते है। यह लाभ एक परिवार में जन्म लेने वाली अधिकतम दो बेटियों को मिलता है।

स्कूल में दाखिले पर छात्रवृति

जन्म के समय खाते में 10 हजार की एफडी कराने के अलावा जैसे ही बेटी का स्कूल में दाखिला होता है उस समय भी सरकार की ओर से बेटियों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

हिमाचल सरकार पहली कक्षा से 12 वीं कक्षा तक की लड़कियों को 300 – 1200 रुपये छात्रवृत्ति देती है। इसके अलावा कॉलेज जाने वाली बेटियों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय मदद देकर हिमाचल सरकार प्रदेश में महिलाओं में उच्च शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहती है।

स्नातक पर मिलेगी छात्रवृत्ति

सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से स्नातक स्तर पर समकक्ष पाठ्यक्रमों और अन्य कोर्स में पढ़ाई करने वाली लड़कियों को 5,000 हजार रुपये की छात्रवृत्ति देती है।

कैसे करें आवेदन

इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन, दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास करने के बाद बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग और मेडिकल - लॉ आदि की पढ़ाई कर रही बेटियां इस योजना के तहत छात्रवृत्ति पा सकती हैं।

क्या चाहिए दस्तावेज

बेटी हैं अनमोल योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात - आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, बीपीएल राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र साथ लगाने होंगे।

क्या है बेटी है अनमोल योजना की पात्रता?

बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश

बेटी है अनमोल योजना के तहत 5 जुलाई 2010 के बाद पैदा हुई। लड़कियों को 12 वीं कक्षा तक पढ़ाई पर मिलने वाले लाभ मिल सकते हैं। यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार की बेटी है अनमोल योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें : http://edistrict.hp.gov.in./pages /staticSite/serviceList.xhtml इस लिंक पर आपको बेटी है अनमोल योजना का लिंक दिखाई देगा। उसके दायीं तरफ आप अप्लाय बटन पर क्लिक करेंगे तो यह पेज खुलेगा। इसे सबमिट करने के बाद आपका आवेदन सरकार के पास पहुंच जायेगा। अगर आप बेटी है अनमोल योजना के तहत आवेदन पत्र भरकर और जरूरी दस्तावेज लगाकर अप्लाय करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: https://himachalforms.nic.in /pdfs/Women-Child-Dev/BetiHaiAnmolYojna.pdf इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके समाने बेटी है अनमोल योजना आवेदन फार्म खुलेगा। इसे डाउनलोड करने के बाद भरकर आप सभी दस्तावेज लगायें और नजदीकी लोकमित्र केंद्र, आंगनबाड़ी या सीडीपीओ के दफ्तर में जमा करा सकते हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

••• ग्रामीण भंडार योजना •••

यह सर्वविदित है कि छोटे किसानों की आर्थिक सामर्थ्य इतनी नहीं होती कि वे बाजार में अनुकूल भाव मिलने तक अपनी उपज को अपने पास रख सकें। देश में इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती रही है कि कृषक समुदाय को भंडारण की वैज्ञानिक सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि उपज की हानि और क्षति रोकी जा सके और साथ ही किसानों की ऋण संबंधी जरूरतें पूरी की जा सकें। इससे किसानों को ऐसे समय मजबूरी में अपनी उपज बेचने से रोका जा सकता है जब बाजार में उसके दाम कम हों। ग्रामीण गोदामों का नेटवर्क बनाने से छोटे किसानों की भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इससे वे अपनी उपज उस समय बेच सकेंगे जब उन्हें बाजार में लाभकारी मूल्य मिल रहा हो और किसी प्रकार के दबाव में बिक्री करने से उन्हें बचाया जा सकेगा। इसी बात को ध्यान में रख कर ग्रामीण गोदामों के निर्माण–जीर्णोद्वार के लिए ग्रामीण भंडार योजना नाम का पूंजी निवेश सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किया गया था।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में कृषि उपज और संसाधित कृषि उत्पादों के भंडारण की किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनुषंगी सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माणय कृषि उपज के बाजार मूल्य में सुधार के लिए ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देना वायदा वित्त व्यवस्था और बाजार ऋण सुविधा प्रदान करते हुए फसल कटाई के तत्काल बाद संकट और दबावों के कारण फसल बेचने की किसानों की मजबूरी समाप्त करना कृषि जिन्सों के संदर्भ में राष्ट्रीय गोदाम प्रणाली प्राप्तियों की शुरूआत करते हुए देश में कृषि विपणन ढांचा मजबूत करना शामिल है। इसके जरिए निजी और सहकारी क्षेत्र को देश में भंडारण ढांचे के निर्माण में निवेश के लिए प्रेरित करते हुए कृषि क्षेत्र में लागत कम करने में मदद की जा सकती है।

ग्रामीण गोदाम के निर्माण की परियोजना देशभर में व्यक्तियों, किसानों, कृषक उत्पादक समूहों, प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, कम्पनियों, निगमों, सहकारी संगठनों, परिसंघों और कृषि उपज विपणन समिति द्वारा शुरू की जा सकती है।

स्थान

इस कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमी को इस बात की आजादी है कि वह अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार किसी भी स्थान पर गोदाम का निर्माण कर सकता है। परंतु गोदाम का स्थान नगर निगम क्षेत्र की सीमाओं से बाहर होना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रोन्नत फूड पार्कों में बनाए जाने वाले ग्रामीण गोदाम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

आकार

गोदाम की क्षमता का निर्णय उद्यमी द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गोदाम की क्षमता 100 टन से कम और 30 हजार टन से अधिक नहीं होनी चाहिए। 50 टन क्षमता तक के ग्रामीण गोदाम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष मामले के रूप में सब्सिडी के पात्र हो सकते हैं, जो व्यवहार्यता विश्लेषण पर निर्भर करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में 25 टन क्षमता के आकार वाले ग्रामीण गोदाम भी सब्सिडी के हकदार होंगे।

स्थान आकार और क्षमता को संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता है–लोकेशन, आकार और क्षमता :

गोदाम म्युनिसिपल क्षेत्र की सीमा के बाहर होना चाहिए।	
न्यूनतम क्षमता	50 मैट्रिक टन
अधिकतम क्षमता	10,000 मैट्रिक टन
गोदाम की ऊचाई	4–5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए
गोदाम की क्षमता	1 क्यूबिक मीटर क्षेत्र 0–4 मैट्रिक टन की

गणना का पैमाना

वैज्ञानिक भंडारण के लिए शर्तें

कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित गोदाम इंजीनियरी अपेक्षाओं के अनुरूप ढांचागत दृष्टि से मजबूत होने चाहिए और कार्यात्मक दृष्टि से कृषि उपज के भंडारण के उपयुक्त होने चाहिए। उद्यमी को गोदाम के प्रचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करना पड़ सकता है, बशर्ते राज्य गोदाम अधिनियम या किसी अन्य सम्बद्ध कानून के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई हो। 1000 टन क्षमता या उससे अधिक के ग्रामीण गोदाम केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) से प्रत्यायित होने चाहिए।

वैज्ञानिक भण्डारण हेतु अपनाई जाने वाली पूर्व शर्त को संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता है :

1) सीपीडब्ल्यूडी एसपीडब्ल्यूडी–के विनिदेशानुसार निर्माण
2) कीटाणुओं से सुरक्षा (अस्थाई सीढ़ियों के साथ ऊंचा, पक्का, क्लेटफार्म चूहारोधक व्यवस्था सहित)
3) पक्षियों से सुरक्षा जाली वाली खिड़कियां व रोशनदान
4) प्रभावी धूम्रीकरण फयूमीगेशन के लिए दरवाजों, खिड़कियों की वायु अवरोधकता

गोदाम कॉम्पलेक्स में ये सुविधाएँ होनी चाहिए

- सुगम पक्की सड़क
- पक्की आंतरिक सड़कें
- जल निकासी की समुचित व्यवस्था
- अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था
- सामान लादने उतारने की उचित व्यवस्था

ऋण से सम्बद्ध सहायता

इस कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी संस्थागत ऋण से सम्बद्ध होती है और केवल ऐसी परियोजनाओं के लिए दी जाती है जो वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों, कृषि विकास वित्त निगमों, शहरी सहकारी बैंकों आदि से वित्त पोषित की गई हों।

कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी गोदाम के प्रचालन के लिए कार्यात्मक दृष्टि से अनुषंगी सुविधाओं जैसे चाहर दिवारी, भीतरी सड़क, प्लेटफार्म, आतरिक जल निकासी प्रणाली के निर्माण, धर्मकांटा लगाने, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, वेयरहाउसिंग सुविधाओं सहित गोदाम के निर्माण की पूंजी लागत पर दी जाती है।

वायदा ऋण सुविधा

इन गोदामों में अपनी उपज रखने वाले किसानों को उपज गिरवी रख कर वायदा ऋण प्राप्त करने का पात्र समझा जाएगा। वायदा ऋणों के नियम एवं शर्तों, ब्याज दर, गिरवी रखने की अवधि, राशि आदि का निर्धारण रिजर्व बैंक नाबार्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य बैंकिंग पद्धतियों के अनुसार किया जाएगा।

बीमा

गोदाम के बीमे की जिम्मेवारी गोदाम के मालिक की होगी।

सब्सिडी की दरें इस प्रकार होंगी :–

क) उद्यमियों और इन समुदायों से सम्बद्ध सहकारी संगठनों तथा पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के मामले में परियोजना की पूंजी लागत का एक तिहाई (33.33 प्रतिशत) सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये होगी

ख) किसानों की सभी श्रेणियों, कृषि स्नातकों और सहकारी संगठनों से सम्बद्ध परियोजना की पूंजी लागत का 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 2.25 करोड़ रुपये होगी।

ग) अन्य सभी श्रेणियों के व्यक्तियों, कंपनियों और निगमों आदि को परियोजना की पूंजी लागत का 15 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा1.35 करोड़ रुपये होगी।

घ) एनसीडीसी की सहायता से किए जा रहे सहकारी संगठनों के गोदामों के जीर्णोद्धार की परियोजना लागत का 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी के प्रयोजन के लिए परियोजना की पूंजी लागत की गणना इस प्रकार की जाएगी :–

क) 1000 टन क्षमता तक के गोदामों के लिए वित्त प्रदाता बैंक द्वारा मूल्यांकित परियोजना लागत या वास्तविक लागत या रुपये 3500 प्रति टन भंडारण क्षमता की दर से आने वाली लागत, इनमें जो भी कम हो।

ख) 1000 टन से अधिक क्षमता वाले गोदामों के लिए :– बैंक द्वारा मूल्यांकित परियोजना लागत या वास्तविक लागत या रुपये 1500 प्रति टन की दर से आने वाली लागत, इनमें जो भी कम हो।

वाणिज्यिक–सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में सब्सिडी नाबार्ड के जरिए जारी की जाएगी। यह राशि वित्तप्रदाता बैंक के सब्सिडी रिजर्व निधि खाते में रखी जाएगी और कर से मुक्त होगी।

किसानों को ग्रामीण भंडार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

हवाई जहाज में दोनों पायलटों को नहीं दिया जाता एक जैसा खाना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधुओं ने साल 1903 में किया था और आसमान की ऊंचाईयों को छुआ था। हालांकि कुछ-कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राइट बंधुओं से आठ साल पहले यानी साल 1895 में मुंबई के रहने वाले शिवकर बापूजी तलपड़े ये कारनामा कर चुके थे, लेकिन उनकी उपलब्धि इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हवाई यात्रा के दौरान लोग ज्यादा गैस छोड़ते हैं। इसलिए हवाई जहाज में दुर्गंध को कम करने के लिए चारकोल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। हवाई सफर के दौरान हमारा खाने का स्वाद बदल जाता है, क्योंकि एयरलाइंस में दिए गए खानों में ज्यादा नमक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन विमान में दबाव ज्यादा होने की वजह से हमें स्वाद में इसका पता नहीं चलता है। हवाई जहाज में इमरजेंसी (आपातकाल) के समय जो ऑक्सीजन मास्क यात्रियों को दिए जाते हैं, उसके सहारे यात्री सिर्फ 15 मिनट ही जिंदा रह सकते हैं। साल 1953 से पहले हवाई जहाज की खिड़कियों के कोने चौकोर होते थे, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से बाद में खिड़कियों को गोल बनाया जाने लगा, क्योंकि गोल किनारे हवा का ज्यादा विरोध नहीं करते और इससे विमान पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। कहा जाता है साल 1987 में अमेरिका के एक व्यक्ति ने एक एयरलाइन को 69 लाख रुपये हवाई जहाज का आजीवन पास बनवा लिया था, जिसकी बदौलत 2008 तक उसने 10 हजार से ज्यादा बार विमान का सफर किया। इससे कंपनी को एक अरब 42 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसके बाद कंपनी ने उस व्यक्ति का पास रद्द कर दिया। हवाई जहाज में पायलट और को-पायलट को अलग-अलग तरह का खाना दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि दोनों पायलट एक जैसा खाना खाकर बीमार न हो जाएं। मान लीजिए जो खाना पायलट को दिया जाता है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो एक जैसा खाना खाकर दोनों के दोनों पायलट बीमार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति विमान में बैठे यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकती है।

दिन में होता है शव का पोस्टमॉर्टम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पोस्टमॉर्टम एक प्रकार का ऑपरेशन होता है, जिसमें शव का परीक्षण किया जाता है। शव का परीक्षण इसलिए किया जाता है, ताकि व्यक्ति की मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। पोस्टमॉर्टम के लिए मृतक के सगे-संबंधियों की सहमति अनिवार्य होती है। हालांकि कुछ मामलों में पुलिस अधिकारी भी पोस्टमॉर्टम की इजाजत दे देते हैं, जैसे की हत्या। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्यक्ति की मौत के बाद छह से 10 घंटे के अंदर ही पोस्टमॉर्टम किया जाता है, क्योंकि इससे अधिक समय होने के बाद शवों में प्राकृतिक परिवर्तन, जैसे कि ऐंठन होने लगते हैं। शवों का पोस्टमॉर्टम करने का समय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का ही होता है। इसके पीछे वजह ये है कि रात में ट्यूबलाइट या एलईडी की कृत्रिम रोशनी में चोट का रंग लाल के बजाए बैंगनी दिखाई देता है और फॉरेंसिक साइंस में बैंगनी रंग की चोट का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। रात में पोस्टमॉर्टम नहीं कराने के पीछे एक धार्मिक कारण भी बताया जाता है। चूंकि कई धर्मों में रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, इसलिए कई लोग मृतक का पोस्टमॉर्टम रात को नहीं करवाते हैं।

आखिर जेसीबी मशीन पीले रंग की ही क्यों होती है

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जेसीबी मशीन तो आपने देखी ही होगी। इसका इस्तेमाल दुनिया में लगभग हर जगह होता है। आमतौर पर जेसीबी का काम खुदाई का होता है। कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर भी जेसीबी की खुदाई खूब वायरल हुई थी। जेसीबी ब्रिटेन की मशीन बनाने वाली एक कंपनी है, जिसका मुख्यालय इंग्लैंड के स्टैफर्डशायर शहर में है। इसके प्लांट दुनिया के चार महाद्वीपों में हैं। जेसीबी दुनिया की पहली ऐसी मशीन है, जो बिना नाम के साल 1945 में लॉन्च हुई थी। इसको बनाने वाले ने बहुत दिनों तक इसके नाम को लेकर सोच-विचार किया, लेकिन कोई अच्छा सा नाम न मिलने के कारण इसका नाम इसके आविष्कारक जोसेफ सायरिल बमफोर्ड के नाम पर ही रख दिया गया। जेसीबी दुनिया की पहली ऐसी मशीन है, जो बिना नाम के साल 1945 में लॉन्च हुई थी। इसको बनाने वाले ने बहुत दिनों तक इसके नाम को लेकर सोच-विचार किया, लेकिन कोई अच्छा सा नाम न मिलने के कारण इसका नाम इसके आविष्कारक जोसेफ सायरिल बमफोर्ड के नाम पर ही रख दिया गया। जेसीबी पहली ऐसी निजी ब्रिटिश कंपनी थी, जिसने भारत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। आज के समय में जेसीबी मशीन का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात भारत में ही किया जाता है। साल 1945 में जोसेफ सायरिल बमफोर्ड ने सबसे पहली मशीन एक टीपिंग ट्रेलर (सामान ढोने वाला ट्रेलर) बनायी थी, जो उस वक्त बाजार में 45 पौंड यानी आज के हिसाब से करीब 4000 रुपये में बिकी थी। दुनिया का पहला और सबसे तेज रफ्तार ट्रैक्टर फास्ट्रैक जेसीबी कंपनी ने ही साल 1991 में बनायी था। इस ट्रैक्टर की अधिकतम रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस ट्रैक्टर को प्रिंस ऑफ वेल्स पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। शुरुआत में जेसीबी मशीनें सफेद और लाल रंग की बनती थीं, लेकिन बाद में इनका रंग पीला कर दिया गया। दरअसल, इसके पीछे तर्क ये है कि इस रंग के कारण जेसीबी खुदाई वाली जगह पर आसानी से दिख जाती है, चाहे दिन हो या रात। इससे लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि आगे खुदाई का काम चल रहा है।

दवाइयों के पत्तों पर खास है लाल रंग की पट्टी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अक्सर जब लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाने के बजाए सीधे मेडिकल स्टोर पर चले जाते हैं और बिना कुछ सोचे – समझे उस बीमारी की दवाइयां खरीद लेते हैं। इससे कभी-कभी तो बीमारी ठीक भी हो जाती है, लेकिन कई बार उसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो शायद आपको पता हो कि दवाइयों के पत्तों पर लाल रंग की एक पट्टी बनी होती है। दरअसल, दवाइयों के पत्तों पर बनी लाल रंग की पट्टी का मतलब होता है कि डॉक्टर के पर्चे के बिना उस दवाई को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही डॉक्टर की सलाह के बिना उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल रोकने के लिए ही दवाइयों पर लाल रंग की पट्टी लगाई जाती है। लाल रंग की पट्टी के अलावा दवाइयों के पत्तों पर और भी कई काम की चीजें लिखी होती हैं, जिनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। कुछ दवाइयों के पत्तों पर Rx लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि उस दवाई को सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। दवाइयों के जिन पत्तों पर NRx लिखा होता है, उसका मतलब होता है कि उस दवाई को लेने की सलाह सिर्फ वहीं डॉक्टर दे सकते हैं, जिन्हें नशीली दवाओं का लाइसेंस प्राप्त है। कुछ दवाइयों के पत्तों पर XRx भी लिखा होता है और इसका मतलब होता है कि उस दवाई को सिर्फ डॉक्टर के पास से ही लिया जा सकता है। इस दवा को डॉक्टर सीधे मरीज को दे सकता है। मरीज इसे किसी मेडिकल स्टोर से नही खरीद सकता है, भले ही उसके पास डॉक्टर द्वारा लिखी पर्ची ही क्यों न हो।

उत्तरी अमेरिका में चली थी सबसे पहली स्कूल बस

द रीव टाइम्स ब्यूरो

स्कूल बस का उपयोग सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में 19वीं सदी में किया गया था। चूंकि उस समय मोटर गाड़ियां नहीं होती थीं, इसलिए स्कूल से दूर रह रहे छात्रों को लाने और ले जाने के लिए घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में स्कूल की गाड़ियों के रूप में घोड़ा गाड़ी की जगह मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल होने लगा, जो लकड़ी और धातु की बनी होती थीं और उनपर नारंगी या पीला रंग चढ़ाया जाता था, ताकि वो दूसरी मोटर गाड़ियों से अलग पहचानी जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूल बसों को आधिकारिक रूप से पीले रंग से रंगने की शुरुआत साल 1939 में उत्तरी अमेरिका में ही हुई थी। भारत, अमेरिका और कनाडा सहित दुनिया के कई देशों में भी स्कूल की बसें पीले रंग की ही होती हैं। अब यह रंग इन गाड़ियों की पहचान बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्कूली बसों को लेकर कई दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसके अनुसार निजी स्कूल बसों का रंग भी पीला ही होना चाहिए। इसके अलावा स्कूल बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए और अगर स्कूल बस किराये की है तो उस पर भी स्कूल बस ड्यूटी लिखा होना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा-निर्देश में ये भी कहा था कि स्कूल बसों में फर्स्ट एड बॉक्स (प्राथमिक उपचार पेटी) का होना जरूरी है। इसके अलावा बस की खिड़कियों के बीच में ग्रिल लगी होनी चाहिए और स्कूल से जुड़ी सभी जानकारियां बस में उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही स्कूल बसों में एक अटेंडेंट का होना आवश्यक है और स्कूल बस की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। नियम के अनुसार, अगर बच्चे 12 साल से छोटे हैं तो स्कूल बसों में 1.5 ज्यादा बच्चों को बैठाया जा सकता है और अगर बच्चा 12 साल से अधिक उम्र का है तो उसे पूरी एक सीट दी जानी चाहिए। बसों के पीले रंग को लेकर साल 1930 में अमेरिका में हुए एक शोध में इस बात की पुष्टि हुई थी कि पीला रंग

बाकी रंगों की तुलना में आंखों को सबसे जल्दी दिखाई देता है और बाकी रंगों के बीच आदमी का ध्यान सबसे पहले पीले रंग पर ही जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, बाकी रंगों की तुलना में पीले रंग में 1.24 गुना ज्यादा आकर्षण होता है।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

द रीव टाइम्स संस्थापक: डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस सायबू निवास समीप सेक्टर -2, बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित
प्रधान सम्पादक: डा. एल.सी. शर्मा
फोन न. 0177 2640761, मेल: editor@themissionriev.com
Title Code : HPBIL00313
RNI Reference No. 1328500

आवश्यक सूचना

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।

द रीव टाइम्स
दूरभाष : 9418404334
Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

द रीव टाइम्स आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिलों, गांव, स्वास्थ्य, कानून, समसामयिक विषयों पर संपादकीय एवं अभिव्यक्ति, सामान्य ज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं का ज्ञान दर्पण, सरकारी जनपयोगी योजनाओं का संपूर्ण दस्तावेज़......द रीव टाइम्स उत्कृष्ट गुणवत्ता, संपूर्ण रंगीन पृष्ठ, शानदार विषयवस्तु के साथ प्रदेश का पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स अब आपको मिलेगा घर-द्वार पर ही। समाचार पत्र को लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट http://sub.missionriev.in पर लॉगइन कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मिशन रीव के कार्यकर्ता/अधिकारी से संपर्क कर भी आप कैशलैस भुगतान कर इसके वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। अब आपके लिए आकर्षक ऑफर.....

अब वार्षिक सदस्य बनें केवल 500/रुपये, छः माह के लिए 250/रुपये में और घर बैठे पाएं द रीव टाइम्स.....क्योंकि आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़